



भारतीय डाक के 150 वर्ष
150 YEARS OF INDIA POST

भारतीय डाक विभाग
Department of Posts, India



भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भारत के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयानिधि मारन और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. शकील अहमद डाक विभाग के 150 वर्षों की सेवा के उपलक्ष्य में दिनांक 04 अक्टूबर, 2004 को सीरी फोर्ट सभागार, नई दिल्ली में आयोजित किए गए उद्घाटन समारोह में।

Hon'ble President of India Dr. APJ Abdul Kalam, Prime Minister of India Dr. Manmohan Singh, along with Minister of Communications & IT Shri Dayanidhi Maran and Minister of State for Communications & IT Dr. Shakeel Ahmad, at the inaugural function marking 150 Years of service by the Department of Posts, at Siri Fort Auditorium, New Delhi on 4th October, 2004.



श्री आर. गणेशन, सचिव, डाक विभाग और अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड।

Shri R. Ganesan, Secretary, Department of Posts, and Chairman, Postal Services Board.



वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2004-2005

भारतीय डाक विभाग
(संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय)
भारत

DEPARTMENT OF POSTS
(MINISTRY OF COMMUNICATIONS
AND INFORMATION TECHNOLOGY)
INDIA

विषय सूची

भाग I

वार्षिक रिपोर्ट

पृष्ठ सं०

विभाग की संकल्पना

अध्याय 1	पुनरीक्षा	1
अध्याय 2	संगठन	5
अध्याय 3	डाक प्रचालन	11
अध्याय 4	फिलैटली	19
अध्याय 5	व्यवसाय विकास कार्यकलाप	23
अध्याय 6	अंतर्राष्ट्रीय संबंध	31
अध्याय 7	प्रौद्योगिकी	39
अध्याय 8	वित्तीय सेवाएं	43
अध्याय 9	वित्तीय प्रबंधन	49
अध्याय 10	मानव संसाधन विकास	59
अध्याय 11	सतर्कता कार्यकलाप	63
अध्याय 12	महिलाओं से संबंधित मुद्दे	65
अध्याय 13	अन्य कार्यकलाप	67
अध्याय 14	पूर्वोत्तर में विकासात्मक कार्यकलाप	75

भाग II

कार्यकलाप

83

(अप्रैल-दिसम्बर, 2004)

CONTENTS
PART 1
ANNUAL REPORT

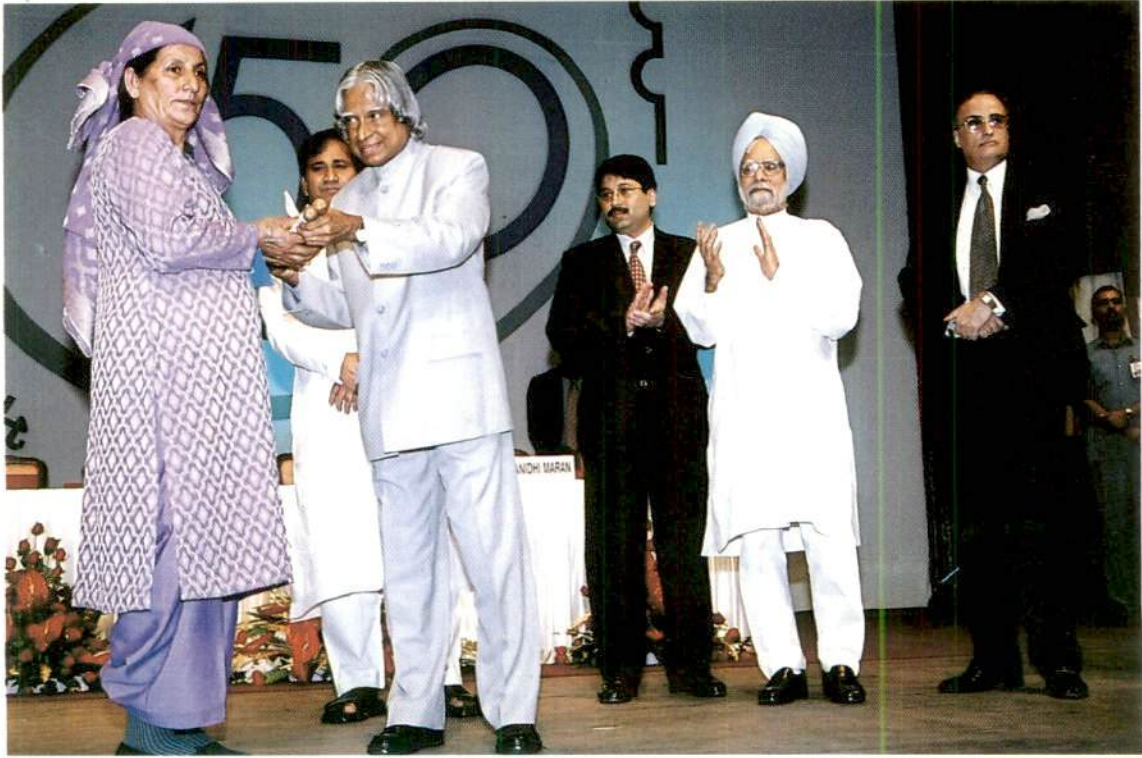
Page No.

Vision of the Department

Chapter 1	Overview	2
Chapter 2	Organisation	6
Chapter 3	Postal Operations	12
Chapter 4	Philately	20
Chapter 5	Business Development Activities	24
Chapter 6	International Relations	32
Chapter 7	Technology	40
Chapter 8	Financial Services	44
Chapter 9	Financial Management	50
Chapter 10	Human Resource Development	60
Chapter 11	Vigilance Activities	64
Chapter 12	Gender Issues	66
Chapter 13	Other Activities	68
Chapter 14	Development Activities in North East	76

PART II

Activities (April-December 2004)	84
--	----



श्रीमती सांदला देवी, विधवा-स्व. श्री बहादुर सिंह, समूह 'घ' कर्मचारी, नालागढ़ डाकघर (हिमाचल प्रदेश) अपने पति को मरणोपरांत दिए गए मेघदूत पुरस्कार को भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम से ग्रहण करते हुए।

Smt. Sandla Devi, widow of Late Shri Bahadur Singh, Group-D official of Nalagarh Post Office (Himachal Pradesh), receiving Meghdoot Award given posthumously to her husband, from the Hon'ble President of India Dr. APJ Abdul Kalam.



डाक प्रशिक्षण केन्द्र, मैसूर (कर्नाटक) में साफ्टवेयर विकास केन्द्र।

Software Development Centre at Postal Training Centre, Mysore (Karnataka).

विभाग की संकल्पना

“भारतीय डाक सामाजिक रूप से प्रतिबद्ध,
प्रौद्योगिकी परिचालित,
व्यावसायिक दृष्टि से संचालित तथा
प्रगतिशील संगठन होगा”

VISION OF THE DEPARTMENT

*“India Post will be a socially
committed, technology driven,
professionally managed &
forward looking Organisation”*

अध्याय 1

पुनरीक्षा

विभाग के उद्देश्य

1.1 डाक विभाग सभी लोगों को सस्ती कीमतों पर देश में बुनियादी डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके उद्देश्य हैं :-

- जनजातीय, पहाड़ी तथा दूर-दराज के इलाकों सहित देश के सभी भागों में बुनियादी डाक सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित करना।
- कार्य-कुशल, विश्वसनीय और किफायती सेवा प्रदान करना।
- बाजार की अपेक्षाओं के अनुरूप मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करना।
- बढ़ते कार्य की मात्रा को कुशलता से निपटाने के लिए सेवाओं का आधुनिकीकरण और इस प्रकार ग्राहक एवं कर्मचारी संतुष्टि में वृद्धि करना।
- एक प्रगतिशील संगठन बनना; और
- अधिक संसाधन जुटाना तथा वित्तीय कार्य-निष्पादन में सुधार लाना।

दायित्व, चुनौतियां और कार्य-नीतियां

1.2 विश्वभर में डाकघर की भूमिका में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मेल और नई प्रौद्योगिकियां पारंपरिक डाक कार्यकलापों की पूरक बन रही हैं। हर कहीं, डाकघर प्रत्येक देश की सामाजिक, आर्थिक जरूरतों के अनुरूप अनेक जनोपयोगी एवं नई वित्तीय सेवाएं प्रदान करके निरंतर नए व्यवसाय अपना रहा है जिससे उसकी विक्रय क्षमता बढ़ने में मदद मिली है। साथ-ही-साथ डाकघर प्रौद्योगिकी की शुरुआत करके पारंपरिक सेवाओं को उन्नत बना रहा है, तथा प्राइवेट कूरियर उद्योग से बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं संचार प्रौद्योगिकी में हो रहे निरंतर विकास को ध्यान में रखते हुए ग्राहकों को त्वरित, अधिक विश्वसनीय और अधिक उत्तरदायी सेवा प्रदान करने की चुनौती का सामना करने के लिए नए उत्पाद और सेवाएं शुरू कर रहा है।

1.3 जहां तक समूचे देश में, भू-भाग को ध्यान में रखे बिना, सस्ती कीमतों पर बुनियादी डाक सेवाएं प्रदान करने का संबंध है, भारतीय डाक सरकार के सार्वभौमिक सेवा दायित्व को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्ध है। इस अपेक्षा को पूरा करने के लिए इसने 31-3-2004 तक 1,55,669 डाकघरों का नेटवर्क स्थापित किया है जिनमें से 1,27,119 शाखा डाकघर हैं जो पूरी तरह ग्रामीण इलाकों की जरूरतों को पूरा करते हैं। इन डाकघरों के जरिए यह देश में कहीं भी प्रत्येक ग्राहक के घर पर डाक का दैनिक वितरण, लैटर बॉक्सों के जरिए पत्रों का संग्रहण, तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण पोस्टमैन के माध्यम से ग्राहकों के घर पर ही डाक-टिकटों और डाक-स्टेशनरी की बिक्री सुनिश्चित करता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर ग्राहकों को अनेक बुनियादी डाक सेवाएं प्रदान करते हैं जिनमें बैंकिंग और बीमा सेवाएं भी शामिल हैं। शहरी क्षेत्रों के सभी डाकघरों, तथा ग्रामीण क्षेत्रों के चुने हुए डाकघरों के माध्यम से बिल संग्रहण सुविधा प्रदान की जा रही है जबकि शहरी क्षेत्रों में चुने हुए डाकघरों में कतिपय मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

1.4 देश में कहीं भी संचार के सस्ते साधन प्रदान के अलावा भारतीय डाक वाणिज्य, उद्योग, सरकार तथा सांस्थानिक निकायों जैसे समाज के विशिष्ट खण्डों की उभरती जरूरतों को भी पूरा करती है जो त्वरित और मूल्यवर्धित सेवाओं की मांग करते हैं। इसके फलस्वरूप, इन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ग्राहकों के अनुकूल अनेक उत्पादों और सेवाओं तथा प्रौद्योगिकी की शुरुआत करके डाक प्रचालन कार्यों का आधुनिकीकरण करने की जरूरत हुई। ग्राहक की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए समय की दृष्टि से संवेदनशील डाक की विभिन्न श्रेणियों की प्रोसेसिंग को प्राथमिकता देना भी आवश्यक हो गया। हाल के वर्षों में भारतीय डाक द्वारा प्रदान की गई मूल्यवर्धित सेवाओं में स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, बधाई डाक, डाटा पोस्ट, स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा, बिल मेल पोस्ट, ई-पोस्ट और ई-बिल पोस्ट सेवाएं शामिल हैं। वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में, जो नई सेवाएं शुरू की गई हैं, उनमें इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विसेज, वारंट पेमेंट, म्यूच्युअल फण्डों और बॉण्ड्स आदि की बिक्री की सुविधाएं शामिल हैं।

Chapter 1

OVERVIEW

Objectives of the Department

1.1 Department of Posts is committed to providing universal access to basic postal services in the country at affordable prices. Its objectives are to :-

- ensure availability of basic postal services in all parts of the country, including tribal, hilly and remote areas.
- provide efficient, reliable and economic service.
- provide value-added services according to market requirements.
- modernize the services to handle the growing volume of work with efficiency and thereby enhance customer and employee satisfaction.
- be a forward-looking organization, and
- generate more resources and improve financial performance.

Responsibilities, Challenges and Strategies

1.2 The role of the Post Office is undergoing transformation the world over, as electronic mail and new technologies supplement traditional postal activities. Everywhere, the Post Office is increasingly adopting new businesses that help to optimise its retailing strength, by providing a range of public utilities and new financial services that are relevant to the socio-economic needs of each country. It is also simultaneously upgrading traditional services through induction of technology, and introducing new products and services in order to meet the challenges of providing faster, more reliable, and more responsive service to the customer in the face of increasing competition from the private courier industry and continuing advances in communication technology.

1.3 India Post is committed to fulfilling the government's Universal Service Obligation in terms of providing basic postal services throughout the country, irrespective of terrain, at an affordable price. For meeting this requirement it has set up a network of 1,55,669 Post Offices as on 31.3.2004 of which 1,27,119 are Branch Post Offices catering exclusively to the rural areas. Through these offices it ensures daily delivery of dak at the doorstep of every customer any where in the country, collection of letters through Letter Boxes, and also sale of Stamps and stationery through village postmen at the doorstep of customers in rural areas. Post Offices in urban and rural areas provide a range of basic postal services to the customers, including banking and insurance services. Bill collection facilities are being extended through all Post Offices in urban areas, and identified Post Offices in rural areas, while certain value added services are being provided in selected offices in urban areas.

1.4 Besides providing access to affordable means of communication anywhere in the country, India Post also meets the emerging needs of specific segments of society like commerce, industry, Government and institutional bodies, who demand quicker, value added services. This has resulted in the need to customise a number of products and services to meet these requirements and modernise postal operations through induction of technology. It has also become necessary to prioritise the processing of different categories of mail according to time sensitivity to meet customer expectations. The value added postal services offered by India Post in recent years include Speed Post, Business Post, Express Parcel Post, Greetings Post, Data Post, Speed Post, Passport Service, Bill Mail Post, e-Post and e-Bill Post. In the area of financial services, new services introduced include facilities for International Money Transfer, Electronic Fund Transfer, Electronic Clearance Services, Warrant Payment, Sale of Mutual Funds and Bonds etc.

1.5 डाक नेटवर्क की पहुंच, एक सुसज्जित लेखांकन प्रणाली और देश के दूर-दराज के इलाकों में भी स्थानीय परिस्थितियों की अंतरंग जानकारी डाक नेटवर्क की क्षमता है जिन्हें स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर ग्राहकों को और अधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए और आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रौद्योगिकी की शुरुआत ने फिजिकल नेटवर्क की क्षमता को उन्नत बनाकर इसे सुविधाजनक बनाया है। प्रशिक्षण, बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में अग्रणी सेवा प्रदाताओं के साथ नीतिपरक सहयोग से कर्मचारियों की कार्यकुशलता और क्षमता में सुधार करने के प्रयास किए गए हैं, तथा एजेंसी आधार पर अधिक से अधिक समनुरूप उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना, इस समय भारतीय डाक की उस पहल में शामिल हैं जिस पर वह अपने सामने उभरती हुई चुनौतियों को पूरा करने तथा उभरते हुए सामाजिक-आर्थिक वातावरण में संचार एवं विकास की सुविधा प्रदान करने की अपनी भूमिका को पूरा करने के लिए ध्यान केन्द्रित कर रहा है।

1.6 ग्राहक को किफायती और व्यवहार्य सेवाएं प्रदान करने की चुनौती भी एक निरंतर चिंता का विषय है। वर्ष 2003-04 के दौरान 56,321.52 मिलियन रु. के कुल कार्यकारी-व्यय की तुलना में कुल राजस्व 42,569.29 मिलियन रु. था। इस प्रकार 13,752.23 मिलियन रुपए का अंतर रहा। डाक राजस्व में वृद्धि 6.17 प्रतिशत थी। जबकि, पिछले वर्ष के बजट घाटे की तुलना में 0.79 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई।

1.7 हालांकि, भारतीय डाक का ध्यान शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में अपनी डाक और वितरण सेवाओं में सुधार करने की ओर निरंतर केन्द्रित रहेगा, लेकिन निकट भविष्य में वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। सेवाओं की गुणवत्ता और कार्यकुशलता

में सुधार लाने के लिए प्रौद्योगिकी की शुरुआत एक प्रमुख नीति के रूप में बनी रहेगी। भारतीय डाक 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान अब सभी प्रधान डाकघरों तथा बड़े उप-डाकघरों में अपने कार्यों का कम्प्यूटरीकरण करने की ओर अग्रसर है। इस तरह, वर्ष 2003-04 में 26 प्रधान डाकघरों, 3 सर्किल कार्यालयों, निदेशक लेखा के 19 कार्यालयों तथा 31 क्षेत्रीय कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया। दसवीं योजना के अंत तक, भारतीय डाक की अपने सभी 842 प्रधान डाकघरों और लगभग 8,000 प्रमुख उप-डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण करने तथा इन डाकघरों को जोड़ने के लिए एक वास्तविक प्राइवेट नेटवर्क सृजित करने की योजना है। इसके अलावा, भारतीय डाक का उद्देश्य सेवाओं की विविधता को समेकित एवं समाकलित करने के लिए एक एंटरप्राइज डाटा वेयरहाउस (डाटा सेंटर) स्थापित करने का भी है। इससे भारतीय डाक सामने आ रही चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नेटवर्क के अनुकूल सेवाएं शुरू करने तथा मौजूदा सेवाओं में खूबियां शामिल करने में समर्थ हो सकेगी। डिजिटल अंतर को पूरा करने और देश के दूर-दराज के इलाकों में जहां कम्प्यूटर नहीं हैं, उन स्थानों को ई-मेल सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए देश भर में "ई-पोस्ट" नामक एक नई सेवा शुरू की गई है जिसमें ई-मेल सुविधा जैसे प्रौद्योगिकीय विकास के लाभ को घर-घर वितरण जैसी पारंपरिक सुविधाओं के साथ जोड़ा गया है।

1.8 इस प्रकार भारतीय डाक का जनता की जरूरतों और आकांक्षाओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनने के लिए अपनी परंपरागत क्षमताओं को आधुनिक प्रबंधन पद्धतियों और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों में बदलने हेतु निरंतर प्रयासरत रहने तथा मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के लिए नए अवसरों की पहचान करते हुए सेवाओं को अधिक ग्राहकोनुकूल बनाने तथा किफायती ढंग से डाक सेवाओं का अधिक से अधिक विस्तार करने का प्रस्ताव है।



1.5 The outreach of the network, a well established accounting system and intimate knowledge of local conditions even in the remotest corners of the country are the strength of the postal network, which are being further tapped to provide more and more services to customers, depending on local needs. Induction of technology is facilitating this objective by upgrading the capacity of the physical network. Efforts to improve the skills and capabilities of employees through training, strategic collaborations with leading service providers in banking and insurance sectors, and provision of more and more homogeneous products and services on agency basis are among the initiatives that India Post is currently focussing on to meet the emerging challenges before it and to fulfill its role as a facilitator of communication and development in the emerging socio-economic environment.

1.6 The challenge of providing cost effective and viable services to the customer is also a matter of constant concern. The total revenue during 2003-04 was Rs. 42,569.29 Million against net working expenses of Rs. 56,321.52 Million, leaving a gap of Rs.13,752.23 Million. The increase in postal revenues was to the extent of 6.17%. While there was a slight increase in the budgetary deficit of 0.79% over the previous year.

1.7 While the focus of India Post will continue to be on improving its mail and delivery services in both urban and rural areas, efforts will also be made to achieve financial self-sufficiency in the immediate future. Induction of technology will continue to be one

of the main strategies for improving the quality and efficiency of services. India Post is now on the move to computerize its operations in all the Head Post Offices and large Sub-Post Offices during the 10th Five Year Plan(2002-07). Thus the year 2003-04 witnessed computerization of 26 Head Post Offices, 3 Circle Offices, 19 Offices of Director of Accounts and 31 Regional Offices. India Post is planning to computerize all its 842 Head Post Offices and around 8,000 major Sub-Post Offices and create a virtual private network linking these Offices by the end of 10th Plan. Further, India Post also aims to set-up an Enterprise Data Warehouse(Data Centre) to consolidate and integrate the multitude of services. This will enable India Post to introduce new network – enabled services and add value to the existing services to meet the challenges ahead. A new service “e-post” has been launched countrywide combining the benefits of technological advances like the e-mail facility with traditional facilities like door-to-door delivery, to bridge the digital divide and extend the advantages of e-mail facilities even to those who do not possess computers in the remotest corners of the country.

1.8 Thus, India Post proposes to continue its efforts to harness its traditional strengths to modern management practices and appropriate technologies to become more responsive to public needs and expectations, and to make the services more customer friendly, while identifying new opportunities to provide value added services and greater access to postal services, in a cost effective manner.

अध्याय 2

संगठन

2.1 डाक विभाग संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक विभाग है। यह विभाग श्री दयानिधि मारन, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अधीन काम कर रहा है। डॉ. शकील अहमद संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। श्री आर. गणेशन, सचिव, डाक विभाग के साथ-साथ महानिदेशक, भारतीय डाक और अध्यक्ष, डाक सेवा बोर्ड हैं।

मुख्यालय में योजना एवं नीति संबंधी कार्य

2.2 डाक सेवा बोर्ड इस विभाग का शीर्ष प्रबंध निकाय है। इसमें अध्यक्ष और तीन सदस्य हैं। बोर्ड के तीन सदस्यों के पास प्रचालन, विकास तथा कार्मिक के प्रकार्यात्मक विभाग हैं। विभाग के संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार इस बोर्ड के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। सचिव, डाक सेवा बोर्ड द्वारा बोर्ड को सहयोग प्रदान किया जाता है। मुख्यालय में उप महानिदेशक, निदेशक तथा सहायक महानिदेशक बोर्ड को आवश्यक सहयोग देते हैं।

संगठनात्मक परिवर्तन

2.3 प्रौद्योगिकी की शुरुआत के कारण सामने आई चुनौतियों के प्रत्युत्तर के रूप में हाल में डाक विभाग के संगठनात्मक स्वरूप का पुनर्गठन किया जा रहा है। कार्यात्मक पुनर्गठन इस प्रकार किया गया है ताकि उच्च प्रबंधन की समन्वय एवं मॉनीटरिंग की भूमिका को यथोचित महत्व देते हुए परिवर्तन की संक्रमणकालीन कठिनाइयों से निपटा जा सके। प्रबंधन की सहायता के लिए परम्परागत पिरामिडीय प्रणाली को डैस्क प्रणाली में बदलने के लिए कदम उठाए गए हैं। इन सुधारों की शुरुआत एक उत्तरदायी, संवेदनशील एवं कार्यकुशल प्रबंधन स्थापित करने के लिए जरूरी सक्रियता के साथ इस प्रणाली को उत्प्रेरक बनाने के लिए की गई है।

डाक सर्किल

2.4 डाक सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरे देश को 22 डाक सर्किलों में बांटा गया है। प्रत्येक सर्किल राज्य का को-टर्मिनस

होता है। लेकिन पूर्वोत्तर सर्किल जिसमें छह पूर्वोत्तर राज्य, महाराष्ट्र सर्किल जिसमें गोवा राज्य, पश्चिम बंगाल सर्किल जिसमें सिक्किम तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र, केरल सर्किल जिसमें लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र और पंजाब जिसमें चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र शामिल है, इसके अपवाद हैं। प्रत्येक सर्किल प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/ मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के अधीन है। प्रत्येक सर्किल को परिक्षेत्रों में बांटा गया है जिसमें फील्ड यूनिटें होती हैं, जिन्हें डिवीजन (डाक/रेल डाक सेवा डिवीजन) कहा जाता है। प्रत्येक परिक्षेत्र पोस्टमास्टर जनरल के अधीन है जो उस क्षेत्र का डाक प्रबंधक होता है। सर्किलों और परिक्षेत्रों में कार्यसंचालन में सहयोग देने के लिए स्टैम्प डिपो, डाक भंडार डिपो तथा मेल मोटर सेवा जैसी अन्य संभार यूनिटें भी होती हैं।

सेना डाक सेवा

2.5 इन 22 सर्किलों के अलावा, सशस्त्र सेनाओं की संचार संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक बेस सर्किल भी है। बेस सर्किल अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा के अधीन है। सेना डाक सेवा के अधिकारी संवर्ग में भारतीय डाक सेवा से प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी होते हैं। सेना डाक सेवा के अन्य रैंकों के लिए भी 75 प्रतिशत कार्मिक डाक विभाग से लिए जाते हैं और शेष कार्मिक सेना द्वारा भर्ती किए जाते हैं।

प्रचालन यूनिट

2.6 देश भर में डाकघरों को मुख्य, उप तथा शाखा डाकघरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ग्रामीण डाक सेवा डाकघर, ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। उप डाकघर विभागीय डाकघर हैं जो ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में हैं। प्रधान डाकघरों को उनके कार्यभार तथा कर्मचारियों की संख्या के अनुसार पांच श्रेणियों में विभक्त किया गया है, इनमें से सबसे बड़े डाकघर मुंबई और कोलकाता के जनरल पोस्ट ऑफिस (जी.पी.ओ.) हैं और उनके बाद अहमदाबाद, बेंगलूर, चेन्नई, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ स्थित जी.पी.ओ. आते हैं।

Chapter 2

ORGANISATION

2.1 Department of Posts under the Ministry of Communications and Information Technology has Shri Dayanidhi Maran as Minister-in-charge with Dr. Shakeel Ahmad as Minister of State. Shri R. Ganesan is Secretary, Department of Posts, Director General, India Post & Chairman, Postal Services Board.

Planning and Policy Functioning at Headquarters

2.2 The Postal Services Board, is the apex management body of the Department, comprising the Chairman and three Members. The three members of the Board hold functional portfolios of Operations, Development and Personnel. The Joint Secretary and Financial Adviser to the Department is a permanent invitee to the Board. The Board is assisted by the Secretary, Postal Services Board. Deputy Directors General, Directors and Assistant Directors General provide necessary support to the Board at the Headquarters.

Organisational changes

2.3 The organisational set up of the Department has been undergoing restructuring in recent times as a response to the challenges faced due to induction of technology. The functional restructuring is designed to tackle the transitional problems of change giving due importance to the coordinating and monitoring role of the higher management. Steps have been taken to substitute the traditional pyramidal system with a desk system to support the management. These reforms were introduced to infuse the system with dynamism needed to create a responsive, sensitive & efficient management.

Postal Circles

2.4 For providing postal services, the whole country has been divided into 22 Postal Circles. Each circle is

co-terminus with a State except the North Eastern Circle which comprises six North Eastern States, Maharashtra Circle which includes Goa, West Bengal Circle includes Sikkim and the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands, Kerala Circle includes the Union Territory of Lakshadweep and Punjab Circle includes the Union Territory of Chandigarh. A Principal Chief Postmaster General/Chief Postmaster General heads each Circle. Each circle is divided into Regions comprising groups of field units, called Divisions (Postal/RMS Divisions). Each Region is headed by a Postmaster General who is the Postal Manager of the area. In the Circles and Regions there are other functional supporting logistical units like Stamp Depots, Store Depots and Mail Motor Service.

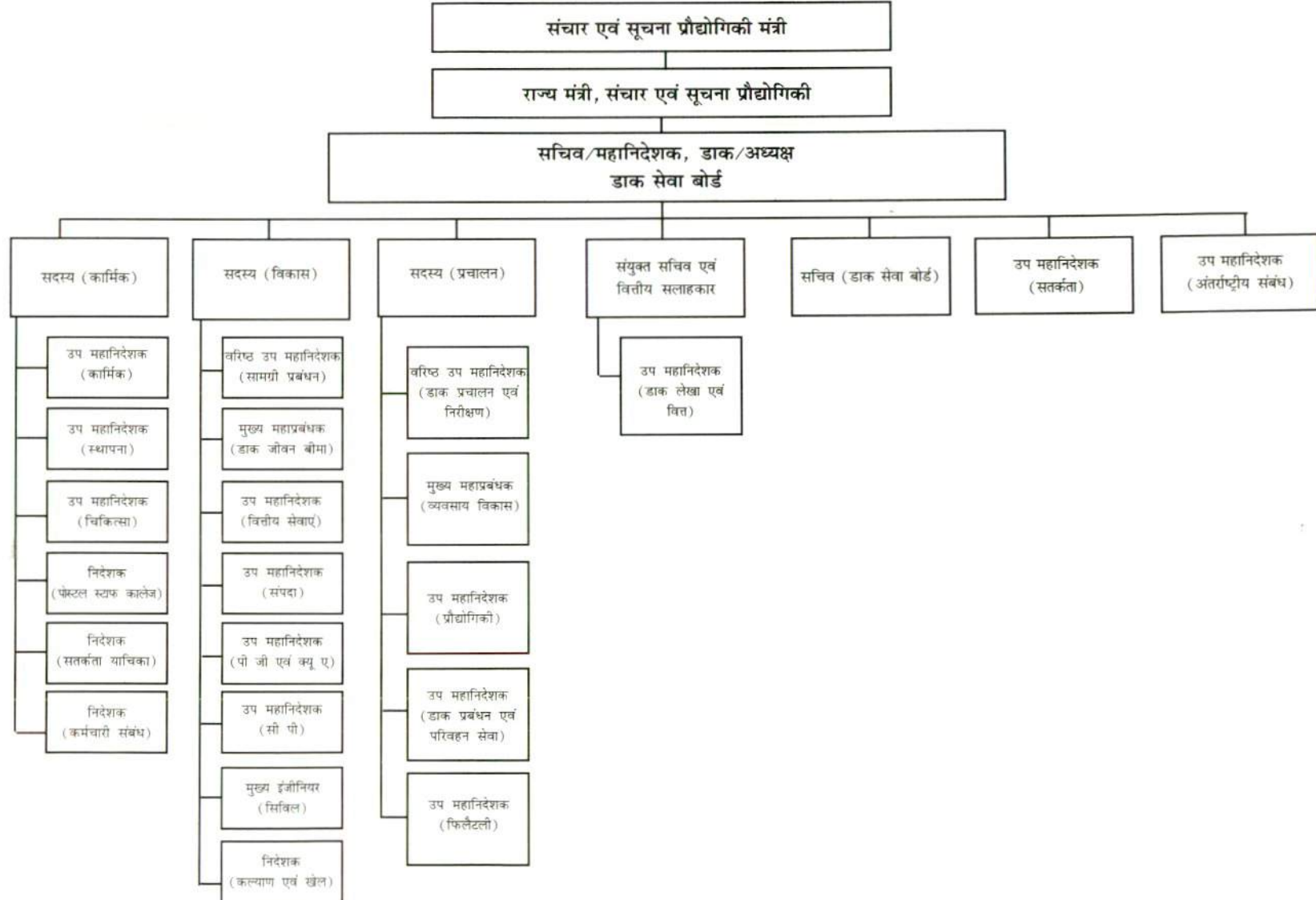
Army Postal Services

2.5 Over and above these 22 Circles, the communication needs of the armed forces are catered to by the Base Circle. Base Circle is headed by the Additional Director General, Army Postal Service. The officer cadre of Army Postal Services is drawn on deputation from the Indian Postal Service. 75 per cent of the other ranks of the Army Postal Service are drawn from the Department of Posts and the remaining personnel are recruited by the Army.

Operational Units

2.6 Post Offices in the country are categorized as Head, Sub and Branch Post Office. Gramin Dak Sewa Post Offices are located in rural areas. The Sub Post Offices are departmental offices located in both rural and urban areas. Head Post Offices are graded into five categories according to their workload and staff strength, the largest being the General Post Offices at Mumbai and Kolkata, followed by GPOs at Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Kanpur and Lucknow.

डाक विभाग का संगठनात्मक चार्ट

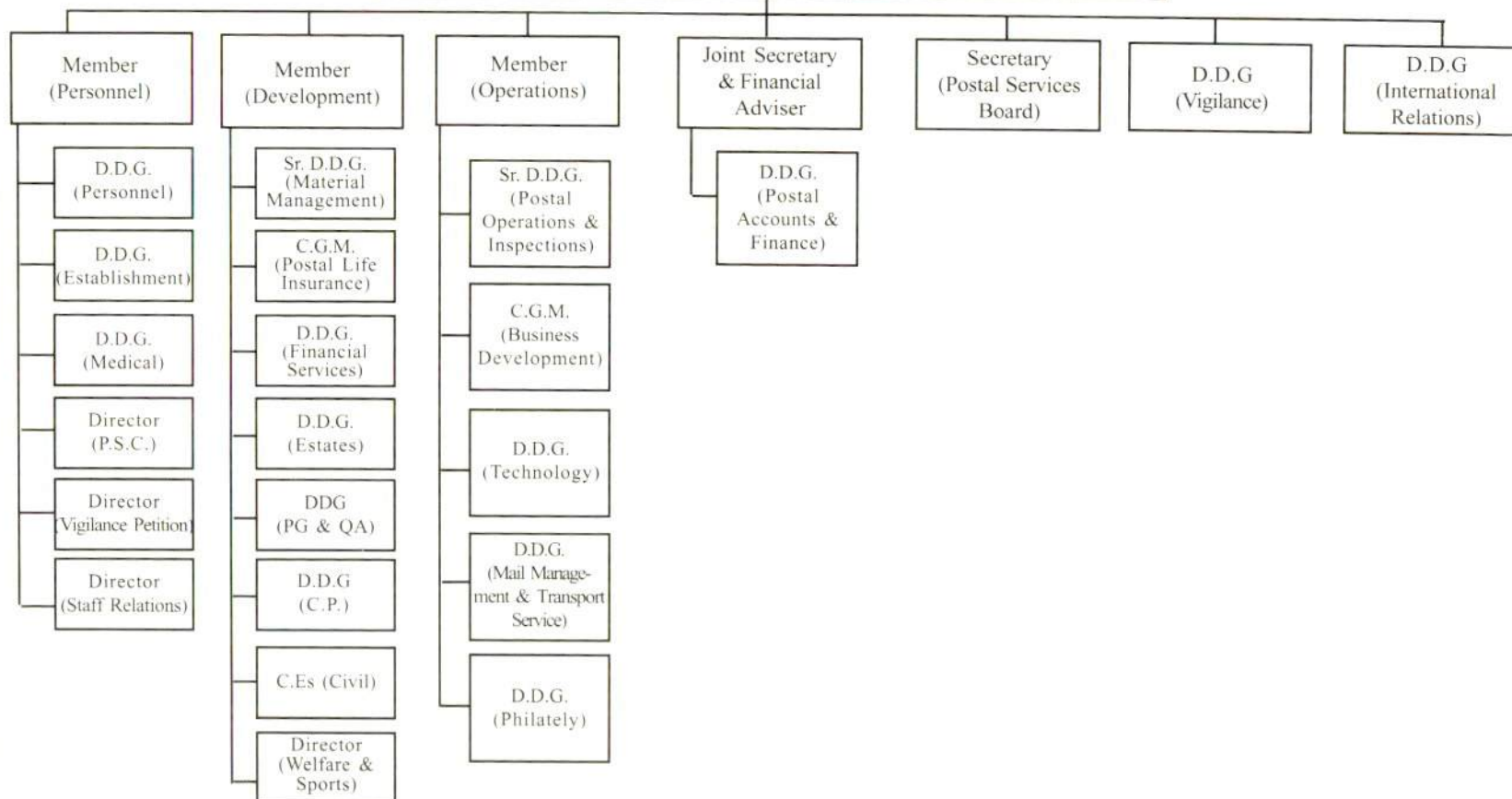


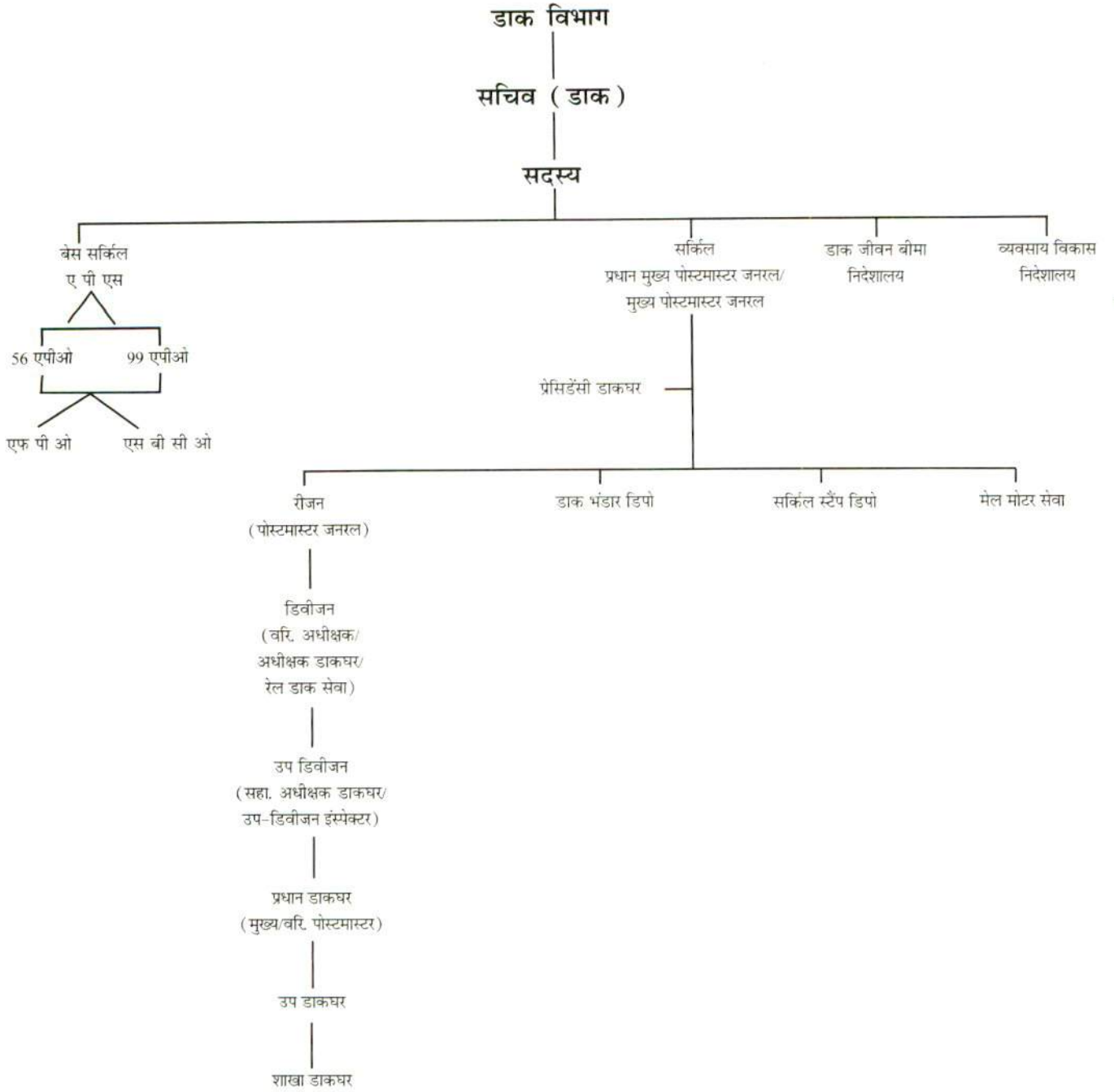
ORGANISATION CHART OF THE DEPARTMENT OF POSTS

**MINISTER OF COMMUNICATIONS &
INFORMATION TECHNOLOGY**

**MINISTER OF STATE
FOR COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY**

**SECRETARY/DIRECTOR GENERAL, POSTS/CHAIRMAN,
POSTAL SERVICES BOARD**

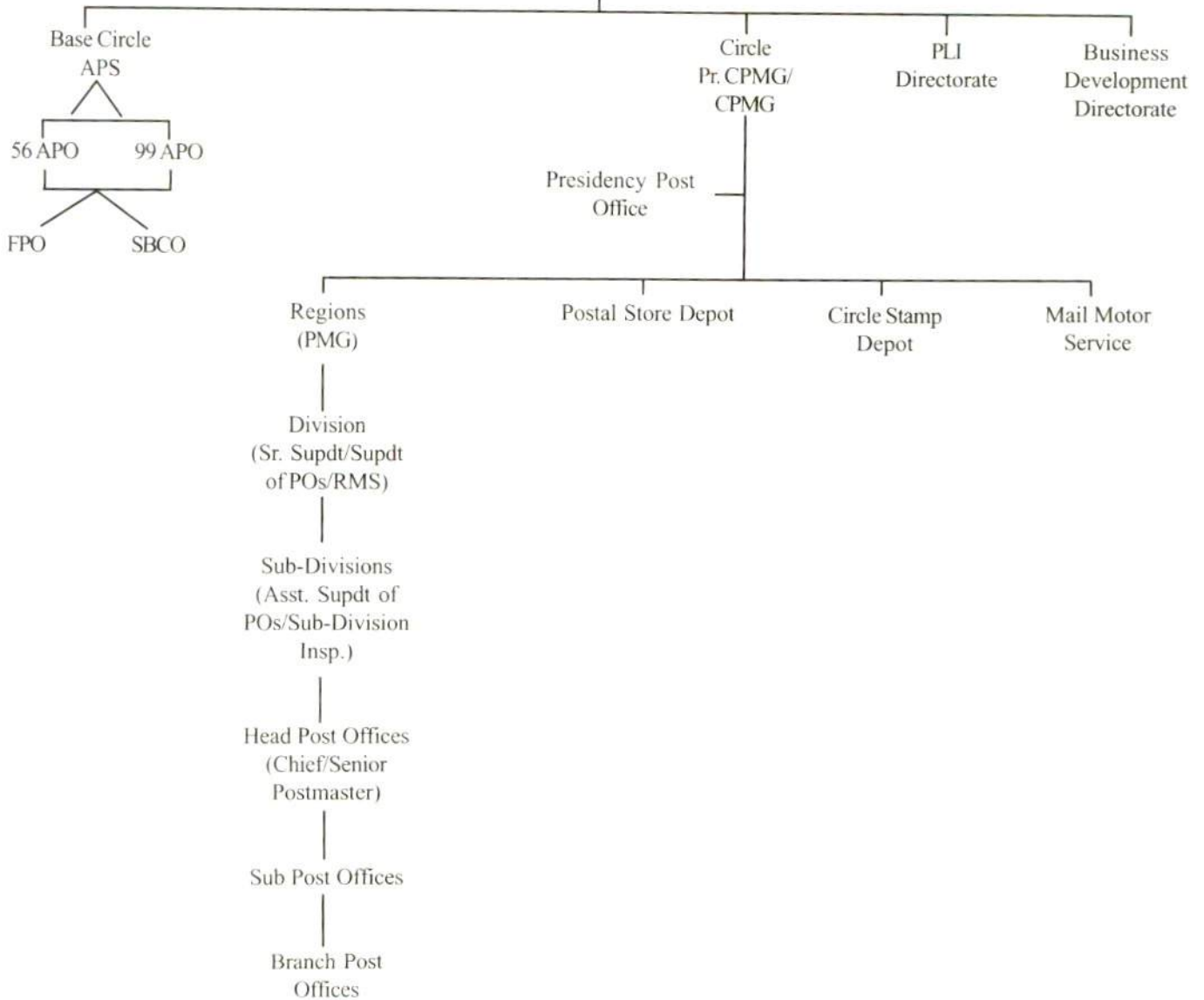




DEPARTMENT OF POSTS

SECRETARY (POSTS)

MEMBERS



अध्याय 3

डाक प्रचालन

डाक नेटवर्क

3.1 भारत का विश्व में 1,55,669 डाकघरों के साथ सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है जिसमें से 89% ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय 23,344 डाकघर थे जो मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में थे। इस प्रकार पिछले पांच दशकों में नेटवर्क में 7 गुना वृद्धि हुई है और यह विस्तार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ है। औसतन एक डाकघर 21.09 वर्ग कि.मी. के क्षेत्र तथा 6,585 की जनसंख्या को सेवा प्रदान करता है।

3.2 देश के डाक नेटवर्क का विस्तार मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त विभागीय डाकघरों को खोलकर किया गया। अतिरिक्त विभागीय डाकघर अंशकालिक आधार पर कार्य करते हैं जिसमें कार्य अवधि न्यूनतम तीन घंटे और अधिकतम 5 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्हें अंशकालिक स्थानीय कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है जिन्हें प्रदत्त सेवा के लिए भत्ता दिया जाता है। दूसरी ओर विभागीय डाकघर आठ घंटे की अवधि के लिए कार्य करता है तथा उन्हें पूर्णकालिक विभागीय कर्मचारियों द्वारा चलाया जाता है।

3.3 डाक नेटवर्क के विस्तार के लिए डाकघर खोलने के लक्ष्य वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत शुरुआत से रखे गए हैं। योजना सहयोग नए डाकघर खोलने की आवृत्ति एवं अनावृत्ति लागतों के लिए भी उस योजना अवधि में उपलब्ध था जिसमें वे खोले गए थे। डाकघरों को दूरी जनसंख्या तथा आय मानदंडों के आधार पर जिन्हें इस प्रयोजन हेतु निर्धारित किया गया है, खोला जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए सभी डाकघरों को रियायत दी जाती है तथा यह सामान्य ग्रामीण क्षेत्रों में 66% से पहाड़ी, जनजातीय, रेगिस्तानी तथा दूर-दूरस्थ में 85% तक दी जाती है। तथापि, शहरी क्षेत्रों में डाकघरों को कोई रियायत प्रदान नहीं की जाती क्योंकि उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो तथा प्रथम वर्ष के पश्चात अपनी लागत से 5% अधिक अर्जित करें।

3.4 नेटवर्क के विस्तार की रणनीति में हाल के वर्षों में कुछ परिवर्तन हुए हैं जिसमें विभाग के घाटे को कम करने में ध्यान दिया गया है जिसमें 40% से अधिक नेटवर्क में दी जाने वाली रियायत के

कारण है। परियोजना हेतु योजना सहयोग योजना लक्ष्यों में कमी के फलस्वरूप कम हो गया है। योजना के अंतर्गत वित्तीय सहयोग भी पर्याप्त रूप से कम हुआ है, अब योजना धनराशि प्रत्येक डाकघर खोलने पर केवल एक समय के अनावृत्ति व्यय के लिए उपलब्ध कराई जाती है। कोई डाकघर खोलने के लिए आवश्यक मैनपॉवर को भी मौजूदा संसाधनों को पुनःव्यवस्थित करके पूरा किया जा रहा है। इसी प्रकार जनवरी 2003 से सर्किल अध्यक्षों को एक दूसरे के निकट अवस्थित एक या दो कर्मचारी वाले डाकघरों को पुनः व्यवस्थित करने का अधिकार दिया गया है। अर्थात् न्यूनतम निर्धारित दूरी से कम उन क्षेत्रों में जिन्हें डाकघर सुविधाओं की आवश्यकता है। इससे विभाग को योजना के अंतर्गत दिए गए अल्प लक्ष्यों की अनुपूर्ति करने, आवश्यक क्षेत्रों में उभरती आवश्यकताएं पूरी करने तथा साथ-साथ नेटवर्क का औचित्यीकरण करने में, जैसा कि दसवीं योजना नीति के अंतर्गत आवश्यक है, सहायता मिली है। भविष्य में योजना के अंतर्गत जरूरतमंद और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा, जहां सेवाओं की कमी है।

3.5 मितव्ययी तरीकों से डाक सुविधाएं उपलब्ध कराने के तरीकों की पहचान हेतु भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। लाइसेंसशुदा स्टैम्प वेंडर स्कीम, लाइसेंसशुदा पोस्टल एजेंट्स स्कीम तथा पंचायत संचार सेवा केन्द्र कुछ ऐसे कदम हैं जो इस संबंध में उठाए गए हैं। अब तक 7,697 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले गए हैं जिनमें 10वीं योजना के अंतर्गत खोले गए 2,371 पंचायत संचार सेवा केन्द्र सम्मिलित हैं। चूंकि, इन स्कीमों का आकलन उनकी पुनःसंरचना की आवश्यकता दर्शाता है, चालू वर्ष में पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने के लिए कोई लक्ष्य नहीं रखे गए थे।

3.6 नेटवर्क की रिटेलिंग क्षमता का अधिकतम उपयोग करने हेतु भी प्रयत्न किए जा रहे हैं। चालू वर्ष में एक उठाया गया महत्वपूर्ण कदम डाकघरों के माध्यम से गैर-जीवन बीमा उत्पादों की रिटेलिंग करना है। विभाग ने ओरियन्टल बीमा कम्पनी के साथ चयनित गैर-जीवन बीमा उत्पादों के विपणन हेतु उनके कारपोरेट एजेंट के बतौर कार्य करने के लिए एक करार किया है। इस स्कीम को पायलट आधार पर प्रत्येक 7

Chapter 3

POSTAL OPERATIONS

Postal Network

3.1 India has the largest Postal network in the world with 1,55,669 Post Offices of which 89% are in rural areas. At the time of independence, there were 23,344 Post Offices, which were primarily in the urban areas. Thus the network has registered a seven fold growth over the last five decades, the focus of this expansion being in the rural areas. On an average, a post office serves an area of 21.09 sq. km. & population of 6,585.

3.2 Expansion of Postal Network in the country, especially in rural areas, was mainly done by opening Extra Departmental Post Offices. The Extra Departmental Post Office functions on part-time basis for periods not exceeding a minimum of three hours and a maximum of five hours. They are manned by part-time locally recruited employees, who are paid an allowance for the services they render. On the other hand, Departmental Post Offices function for a period of eight hours and are manned by full fledged departmental employees.

3.3 Targets for opening Post Offices for expansion of the Postal Network have been given since inception under Annual Plans. Plan support was also available for the recurring and non-recurring costs of the new Post Offices during the plan period in which they were opened. Post Offices are opened subject to distance, population and income norms fixed for the purpose. Subsidy is also given to all Post Offices opened in the rural area, and it ranges from 66% in normal rural area to 85% in hilly, tribal, desert and remote areas. However, no subsidy is offered to Post Offices in urban areas, as they are expected to be financially self-sufficient and earn five percent more than their cost after the first year.

3.4 The strategy for expansion of the network has undergone some modifications in recent years with increasing focus on reducing the deficit of the Department, over 40% of which is attributed to the

subsidy on the network. Plan support for the scheme has dwindled substantially as a result of reduction of Plan Targets; financial support under Plan has also reduced substantially, with Plan funds being made available only for a one time non-recurring expenditure on opening of every Post Office. The manpower requirements for opening a Post Office are also being met only through redeployment of existing resources. Similarly, since January, 2003 Heads of Circles have been empowered to re-deploy existing single or double handed Post Offices located in close proximity to each other, i.e. at lesser than the minimum prescribed distance, to areas which are in need of Post Office facilities. This has helped the Department to supplement the meager targets given under Plan, to meet the emerging requirement in needy areas, while simultaneously rationalizing the network, as required under the 10th Plan Policy initiatives. Support under Plan in future is proposed to be focused on needy, under served areas like the North-East.

3.5 Efforts are also being made to identify means of providing postal services through more cost effective measures. The Licensed Stamp Vendor Scheme, Licensed Postal Agents Scheme and the Panchayat Sanchar Sewa Yojana (PSSY) were initiatives that were taken up in this regard. So far 7,697 Panchayat Sanchar Sewa Kendras (PSSKs) have been opened, including 2,371 PSSKs under the 10th Plan. Since an assessment of these schemes indicates the need for restructuring them, no targets were given in the current year for opening PSSKs.

3.6 Efforts are also underway to optimize the retailing capacity of the network. One major initiative taken up in the current year is the retailing of non-life insurance products through Post Offices. The Department has entered into an agreement with the Oriental Insurance Company to function as their Corporate Agent for marketing identified non-life products. This Scheme was launched on a pilot basis through select Post Offices in 2 districts each of 7 Circles. It is being gradually expanded, after providing

सर्किलों के 2 जिलों में चयनित डाकघरों के माध्यम से शुरू किया गया। इसका अन्य सर्किलों को आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के पश्चात क्रमिक विस्तार किया जा रहा है।

डाक सेवाएं

3.7 डाकघर में डाक प्रचालनों में अन्य सेवाओं के साथ-साथ निम्नलिखित मूल डाक सेवाओं का समूचा क्षेत्र शामिल है :-

- डाक-टिकट तथा डाक लेखन सामग्री की बिक्री
- पंजीकृत वस्तुओं की बुकिंग
- बीमाकृत वस्तुओं की बुकिंग
- मूल्यदेय वस्तुओं की बुकिंग
- मनीआर्डर और पोस्टल आर्डरों के माध्यम से धन प्रेषण तथा
- पार्सलों की बुकिंग

3.8 परंपरागत रूप से ये सेवाएं मैनुअल काउंटरों पर प्रदान की जा रही थीं। ग्राहकों को प्रौद्योगिकी के लाभ प्रदान करने की अनिवार्य आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अब काउंटर प्रचालनों को उत्तरोत्तर कम्प्यूटरीकृत किया जा रहा है ताकि एक ही खिड़की से अधिकाधिक प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा सकें जिससे सेवाएं अधिक अनुक्रियाशील हों और उनमें गलती की संभावना भी कम हो तथा व्यर्थ के काम से बचा जा सके।

डाकघरों के माध्यम से राजस्व टिकट की बिक्री पर कमीशन

3.9 विभाग ने वित्त मंत्रालय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों से परामर्श के पश्चात यह निर्णय लिया है कि डाकघरों के माध्यम से राजस्व टिकट की बिक्री पर अक्टूबर 2003, अक्टूबर 2004 एवं अक्टूबर 2005 से क्रमशः 3% , 6% और 10% की दर से कमीशन प्रभारित

किया जाएगा। यह कमीशन प्रधान डाकघरों द्वारा राज्य कोषागारों से राजस्व टिकट खरीदते समय अग्रिम में काट लिया जाएगा।

मैनुअलों का संशोधन

3.10 वर्ष के दौरान शाखा कार्यालय नियमावली, डाक मैनुअल खंड-VI (भाग-II) तथा तार संदेश कोड के मैनुअल का अंग्रेजी संस्करण अद्यतन किया गया है तथा मुद्रण के लिए भेजा गया है।

मनीआर्डर सेवा

3.11 पिछले वर्ष के परियात की तुलना में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पारेषित मनीआर्डर के मूल्य तथा मनीआर्डर परियात के तुलनात्मक आंकड़े तालिका-1 में दिए गए हैं।

डाक प्रचालन

3.12 डाक प्रोसेसिंग, पारेषण तथा उनका वितरण विभाग के मुख्य कार्यकलाप हैं। देश की 0.60 मिलियन पत्र-पेटियों से पत्रों को एकत्रित किया जाता है। 466 रेल डाक सेवा (आर एम एस) कार्यालयों के नेटवर्क पर इनकी प्रोसेसिंग की जाती है तथा देश भर में सड़क, रेल तथा वायुयान द्वारा इन्हें प्रेषित किया जाता है।

डाक की मात्रा

3.13 गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2003-2004 के दौरान डाक परियात के तुलनात्मक आंकड़े तालिका-2 में दिए गए हैं।

तालिका -1			
मनीआर्डर परियात तथा मूल्य (मिलियन में)			
	2002-2003	2003-2004	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
1. मनीआर्डर परियात (मिलियन में)	105.0	99.3	(-) 5.43%
2. पारेषित मनीआर्डरों का मूल्य	86500.0	68750.2	(-) 20.52%

डाक प्रबंधन

3.14 देशभर में अत्यधिक प्रभावी और अधिकतम कुशल डाक पारेषण नेटवर्क स्थापित करने की योजनाओं को व्यावहारिक रूप से लागू किया गया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर विभाग ने डाक परियात के विभिन्न भागों का पता लगाया है और प्रत्येक भाग के लिए परियात के निपटान का विशिष्ट तरीका निश्चित किया है। इस प्रकार महानगरों के

बीच की डाक के लिए मैट्रो चैनल राष्ट्रीय राजधानी और राज्यों की राजधानियों के बीच तथा इसके विपरीत के लिए राजधानी, चैनल, स्थानीय डाक के लिए ग्रीन चैनल, थोक डाक के लिए बिजनेस चैनल और समाचार पत्रों तथा आवधिक पत्र-पत्रिकाओं के लिए पत्रिका चैनल जैसे विशिष्ट चैनल बनाए गए हैं।

the requisite training to other Circles.

Postal Services

3.7 Postal operations at the post office encompass the entire gamut of the basic postal services which interalia include:

- (i) Sale of stamps and stationery
- (ii) Booking of registered articles
- (iii) Booking of insured articles
- (iv) Booking of value payable articles
- (v) Remittance of money through money orders and postal orders
- (vi) Booking of Parcels

3.8 Traditionally, these services were being provided at manually operated counters. Considering the vital need for providing the benefit of technology to the customers, the counter operations are now being progressively computerised to provide a greater range of service to the customer from a single window leading to services being more responsive, and error free.

Commission on sale of Revenue Stamps through Post Offices

3.9 The Department in consultation with Ministry of Finance and Representatives of State Governments has decided that Commission @ 3%, 6% and 10% will be charged w.e.f. October, 2003, October, 2004 and October, 2005 respectively for sale of Revenue Stamps through Post Offices. This Commission will

be deducted in advance by the Head Post Offices while purchasing Revenue Stamps from the State Treasuries.

Revision of Manuals

3.10 During the year, the English Version of the Manuals of Branch Office Rules, Postal Manual Volume VI (Part-II) and Telegraph Message Code have been updated and sent for printing.

Money Order Service

3.11 Comparative statistics of Money Order traffic and the value of Money Orders transmitted, compared with the previous year is given in Table 1.

Mail Operations

3.12 Mail processing, transmission and delivery are the core activities of the Department. Mail is collected from 0.60 Million letter boxes in the country. This is processed by a network of 466 Railway Mail Service Offices, and conveyed by road, rail and airlines all over the country.

Mail Volume

3.13 Comparative statistics of mail traffic handled during 2003-2004 as compared to previous year, is given in Table 2

TABLE 1
MONEY ORDER TRAFFIC AND VALUE (in Million)

	2002-2003	2003-2004	Increase/Decrease (in %age)
1. Money Order traffic	105.0	99.3	(-) 5.43%
2. Value of MOs transmitted	86500.0	68750.2	(-) 20.52%

Mail Management

3.14 Plans for achieving an efficient mail transmission network throughout the country have been put into effect. With this objective the Department has identified different segments of mail traffic and devised exclusive handling

for each segment. Thus, there are specialised channels like Metro Channel for mail between metro cities, Rajdhani Channel for mail between the national capital and the state capitals and vice-versa, Green Channel for local mail, Business Channel for bulk mail and Patrika Channel for newspapers and periodicals.

तालिका-2 डाक परियात (मिलियन में)			
	2002-2003	2003-2004	वृद्धि/कमी (प्रतिशत में)
1. पंजीकृत वस्तुएं	222.4	213.6	(-)3.96 %
2. अपंजीकृत वस्तुएं	1565.0	1779.3	(+)13.69%
कुल (1+2)	1787.4	1992.9	(+)11.50%

* आंकड़े राजस्व में मिला दिए गए हैं

3.15 दीपावली, क्रिसमस, रक्षाबंधन तथा नववर्ष जैसे फेस्टिवल सीजन के दौरान डाक की मात्रा में होने वाली आकस्मिक वृद्धि से निपटने के लिए विशेष प्रबंध किए गए। प्रमुख शहरों में, लोगों को उनके पत्र सीधे गंतव्य थैलों में डालने के लिए उचित सुझाव दिया गया जिससे प्रेषितियों को पत्रों का वितरण जल्दी किया जा सके।

डाक प्रचालनों का आधुनिकीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण

3.16 विभाग ने डाक के पारेषण, प्रोसेसिंग तथा वितरण के कार्य में तेजी लाने की दृष्टि से डाक के पारेषण, प्रोसेसिंग तथा वितरण के कम्प्यूटरीकरण तथा आधुनिकीकरण की एक नीति प्रारंभ की है। डाक कार्यालयों के आधुनिकीकरण का उद्देश्य डाक कार्यालयों में बेहतर उपकरण उपलब्ध कराना और बेहतर कार्य के वातावरण का निर्माण करना है जिससे संपूर्ण कार्यकुशलता प्राप्त हो सके।

3.17 लेखादेय मदों जैसे पंजीकृत पत्रों, बीमाकृत मदों आदि की छंटाई को इन मदों के त्वरित निपटान एवं सुरक्षा के उद्देश्य से और शिकायतों/पूछताछ के मामले में अधिक शीघ्रतापूर्वक कार्रवाई करने के लिए कम्प्यूटरीकृत किया गया है।

3.18 वर्ष के दौरान 22 मेल कार्यालयों का आधुनिकीकरण किया गया है जबकि समीक्षाधीन अवधि के अंतर्गत 10 प्रधान रिकॉर्ड कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण किया गया है।

मेल मोटर सेवा (एम एम एस)

3.19 मेल मोटर सेवा विभाग के 1149 मेल मोटर वाहनों और 486 स्टाफ कारों/निरीक्षण वाहनों के रखरखाव, प्रचालन और प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। विभाग के अपने मेल मोटर वाहन 94 स्टेशनों में चलते हैं। इनमें से 17 स्टेशनों पर बड़े मरम्मत कार्य और रखरखाव कार्य करने के लिए पूर्ण विकसित वर्कशाप

सुविधाएं उपलब्ध हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान, विभागीय डाक वाहनों ने डाक प्रेषित करने के लिए 25.98 मिलियन कि.मी. की दूरी तय की। इस अवधि के दौरान एम.एम.एस. पर 481.69 मिलियन रुपये का व्यय हुआ। वर्ष 2003-04 के दौरान औसत लागत प्रति कि.मी. पूर्व वर्ष के दौरान 19.56 रु. की तुलना में 18.54 रु. थी। उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास संबंधी निदेशों को ध्यान में रखते हुए 4 नए वाहन खरीदे गए तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र के दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में इनकी आपूर्ति की गई जहां विश्वसनीय तथा वैकल्पिक साधन उपलब्ध नहीं थे।

सामग्री प्रबंधन

3.20 निदेशालय के सामग्री प्रबंधन डिवीजन को देश भर में डाक नेटवर्क प्रचालन के लिए आवश्यक सामग्री, प्रपत्र और उपकरण उपलब्ध कराने, उनकी मानीटरिंग तथा आपूर्ति कराने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। अनेक प्रकार के डाक थैले, लैटर बाक्स, वर्दी की मदें, कागज तथा अन्य आधारभूत उपकरण या तो सामग्री प्रबंधन डिवीजन द्वारा सीधे प्राप्त और मुहैया कराए जाते हैं अथवा पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय की एजेंसियों के माध्यम से इनकी आपूर्ति की जाती है। तथापि वर्ष के दौरान कई प्रापण कार्य सर्किलों को विकेंद्रित कर दिए गए हैं जैसे वर्दी, छाता, जूट और सूती ट्वाइन, पोस्ट-बाक्स केबिनेट तथा जूते। इसका उद्देश्य निदेशालय में सामग्री प्रबंधन डिवीजन को पूरी तरह से पॉलिसी निर्धारण डेस्क के तौर पर पुनर्गठित करना है। डाकघरों को यह आपूर्ति 46 पोस्टल स्टोर डिपो (पी.एस.डी.) तथा 5 रीजनल फार्म डिपो (आर.एफ.डी.) के माध्यम से की जाती है। ये डिपो उन डाक सर्किलों के अध्यक्षों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं जहां वे स्थित होते हैं। इन डिपुओं के अतिरिक्त भुवनेश्वर में एक डाक मुद्रण प्रेस है।

3.21 आधुनिकीकरण और बेहतर इन-हाउस सुविधाएं प्रदान करने के लिए पी.एस.डी./आर.एफ.डी. को मशीनरी और उपकरण की आपूर्ति की जाती है। प्रभावी सामान सूची (इन्वेंटरी) नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए, विभाग द्वारा 46 डाक भंडार डिपुओं का कम्प्यूटरीकरण भी किया गया है।

TABLE 2
MAIL TRAFFIC (in Million)

	2002-2003	2003-2004	Increase/Decrease (in %age)
1. Registered	222.4	213.6	(-) 3.96%
2. Unregistered *	1565.0	1779.3	(+) 13.69%
TOTAL	1787.4	1992.9	(+) 11.50%

* Figures are adjusted with revenue.

3.15 Special arrangements to meet the sudden spurt in traffic during festival season like Diwali, Christmas, Raksha Bandhan and New Year were made. In major towns, appropriate guidance was provided to the members of the public to post their letters directly into the destination mail-bags to speed up transmission and delivery to the addressees.

Modernisation and Computerisation of Mail Operations

3.16 In order to expedite transmission, processing and delivery of mail, the Department has embarked on a policy of computerisation and modernisation of the mail processing, transmission and delivery in post offices. The modernisation of mail offices aims at providing better equipment and improved work environment in the Mail Offices.

3.17 Sorting of accountable articles like Registered Letters, Insured Articles etc., has been computerised for speedy and safe handling of articles and for more expeditious response in case of enquiries.

3.18 During the year, 22 Mail Offices have been modernised, while 10 Head Record Offices were computerised during the period under review.

Mail Motor Service (MMS)

3.19 The Mail Motor Service is responsible for maintenance, operations and administration of 1149 Mail Motor Vehicles and 486 staff cars/inspection vehicles of the Department. The Department operates its own fleet of mail motor vehicles at 94 stations. Full-fledged workshop facilities for major repairs and maintenance are available at 17 of these stations. During 2003-2004, the MMS Vehicles covered 25.98 Million Kms. for conveyance of mails. A total expenditure of Rs. 481.69 Million was incurred

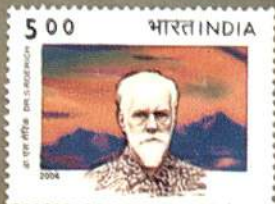
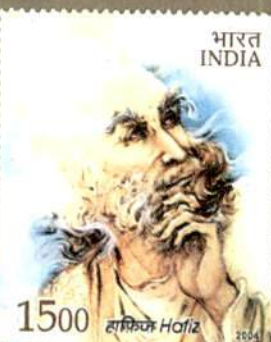
on MMS during this period. During the year 2003-04, the average cost per Km. was Rs. 18.54 as against Rs. 19.56 during the previous year. Keeping in view the directives regarding development of North-Eastern Region, 4 new vehicles were procured and supplied to the remote and backward areas of North-Eastern Region where reliable and alternative means were not available.

Material Management (MM)

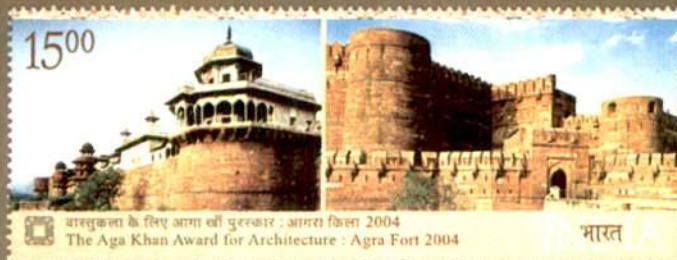
3.20 Material Management (MM) Division of the Directorate is entrusted with the responsibility of procuring monitoring and supplying material, forms, and equipment required for postal network operation throughout the country. A large variety of mail bags, letter boxes, uniform items, paper and other infrastructural equipment is either procured and supplied directly by Material Management Division or through the agencies of the Directorate General of Supply and Disposal. However, during the year many procurement functions have been decentralised to the circles like procurement of uniforms, umbrellas, jute and cotton twine, post box cabinets and footwear. The aim is to restructure the Material Management Division in the Directorate into a purely policy making desk. The supply of stores to post offices is done through 46 Postal Store Depots (PSDs) and 5 Regional Form Depots (RFDs). These Depots work under the administrative control of Heads of Postal Circles in whose jurisdiction they are located. Apart from these Depots, there is a Postal Printing Press at Bhubaneswar.

3.21 As a part of modernisation and for providing better in-house facilities, machinery and equipment are supplied to PSDs/RFDs. In order to ensure effective inventory control computerisation of 46 Postal Store Depots has also been undertaken by the Department.

कुछ विशेष डाक-टिकट



SOME THEMATIC STAMPS



अध्याय 4

फिलैटली

डाक-टिकट

4.1 स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही डाक-टिकटों के माध्यम का उपयोग विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा आर्थिक-सामाजिक विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों को उजागर करने में किया जाता रहा है। पंचवर्षीय योजनाएं, इस्पात संयंत्र, बांध आदि विषयों को डाक-टिकटों के ऊपर स्थान दिया जाता रहा है। बाद में, देश की समृद्ध सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत पर ध्यान केन्द्रित हो गया। कला, वास्तुकला, सामुद्रिक विरासत, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा संबंधी मुद्दों और सिनेमा पर विषयपरक सेटों में अनेकों सुन्दर डाक-टिकट जारी किए गए। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के महान नेताओं को उन पर स्मारक डाक-टिकट जारी करके सम्मानित किया गया जिनमें सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी रहे। उन महापुरुषों पर भी स्मारक डाक-टिकट जारी करके उन्हें सम्मानित किया गया जिन्होंने चित्रकला, साहित्य, संगीत आदि जैसे क्षेत्रों में अपार योगदान दिया है। इस प्रकार, डाक शुल्क प्राप्त होने के मूल प्रयोजन के अलावा डाक-टिकटों को "सांस्कृतिक राजदूत" की भूमिका सौंप दी गई।

4.2 "डाक शुल्क की प्राप्ति" और "सांस्कृतिक राजदूत" के दोहरे स्वरूप को ध्यान में रखकर डाक-टिकटों की दो श्रेणियां सामने आई हैं, नामतः "नियत डाक-टिकट" एवं "स्मारक डाक-टिकट"। नियत डाक-टिकटें डाकघरों में और मेल वस्तुओं पर दिन-प्रति दिन इस्तेमाल करने के निमित्त हैं। इनमें डिजाइन पर अपेक्षाकृत कम बल दिया जाता है। इनके विनिर्माण में न्यूनतम व्यय होता है और ये बड़ी संख्या में मुद्रित किए जाते हैं। दूसरी ओर, स्मारक डाक-टिकटों को अत्यंत सावधानी से डिजाइन एवं मुद्रित किया जाता है। ये अपेक्षाकृत कम संख्या में तैयार किए जाते हैं और ये संग्रहकर्ताओं के मध्य नियत डाक-टिकटों की तुलना में अधिक रुचि जागृत करते हैं।

4.3 विभाग के फिलैटली संबंधी कार्यकलाप निम्नलिखित के अनुसार हैं :-

1. विशेष/स्मारक डाक-टिकटों और अन्य डाक-शुल्क टिकटों/सेवा शुल्क डाक-टिकटों को डिजाइन करना, उनका मुद्रण एवं वितरण।

2. डाक स्टेशनरी की वस्तुएं जैसे लिफाफे, अंतर्देशीय पत्र-कार्ड, पोस्टकार्ड, हवाई पत्र, पंजीकृत लिफाफे आदि।

3. फिलैटली का अनुवीक्षण एवं प्रचार-प्रसार/देश के भीतर फिलैटली प्रदर्शनियों का आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय तथा विश्व प्रदर्शनियों में भाग लेना।

4. राष्ट्रीय डाक-टिकट संग्रहालय, डाक भवन की देखरेख करना।

फिलैटली-नीति

4.4 स्मारक डाक-टिकटों के वार्षिक विमोचन कार्यक्रम के बारे में सरकार को परामर्श देने के लिए फिलैटली सलाहकार समिति का गठन किया गया है। विभाग को डाक-टिकट जारी करने के लिए सांसदों, विधायकों, राज्य सरकारों और अन्य सरकारी संगठनों, निजी संगठनों तथा व्यक्ति विशेषों से प्रति वर्ष बड़ी संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। समिति विनिर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर इन प्रस्तावों की जांच-पड़ताल करती है और भारत की विरासत/भारत का प्राकृतिक जगत/अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं और राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महापुरुषों जैसे विषयों के संदर्भ में मार्गदर्शी सिद्धांतों के विनिर्धारणों को ध्यान में रखकर वार्षिक डाक-टिकट विमोचन कार्यक्रम की सिफारिश करती है। फिलैटली सलाहकार समिति फिलैटली और इसके प्रचार-प्रसार से संबंधित नीतिगत मुद्दों की भी जांच-पड़ताल करती है। यह समिति डाक तथा आर्थिक कार्य विभागों के सरकारी सदस्यों तथा माननीय संसद सदस्यों, प्रख्यात फिलैटलीविदों और कला, संग्रहालय-विद्या, डिजाइन, फोटोग्राफी और पत्रकारिता जैसे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रसिद्ध व्यक्तियों से मिलकर बनी होती है। विभाग फिलैटली सलाहकार समिति की सिफारिशों और प्रतिभूति मुद्रणालय की क्षमता को ध्यान में रखकर स्मारक डाक-टिकटों का वार्षिक कैलेंडर तैयार करता है।

Chapter 4

PHILATELY

The Postage Stamp

4.1 Since independence, the medium of postage stamps has been used to highlight the country's achievements in various spheres, including science and technology and socio-economic development. Themes like the Five-Year Plans, Steel Plants, Dams etc. have been the subject of stamps over the years. Subsequently, the focus shifted to the country's rich cultural and natural heritage. Many beautiful stamps were issued in thematic sets on Art, Architecture, Maritime Heritage, Science and Technology, Defence and Cinema. Great leaders of National and International stature were honoured with commemorative stamps, the most prominent being Mahatma Gandhi, the Father of the Nation. Personalities who made immense contribution in areas like painting, literature, music etc. were also honoured with commemorative stamps. Thus postage stamps were assigned the role of "Cultural Ambassadors", apart from their original purpose of being receipts of postage.

4.2 In keeping with its dual character of "Receipts of Postage" and "Cultural Ambassadors", two categories of stamps have emerged, viz. the "Definitive Postage Stamps" and the "Commemorative Postage Stamps". The former are meant for day-to-day use at post offices and on mail articles. They incorporate less design inputs, with minimum expenditure in their manufacture and are printed in large quantities. The latter, on the other hand, are designed and printed with special care. They are manufactured in smaller quantities and generate more interest among stamp collectors than definitive stamps.

4.3 The philatelic activities of India Post include:-

1. Designing, printing and distribution of special/commemorative postage stamps and other postage stamps/ service postage stamps.

2. Items of postal stationery like Envelope, Inland Letter Card, Postcard, Aerogram and Registered Cover etc.
3. Monitoring and promotion of Philately/conduct of philatelic exhibitions within the country, participation in international and world exhibitions
4. Management of the National Philatelic Museum, Dak Bhavan.

Policy on Philately

4.4 A Philatelic Advisory Committee (PAC) has been constituted to advice the Government on the annual programme for issue of commemorative stamps. Every year, the Department receives a large number of proposals for issue of stamps from MPs, MLAs, State Governments, other organisations in the public and private sectors and also from individuals. The Committee examines these proposals on the basis of specific guidelines, and recommends an annual stamp issue programme, taking into account the guidelines regarding themes relating to Heritage India/ Nature India/ international events, and personalities of national and international importance. The PAC also examines policy issues related to philately and its promotion. The Committee comprises official members from the Departments of Posts and Economic Affairs, and non-official members drawn from among Hon'ble Members of Parliament, noted philatelists and eminent personalities from various walks of life like art, museology, archaeology, design, photography and journalism. An annual calendar focussing on Commemorative Postage Stamps is then drawn up keeping in view the recommendations of the PAC and the capacity of the security printing presses.

फिलैटली का प्रचार-प्रसार

4.5 डाक विभाग ने ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए आदि जैसे अन्य कई देशों के अनुभव के अनुरूप फिलैटली को अग्रणी राजस्व अर्जन क्षेत्र समझा है। गत कुछेक वर्षों के दौरान विभाग ने फिलैटली के प्रचार-प्रसार तथा उन्नति के लिए कई उपाय किए हैं :

- योजना गतिविधियों के बतौर देश के विभिन्न भागों में जिला स्तर पर फिलैटलिक प्रदर्शनियां आयोजित करना।
- फिलैटलिक ब्यूरो, जो ग्राहकों से सम्पर्क कायम करने के स्थान हैं, का प्रौद्योगिकीय एवं सौन्दर्यपरक उन्नयन।
- अधिकारियों एवं कर्मचारियों को गहन प्रशिक्षण
- फिलैटली के बारे में जागरूकता लाने के लिए बाजार सर्वेक्षण/प्रचार कार्यक्रम।
- स्कूली बच्चों के मध्य वार्षिक डाक-टिकट डिजाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रायः, इसका आयोजन डाक सप्ताह समारोहों के दौरान किया जाता है। डाक-टिकट डिजाइन प्रतियोगिता की पुरस्कार प्राप्त प्रविष्टियों में से एक का वर्ष 1999 से प्रति वर्ष बाल दिवस डाक-टिकट को डिजाइन करने में उपयोग किया जाता है।

पंजीकृत ग्राहक

4.6 फिलैटली का प्रचार-प्रसार करने के गंभीर प्रयासों के परिणामस्वरूप देश के भिन्न-भिन्न भागों में इस शौक की लोकप्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह प्रोत्साहनजनक नतीजा है क्योंकि इस शौक से जनसाधारण को शिक्षा, मन-बहलाव तथा चरित्र-निर्माण के रूप में बहुत कुछ हासिल होता है। विभाग में पंजीकृत ग्राहकों की जो संख्या 1999-2000 में 23,905 थी, वह 2003-2004 में बढ़कर 82,593 हो गई। विभाग द्वारा हाल ही में कराए गए एक स्वतंत्र अध्ययन के मुताबिक देश में कुल 4 मिलियन डाक-टिकट संग्रहकर्ताओं के होने का अनुमान है।

डाक-टिकट एवं स्टेशनरी

4.7 वर्ष 2003-2004 के दौरान पैसठ (65) स्मारक/विशेष डाक-

टिकट जारी किए गए हैं। फिलैटली सलाहकार समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुरूप व्यक्तित्व आधारित डाक-टिकटों को इनकी फिलैटली संगतता सुनिश्चित करने हेतु विषयपरक सेटों में निकाला जा रहा है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभाग ने पुणे में डाक-टिकटों के दो सेट जारी किए जिनके शीर्षक थे- अतीत के सुनहले स्वर (चार डाक-टिकट का सेट), ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता: मलयालम (तीन डाक-टिकट का सेट) तथा लोक संगीत (दो डाक-टिकटों का सेट)। इस अवधि के दौरान कला एवं संस्कृति, वन्य एवं पशु जीवन, विरासत, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इत्यादि पर कई सुन्दर डाक-टिकट जारी किए गए जिसमें भारत-फ्रांस संबंधों पर संयुक्त रूप से जारी दो डाक-टिकटों का सेट, भारत एवं कोरिया गणतंत्र के बीच राजनयिक संबंधों की 30वीं वर्षगांठ पर दो डाक-टिकटों का सेट और भारत की औषधीय वनस्पति, मंदिर वास्तुकला, भारत के जल प्रपात, भारत के मैंग्रोव, ग्रीटिंग तथा भारतीय सांप, प्रत्येक पर चार डाक-टिकटों का सेट जारी किया गया।

4.8 वर्ष के दौरान डाक स्टेशनरी वस्तुएं जैसे पोस्टकार्ड, लिफाफे, पंजीकृत लिफाफे, अंतर्देशीय पत्र कार्ड और हवाई पत्रों पर विज्ञापन, जन जागृति उद्घरण, संदेश आदि अंग्रेजी और हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में जारी किए गए।

4.9 फिलैटलिक मदों का विक्रय पूरे देश में 65 फिलैटलिक ब्यूरो तथा 900 फिलैटलिक काउन्टरों के माध्यम से किया जाता है जिसमें देश के सभी प्रधान डाकघर तथा मुख्य डाकघर सम्मिलित हैं।

4.10 जुलाई 2003 के दौरान डाक-टिकट लोकप्रियता मतदान, 2003 पूरे देश में आयोजित किया गया।

4.11 14 नवम्बर, 2003 को देशभर में सर्किलवार डाक-टिकट डिजाइन प्रतियोगिता, 2003 का आयोजन किया गया।

फिलैटली प्रदर्शनी

4.12 फिलैटली को एक शौक के बतौर स्थापित करने तथा संग्रहकर्ताओं एवं जनता में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रदर्शनियां महत्वपूर्ण हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान देश के विभिन्न डाक सर्किलों में 20 प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

Promotion of Philately

4.5 Philately has been taken up as a priority revenue generation area, in line with the experience of a number of other countries such as Britain, France, USA, etc. Various measures initiated to promote and develop philately during the last few years include the following:-

- Holding of District Level Exhibitions across the country as part of Plan activities.
- Technological and aesthetic upgradation of philatelic bureaux, which are the points of customer interaction.
- Extensive training of officers and staff.
- Market survey/publicity exercises to generate awareness about philately.
- An Annual Stamp Design Competition for school children. Since 1999, the prize-winning entries from the Stamp Design Competition, which is usually held during Postal Week Celebrations, are being used each year, for designing the Children's Day stamp.

Registered Customers

4.6 Due to the Department's concerted efforts to promote Philately, there has been a tremendous increase in the popularity of the hobby in different parts of the country. This is a heartening development, since the hobby offers many rewards to the public, in the form of education, relaxation and character-formation. The number of registered customers with the Department, which stood at 23,905 in 1999-2000, has increased to 82,593 by 2003-2004. The total number of stamp collectors in the country is estimated to be four Million, according to a recently commissioned independent study.

Stamps and Stationery

4.7 During 2003-04 sixty five (65) commemorative

/ special postage stamps have been issued. In accordance with the decision taken by the Philatelic Advisory Committee, personality based stamps are being brought out in thematic sets, to ensure the philatelic relevance of these stamps. During the year under report the Department released sets of stamps titled – “Golden Voices of Yester Years” (set of four stamps), “Jnanpith Award Winners : Malyalam” (set of three stamps) and “Folk Music” (set of two stamps). During this period, a number of beautiful stamps were released on art and culture, flora and fauna, heritage, international relations, etc., which included – a set of two stamps jointly issued on Indo-France relations, a set of two stamps on the 30th Anniversary of Diplomatic Relations between India and Republic of Korea, a set of four stamps each on Medicinal Plants of India, Temple Architecture, Water Falls of India, Mangroves of India, Greetings and Indian Snakes.

4.8 Items of postal stationery viz. postcard, envelopes, registered envelopes, inland letter card and aerogrammes carrying advertisements, socially relevant messages, aimed at generating public awareness, etc. in English, Hindi as well as regional languages were also issued during the year.

4.9 Sale of Philatelic items is carried out all over the country through 65 Philatelic Bureaux and around 900 Philatelic Counters including all the Head Post Offices and Mukhya Dak Ghars of the country.

4.10 During July, 2003 a Stamp Popularity Poll, 2003 was organised all over the country.

4.11 “Design a Stamp Competition, 2003” was also held Circle-wise all over the country on 14th November, 2003.

Philatelic Exhibition

4.12 Exhibitions are crucial to the preparation of Philately as a hobby and for increasing the awareness of collectors and the public. During 2003-2004, 20 exhibitions were held throughout the country in different Postal Circles.

अध्याय 5

व्यवसाय विकास कार्यकलाप

5.1 विभाग के मूल्यवर्धित प्रीमियम उत्पादों के डिजाइन, मॉनीटरिंग करके उनके विकास एवं विपणन हेतु वर्ष 1996 में व्यवसाय विकास निदेशालय की स्थापना की गई थी। व्यवसाय विकास निदेशालय का मुख्य दायित्व मूल्यवर्धित सेवाओं का संकेन्द्रित प्रबंधन सुनिश्चित करना है तथा इसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

- मौजूदा मूल्यवर्धित उत्पादों एवं सेवाओं का प्रशासन, विस्तार एवं संवर्धन
- नए मूल्यवर्धित उत्पादों एवं सेवाओं की योजना बनाना एवं उन्हें प्रयोग में लाना
- उनकी रिटेलिंग एवं नेटवर्किंग हेतु प्रक्रियाएं, विनियमन एवं दिशानिर्देश
- बाजार अध्ययन, बाजार परीक्षण एवं उत्पाद सुधार
- बाजार नीतियां, गठजोड़ एवं सहयोग
- मूल्यवर्धित उत्पादों एवं सेवाओं की वृद्धि की निगरानी एवं समीक्षा

- विभाग के निष्क्रिय संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग की संभावना की खोज

उत्पाद

5.2 व्यवसाय विकास निदेशालय स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा, व्यवसाय डाक, बधाई डाक, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, मीडिया पोस्ट, मेघदूत पोस्टकार्ड, डाटा पोस्ट, ई-बिल पोस्ट, ई-पोस्ट और बिल मेल सेवा के प्रचालन एवं विपणन के लिए उत्तरदायी है।

व्यवसाय वृद्धि

5.3 वित्तीय वर्ष 2003-2004 के दौरान प्रीमियम उत्पादों से 7472.53 मिलियन रु. की वसूली हुई। उत्पादवार राजस्व नीचे दर्शाया गया है।

तालिका-3 व्यवसाय विकास कार्यकलापों की उत्पादवार राजस्व वृद्धि (मिलियन रु. में)			
उत्पाद	वर्ष 2002-2003 में राजस्व	वर्ष 2003-2004 में राजस्व	%वृद्धि/कमी
स्पीड पोस्ट	2430.1	2983.59	22.77
व्यवसाय डाक	2768.6	3651.14	31.87
मीडिया पोस्ट	59.7	57.47	(-) 3.73
एक्सप्रेस पोस्ट	261.0	314.49	20.49
रिटेल पोस्ट	78.7	336.50	327.57
बधाई डाक	3.8	3.95	3.94
* अन्य व्यवसाय सेवा	34.5	125.39	263.44
कुल	5636.4	7472.53	32.57

- अन्य में शामिल हैं : सैटेलाइट पोस्ट, ई-पोस्ट, ई-बिल पोस्ट आदि।

Chapter 5

BUSINESS DEVELOPMENT ACTIVITIES

5.1 Business Development Directorate was set up in 1996 to design, monitor, develop and market value-added premium products of the Department. The main responsibility of the Business Development Directorate is to ensure focussed management of value added services and it includes the following: -

- Administration, expansion and promotion of the existing value-added products and services;
- Planning and introduction of new value-added products and services;
- Procedures, regulations and guidelines for their retailing and networking;
- Market study, market testing and product improvement;
- Market strategies, alliances and cooperation;
- Monitoring and review of growth of value-added products and services;

- Exploring the scope of commercial utilization of idle resources of the Department;

Products

5.2 Business Development Directorate is responsible for the operations and marketing of Speed Post, Speed Post Passport Service, Business Post, Greeting Post, Express Parcel Post, Media Post, Meghdoot Post Card, Data Post, e-Bill Post, e-Post and Bill Mail Service.

Business Growth

5.3 During the financial year 2003-04, the revenue realized from premium products was Rs. 7,472.53 Million. The Product-wise revenue is reflected below :-

TABLE 3
PRODUCT-WISE REVENUE GROWTH OF BUSINESS DEVELOPMENT ACTIVITIES
(Rs. in Million)

Product	Revenue in 2002-2003	Revenue in 2003-2004	% of increase
Speed Post	2,430.10	2,983.59	22.77
Business Post	2,768.60	3,651.14	31.87
Media Post	59.70	57.47	(-)3.73
Express Post	261.00	314.49	20.49
Retail Post	78.70	336.50	327.57
Greeting Post	3.80	3.95	3.94
*Other Business Services	34.50	125.39	263.44
Total	5,636.40	7,472.53	32.57

*Others includes : Satellite Post, e-Post, e-Bill Post etc.

स्पीड पोस्ट

5.4 त्वरित एवं समयबद्ध वितरण सेवाएं प्रदान करने के लिए सात मेट्रो नगरों को जोड़ते हुए 1986 में स्पीड पोस्ट सेवाएं शुरू की गई थीं। स्पीड पोस्ट के वृहत नेटवर्क के अंतर्गत राष्ट्रीय नेटवर्क के तहत भारत में 156 प्रमुख शहरों/नगरों तथा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में 97 देश जुड़े हुए हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य स्पीड पोस्ट नेटवर्क में 772 शहर और जिला मुख्यालय जुड़े हुए हैं जहां से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय गंतव्य स्थानों के लिए स्पीड पोस्ट वस्तुएं बुक की जा सकती हैं।

5.5 स्पीड पोस्ट ग्राहकों को पूरे देश तथा समूची दुनिया में पत्रों, दस्तावेजों तथा 35 कि.ग्रा. तक के पार्सलों की समयनिष्ठ एवं सुनिश्चित वितरण सेवा उपलब्ध करवाता है। केन्द्रों को जोड़ने के लिए उपलब्ध तीव्रतम परिवहन के साधन को ध्यान में रखते हुए वितरण मानदंड निर्धारित किए जाते हैं। इसके प्रचालन एवं प्रबंधन में बाणिज्यिक दृष्टिकोण के साथ इसका व्यावसायिक सेवा के रूप में प्रबंधन किया जाता है।

5.6 स्पीड पोस्ट ब्राण्ड में घरेलू सेवाएं, अंतर्राष्ट्रीय सेवा, स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा, स्पीड पोस्ट मनीआर्डर एवं स्पीड पोस्ट उपहार सेवा शामिल हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान स्पीड पोस्ट से उत्पन्न राजस्व 2983.59 मिलियन रुपये रहा है जो पिछले वर्ष की तुलना में 22.77% की वृद्धि दर दर्शाता है।

ऑनलाइन ट्रेक एवं ट्रेस का क्रियान्वयन

5.7 इंटरनेट आधारित ट्रेक एवं ट्रेस प्रणाली स्पीड पोस्ट एवं एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट हेतु क्रियान्वित की गई है जहां एक ग्राहक इंटरनेट के माध्यम से अपने माल की स्थिति के संबंध में ऑनलाइन जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसे राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केन्द्रों और राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्रों में प्रचालित किया गया है।

स्पीड पोस्ट के तहत मूल्यवर्धन

5.8 नियमित आधार पर स्पीड पोस्ट करने वाले निगमित ग्राहकों को मुफ्त पिकअप सेवा, वॉल्यूम आधारित छूट एवं क्रेडिट सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है।

स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा

5.9 डाक विभाग ने विदेश मंत्रालय की साझेदारी में 5 मार्च, 2001 को स्पीड पोस्ट पासपोर्ट सेवा प्रारंभ की। इस सेवा के तहत चुनिंदा स्पीड पोस्ट कार्यालयों पर पासपोर्ट आवेदन प्रपत्र बेचे जाते हैं। इन

केन्द्रों पर भरे हुए पासपोर्ट आवेदन प्रपत्र स्वीकार किए जाते हैं जिन्हें आगे कार्रवाई हेतु पासपोर्ट कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है। यह सेवा देशभर में 213 डाकघरों/स्पीड पोस्ट केन्द्रों पर उपलब्ध है।

व्यवसाय डाक

5.10 व्यवसाय डाक तैयारशुदा सेवाएं उपलब्ध करवाकर थोक प्रयोक्ताओं हेतु व्यवसाय समाधान प्रस्तुत करते हैं। यह मेल के एकत्रीकरण, निविष्टीकरण, पता लेखन, सीलिंग, फ्रैंकिंग आदि के रूप में डाक द्वारा प्रस्तावित सभी पारंपरिक सेवाओं का मूल्यवर्धन करता है। अधिकाधिक निगमित ग्राहकों द्वारा व्यवसाय डाक सेवाओं का प्रयोग किया जा रहा है चूंकि व्यवसाय मेल मेट्रो शहरों एवं कस्बों में सतत बढ़ रहा है। व्यवसाय डाक ने अपने प्रारंभ से, पिछले चार वर्षों के दौरान 31.87% की वृद्धि दर्ज की है। वर्ष 2003-2004 में व्यवसाय डाक के माध्यम से 3,651.14 मिलियन रुपए का राजस्व अर्जन हुआ है।

बधाई डाक

5.11 बधाई डाक सितम्बर 2000 में प्रारंभ की गई। यह बधाई संदेश एक लिफाफे के साथ आता है जिसपर एक डाक-टिकट मुद्रित है। यह मुद्रित टिकट कार्ड के ऊपर मुद्रित डिजाइन का लघु रूप है। यह कार्ड दो आकारों में उपलब्ध है तथा डाक-टिकट सहित इसका मुद्रित मूल्य क्रमशः 14 रु. एवं 17 रु. है। इन्हें पूरे देश में चुनिंदा डाकघरों में बेचा जाता है। बड़े डाकघरों में विशेष बधाई कार्ड काउंटर खोले गए हैं। बधाई डाक में डाक चिह्न के साथ-साथ कार्ड के प्रचलित डिजाइन की सुविधा भी मिलती है। 2003-04 के दौरान, "मिनिएचर पेंटिंग" के विषयपरक डिजाइन पर फोकस किया गया था।

एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट

5.12 यह सेवा 35 कि.ग्रा. तक वजन वाले पार्सलों की बुकिंग एवं प्रेषण करती है। कारपोरेट ग्राहकों को करार आधार पर सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। वर्ष 2003-2004 के दौरान एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट से 314.49 मिलियन रुपये राजस्व अर्जित किया गया।

मीडिया पोस्ट

5.13 मीडिया पोस्ट द्वारा डाक लेखन सामग्री, डाक वैन, पत्र-पेटियों आदि पर उत्पाद/सेवाओं के विज्ञापन के लिए कारपोरेट ग्राहकों/सरकारी संगठनों एवं अन्य बड़े निजी उपक्रमों को अवसर प्रदान किया जाता है। वर्ष 2003-2004 के दौरान मीडिया पोस्ट से अर्जित राजस्व 57.47 मिलियन रु. रहा है।

Speed Post

5.4 Speed Post Services were introduced in 1986 linking 7 Metro Cities with a view to provide fast and time-bound delivery services. Speed Post has a network linking 156 major cities/towns in India in the national network and 97 countries in the international network. In addition, 772 towns and district headquarters are linked on the State Speed Post Network from where Speed post articles can be booked for national and international destinations.

5.5 Speed Post offers the customer, time-specific and assured delivery service of letters, documents and parcels upto 35 Kg. across the country and around the world. Delivery norms are fixed taking into account the fastest transport available to link the stations. It is managed as a business service with commercial approach in its operations and management.

5.6 The Speed Post brand covers Domestic Services, International Services, Speed Post Passport Service, Speed Post Money-Order and Speed Post Gift Service. During 2003-04, revenue generation from Speed Post has been Rs. 2,983.59 Million, representing a growth rate of 22.77% over the previous year.

Implementation of Online Track & Trace

5.7 Internet based Track and Trace System has been implemented for Speed Post and Express Parcel Post wherein a customer can find out the status of his consignment online through the Internet. It has been operationalised in the National Speed Post Centres and in State Speed Post Centres

Value Additions under Speed Post

5.8 Free pick-up services, volume based discount and credit facility are provided to corporate customers using Speed Post on regulars basis.

Speed Post Passport Service

5.9 Department of Posts, in partnership with Ministry of External Affairs launched Speed Post Passport Service on 05th March 2001. Under this Service Passport Application Forms are sold at selected Speed Post Centres.

Filled-up Passport Application Forms are also accepted at these Centres, which are dispatched to the Passport Office for further processing. The Service is available across the country at 213 Post Offices/Speed Post Centres.

Business Post

5.10 Business Post offers business solutions for the bulk users by providing customised services. It provides value addition to all traditional services offered by the Post in the form of collection, insertion, addressing, sealing, franking etc. More and more corporate customers have been using Business Post Services as Business Mail continues to grow in the Metro Cities and Towns. Since the introduction of Business Post, it has registered an annual growth of over 31.87% in the last four years. In the year 2003-04, the revenue generated through Business Post is 3,651.14 Million.

Greeting Post

5.11 Greeting Post was introduced in September, 2000. The Greeting Post comes with an envelope, which has a printed postage stamp. This stamp is a miniature replica of the design on the card. The Cards are available in two sizes and are priced at Rs.14/- and Rs.17/- respectively, including postage. They are sold at selected Post Offices throughout the country. Special Greeting Card Counters have been organized in big Post Offices. Greeting Post also offers the facility of customized design of the Card as well as of the postage impression. During 2003-04, the focus was on thematic designs of "Miniature Painting".

Express Parcel Post

5.12 It provides for booking & dispatch of parcels weighing upto 35 Kg. The service is provided to corporate customers on a contractual basis. During 2003-04, the revenue earned was Rs. 314.49 Million.

Media Post

5.13 Media Post provides opportunities to corporate customers/Govt. organisations and other large private institutions to have their products/services advertised on the postal stationery, postal vans, letter-boxes etc. During 2003-04, revenue from Media Post has been Rs. 57.47 Million.

मेघदूत पोस्टकार्ड

5.14 एक नए प्रकार का पोस्टकार्ड जिसका नाम मेघदूत पोस्टकार्ड है, को 2 सितंबर, 2002 को शुरू किया गया था। इस पोस्टकार्ड का मूल्य 25 पैसे है तथा पते वाली तरफ बायीं ओर आधे हिस्से में एक विज्ञापन है। यह विज्ञापन चार रंगों में हो सकता है। यह ग्रामीण विपणन हेतु उत्तम अवसर प्रदान करता है। मेघदूत पोस्टकार्ड पर विज्ञापन की दर 2 रु. प्रति पोस्टकार्ड है। भारी मात्रा में मुद्रण करवाने वालों के लिए छूट भी प्राप्त है। 2002-2003 में विभाग ने इस उत्पाद से 2.7 मिलियन रु. और 2003-2004 में 13.6 मिलियन रु. अर्जित किए हैं।

डाटा पोस्ट

5.15 भारतीय डाक ने कारपोरेट जगत के साथ लोगों को जोड़ने के लिए अभिनव माध्यम शुरू किया है। यह उपभोक्ता पता, टेलीफोन संख्या, वैवाहिक स्थिति, लिंग, वय, पेशा, पासपोर्ट स्वामित्व के बारे में विस्तृत ब्यौरा एवं और अधिक सूचना देते हुए आंकड़े उपलब्ध करवाती है। कारपोरेट अपने उत्पादों की बिक्री के लिए इस आंकड़ा आधार का प्रयोग कर सकते हैं। भारतीय डाक ने चुनिंदा व्यवसाय घरानों के लिए विवरणिकाओं सहित प्रश्नावलियों के विकास, डिजाइन, मुद्रण एवं प्रेषण हेतु भी विशेषज्ञता प्राप्त की है।

ई-बिल पोस्ट

5.16 यह एक नई सेवा है जिसे विभाग द्वारा एक प्रौद्योगिकी-क्षम सेवा के रूप में ग्राहकों के लिए प्रारंभ किया गया है। इस सेवा से डाकघर काउंटर पर बिजली, टेलीफोन, मोबाइल, पानी एवं अन्य बिलों/देयताओं का भुगतान हो सकेगा।

ई-पोस्ट

5.17 यह डाक विभाग द्वारा देशभर में 30 जनवरी, 2004 को चालू की गई एक अन्य ई-क्षम सेवा है। ई-पोस्ट निकटतम प्रेषितियों को डाकघरों से ई-मेल के माध्यम से संदेश प्रिंट करने की अनुमति देता है तथा उनके डाक पतों पर उन्हें पत्रों के तौर पर वितरित करता है। इसी प्रकार किसी भी डाकघर पर अपना लिखित संदेश दिया जा सकता है जिसे वह डाकघर स्कैन करेगा और उसे आगे विश्व में किसी भी अन्य ई-मेल आई डी को ई-मेल के तौर पर अथवा भारत में किसी भी डाक पते पर भेजेगा। यह सेवा डाकघर की पहुंच हर कहीं करने के लिए शुरू की गई है। इस सेवा का उपयोग करने के लिए विभाग ने पूर्व-दत्त कार्ड जारी किए हैं। प्रत्येक प्रेषित के लिए ए-4 साइज के प्रत्येक संदेश हेतु ई-पोस्ट सेवाओं का प्रभार 10/- रु. है। बिलों, विवरणों, नोटिसों आदि के लिए एक त्वरित एवं किफायती साधन के तौर पर कारपोरेट बाजार इस सेवा से अत्यधिक प्रभावित हो रहा है।

रिटेल पोस्ट

5.18 समूचे देश में 1,50,000 से अधिक डाकघरों के अपने विशाल नेटवर्क के माध्यम से भारतीय डाक टेलीफोन/विद्युत/सरकारी तथा निजी संगठनों के मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं के उपभोक्ता बिलों को वसूलने का कार्य करता है। डाकघरों के काउंटरों पर अब सरकारी निकायों के फार्मों की भी बिक्री होती है। इसके अतिरिक्त सैलुलर कंपनियां डाकघर आउटलेटों का उपयोग अपने कैशकार्ड तथा रिचार्ज कूपनों की बिक्री के लिए भी करते हैं। इस सेवा से अच्छी संभावनाएं दिखी हैं, 2002-2003 के दौरान अर्जित राजस्व की तुलना में 2003-2004 के दौरान 327.57% की विकास दर दर्ज की गई।

बिल मेल सेवा

5.19 वित्तीय विवरणों, बिलों अथवा ऐसी अन्य मदों के संबंध में पत्र-व्यवहार के लिए 15 सितंबर, 2003 को देशभर में इस सेवा को प्रारंभ किया गया, जिसे सेवा प्रदाताओं द्वारा अपने ग्राहकों को डाक द्वारा भेजा जा सकता है। यह सेवा नियमित आधार पर स्थानीय अथवा एक जिले के अंदर वस्तुओं को वितरित करने के लिए है। प्रथम 20 ग्राम के लिए 3/-रु. तथा अतिरिक्त 20 ग्राम अथवा उसके अंश के लिए 1.60 रु. का प्रभार लिया जाता है। अपने प्रचालन के प्रथम छः महीनों में ही इस सेवा से 58.93 मिलियन रु. का राजस्व अर्जन हुआ।

व्यवसाय विकास द्वारा की गई नई पहल

5.20 **कस्टमाइज्ड सर्वेक्षण** : दिल्ली नगर निगम की ओर से सम्पत्ति धारकों का एक डाटाबेस तैयार करने हेतु एक सर्वेक्षण किया गया था। देश में डाक सेवाओं द्वारा यह प्रक्रिया पहली बार शुरू की गई थी। भारत के महापंजीयक के लिए गांवों का आधारभूत सर्वेक्षण भी किया गया था।

5.21 **व्यवसाय पैकेज अनुमोदित करने के लिए सर्किल अध्यक्षों की शक्ति**: विभाग की मौजूदा मानवशक्ति, नेटवर्क और आधारभूत संसाधनों के उपयोग द्वारा विभाग के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्जित करने के उद्देश्य से डाक सर्किलों के अध्यक्षों को व्यवसाय पैकेज अनुमोदित करने की शक्ति दी गई है।

5.22 **राष्ट्रीय लेखा प्रबंधन** : अगस्त 2003 से ज्यादा परिमाण में डाक देने वाले ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक नई व्यवसाय योजना है। राष्ट्रीय लेखा प्रबंधन का उद्देश्य महत्वपूर्ण ग्राहकों के लिए विशिष्ट ग्राहकोन्मुखी सेवा तथा सुनम्य मूल्य प्रदान करना है।

5.23 **भारत के निर्वाचन आयोग को सहायता** : चयनित डाकघरों में निर्वाचक नामावली प्रदर्शित करने और निर्वाचक नामावली में संशोधन के लिए आवेदन फार्मों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार को सहायता प्रदान की गई।

Meghdoot Post Card

5.14 A new kind of Postcard called Meghdoot Postcard was launched on September 2, 2002. This Postcard is priced at Rs. 0.25 each and carries an advertisement on the left hand half portion on the address side. The advertisement can be in four colours. It provides an ideal opportunity for rural marketing. The rate per advertisement on Meghdoot Postcard is Rs. 2/- per card. Volume discounts are also available. Department has earned Rs. 2.7 Millions in 2002-03 and Rs. 13.6 Millions in 2003-04 from the product.

Data Post

5.15 India Post has recently introduced an innovative medium for connecting people with the corporates. It provides data on households with detailed information on consumer addresses, telephone numbers, marital status, gender, age, occupation, passport ownership and much more. Corporates can use this data for selling their products. India Post has also specialised in developing, designing, printing and mailing communication questionnaires as well as the brochures for business houses to select clientele.

e-Bill Post

5.16 This is a new service. It is one of the technology-enabled services. The service is useful for the payment of electricity, telephone, mobile, water and other kinds of bills/dues at the Post Office Counter.

e-Post

5.17 This is another e-enabled service launched nationwide by Department of Posts on 30th January, 2004. e-Post allows sending of messages through e-mail to be printed in Post Offices nearest to the addressees and to be delivered to them at their postal addresses as letters. Similarly, written message can be brought to a Post Office which will scan them and can further send it as e-mail to any e-mail ID in the world or to a postal address in India. This service has been introduced keeping in view the last mile advantage of the Post Office. The Department has issued pre-paid cards to use this Service. The charges for e-post services are Rs. 10/- per message of A-4 size per addressee. The corporate world has increasingly been attracted to e-Post as a quick and inexpensive means of using bills, statements, notices, etc.

Retail Post

5.18 Through its vast network of more than 1,50,000

Post Offices across the country, India Post offers the facility to collect customers bills for service industries like telephone/electricity/mobile phone users etc. for Govt. and private organizations. Post Offices also sell forms for public bodies over the counter of Post Offices. Besides this, Cellular companies also use PO outlets for sale of cash cards and recharge coupons. The product has shown a good potential, registering growth rate of 327.57% during 2003-04, over the revenue earned during 2002-03.

Bill Mail Service

5.19 This service was launched nationwide on 15th September, 2003 for mailing of communications in the nature of financial statements, bills or other such items, which may be posted by service providers to their customers. This Service is meant for articles to be delivered locally or within a district on regular basis. The charges for bill mailing service are Rs. 3/- for first 20 Gms. and Rs. 1.60 for additional 20 Gms. and part thereof. This Service generated a revenue of Rs. 58.93 Million in the first six months of its operation.

New initiatives of Business Development Directorate

5.20 **Customised Surveys :** A survey was conducted to prepare the database of property holders on behalf of Municipal Corporation of Delhi. This exercise was carried out for the first time by the Postal Services in the country. Infrastructure survey of villages was also carried out for the Registrar General Of India.

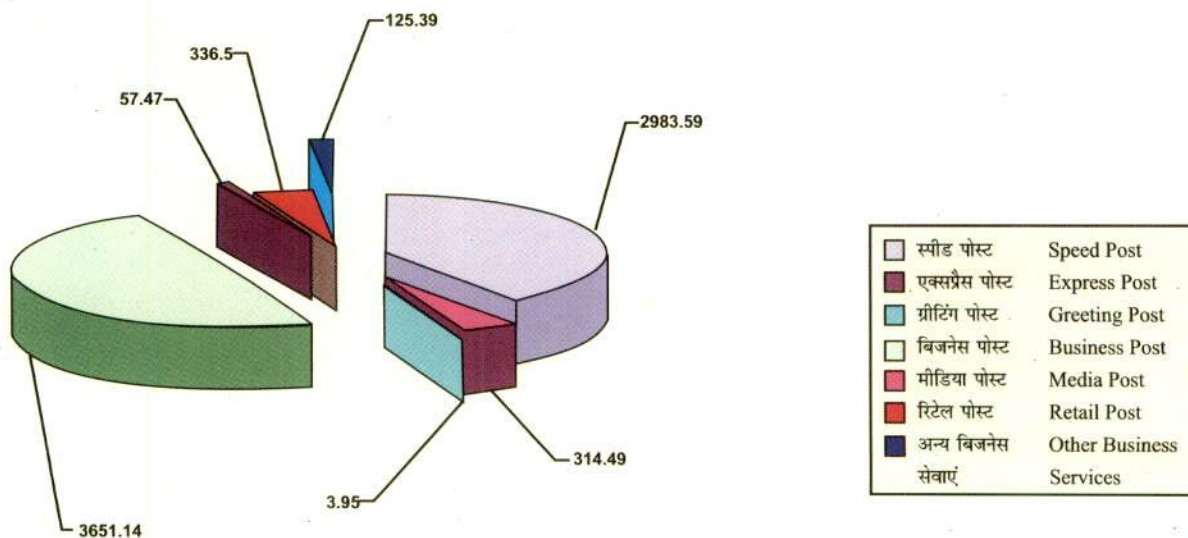
5.21 **Empowerment of Heads of Circles to approve Business Packages :** Heads of Postal Circles have been empowered to approve Business Packages for the purpose of generating additional revenue for the Department by utilising the existing manpower, network and infrastructure resources of the Department.

5.22 **National Accounts Management :** A new business strategy, tailor-made to attract high business volume customers has been introduced since August, 2003. National Accounts Management aims at providing specialised customer friendly service and a flexible pricing format for important customers.

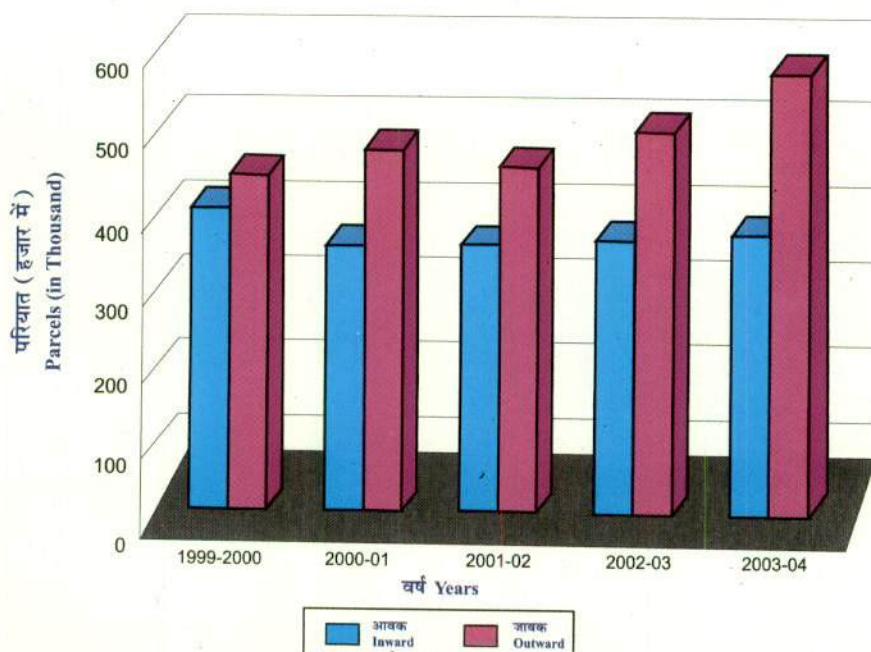
5.23 **Assistance to Election Commission of India:** Assistance was provided to Election Commission of India for display of Electoral Rolls in selected Post Offices and for receipt of application forms for correction in the Electoral Rolls.

व्यवसाय विकास के कार्यकलापों का उत्पादवार राजस्व विभाजन
(2003-04) (रुपये मिलियन में)

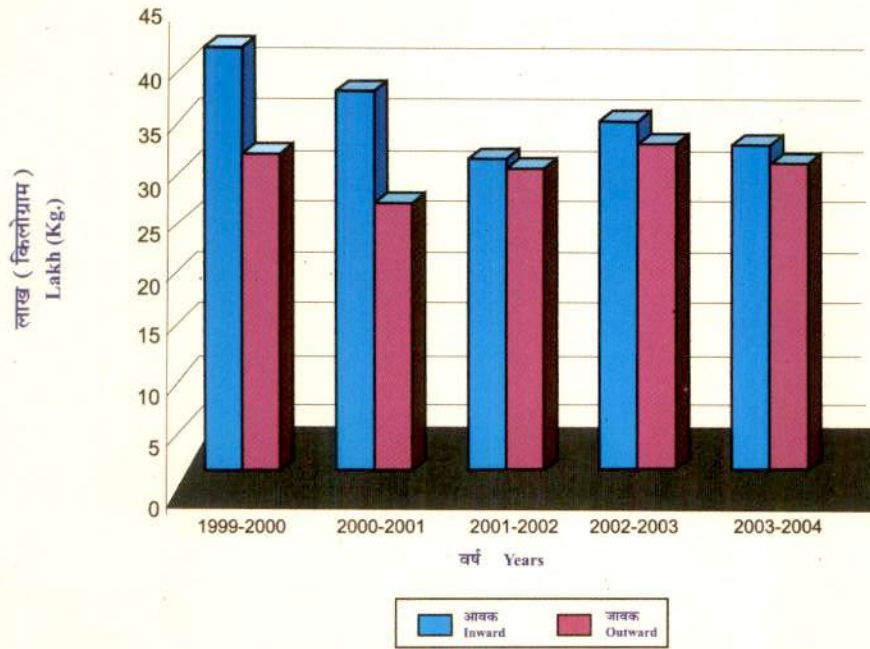
**Product-wise Revenue Segmentation of Business Development Activities
(2003-04) (Rs. in Million)**



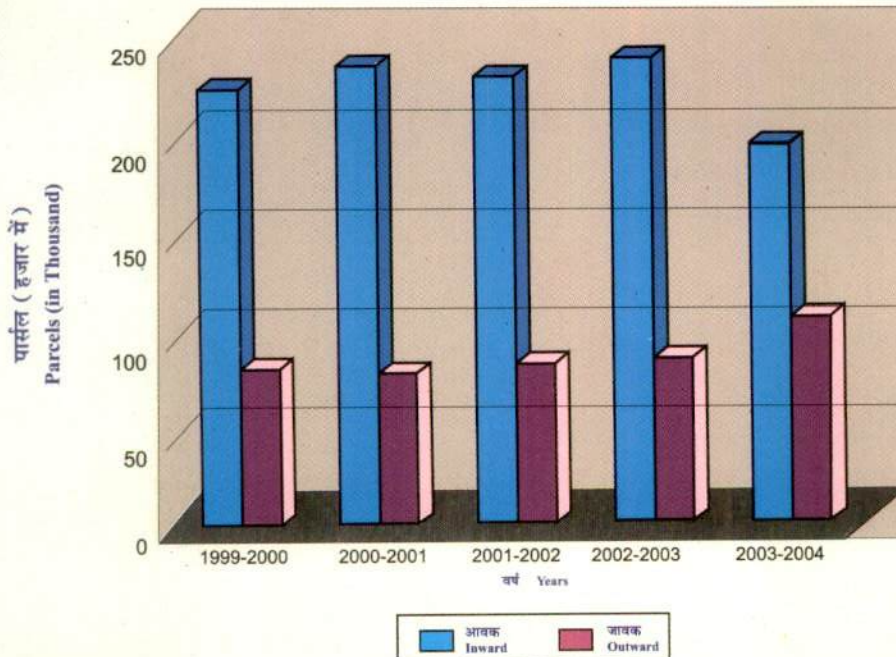
अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट परियात
INTERNATIONAL SPEED POST TRAFFIC



पत्र, पोस्टकार्ड और अन्य वस्तुएं
LETTERS, POSTCARDS & OTHER ARTICLES



विदेश पार्सल परियात
FOREIGN PARCEL TRAFFIC



अध्याय 6

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

6.1 यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी है जिसके 190 देश सदस्य हैं। इसका मुख्यालय बर्न, स्विटजरलैण्ड में है। यू पी यू की 1874 में स्थापना हुई थी तथा भारत 1876 से इसका सदस्य रहा है। यू पी यू डाक मामलों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देती है तथा अपने विभिन्न निकायों तथा बहुपक्षीय समझौतों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रचालनों का विनियमन करती है। यू पी यू के चार महत्वपूर्ण अंग हैं- कांग्रेस, प्रशासन परिषद, डाक प्रचालन परिषद और अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो।

6.2 40 सदस्यीय डाक प्रचालन परिषद महत्वपूर्ण प्रचालन, वाणिज्यिक, आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग से संबंधित समस्याओं पर अध्ययन करने के लिए उत्तरदायी है। भारत 1964 से निरंतर डाक प्रचालन परिषद का सदस्य रहा है। प्रशासन परिषद यू पी यू का 41 सदस्यीय निर्वाचित निकाय है तथा यह दो कांग्रेसों के बीच यूनिन के काम की निरंतरता को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है।

6.3 तत्कालीन सचिव (डाक) की अध्यक्षता में चार सदस्यीय भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन परिषद और डाक प्रचालन परिषद की बर्न, स्विटजरलैण्ड में 29 जनवरी, 2004 से 13 फरवरी, 2004 तक आयोजित हुए संयुक्त सत्र में भाग लिया।

भारतीय डाक-सेवा गुणवत्ता निधि न्यासी बोर्ड का सदस्य

6.4 वर्ष 2001 के इसके वार्षिक अधिवेशन के दौरान डाक प्रचालन परिषद ने सेवा गुणवत्ता निधि के कार्य की देखरेख करने के लिए न्यासी बोर्ड का गठन किया (औद्योगिकीकृत देशों से विकासशील देशों के डाक प्रवाह पर अनुप्रयोज्य 3.427 एसडीआर प्रति किलोग्राम के टर्मिनल शुल्क दर में 7.5% वृद्धि करके सेवा गुणवत्ता निधि (क्यूएसएफ) की स्थापना की गई। न्यासी बोर्ड की

शक्तियां न्यास विलेख में प्रतिष्ठापित हैं। न्यासी बोर्ड में 9 सदस्य हैं जो भिन्न-भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाते हैं। भारत एशिया-प्रशांत क्षेत्र का निर्वाचित सदस्य है। भारत ने सेंट पीटर्सबर्ग, रूस और बर्न में क्रमशः जुलाई और अक्टूबर, 2003 में आयोजित न्यासी बोर्ड की बैठकों में भाग लिया। भारत द्वारा क्यूएसएफ सचिवालय को प्रस्तुत तीनों प्रस्ताव न्यासी बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए गए। ये (i) उच्च गुणवत्ता के डाक-टिकट विरूपण और डाक पर दिनांकित मुहर लगाने; (ii) एकीकृत गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम; (iii) एमएआरआईए पर आधारित पक्ष-डाक की सुरक्षा से संबंधित हैं।

6.5 भारत को डाक प्रचालन परिषद की कई महत्वपूर्ण समितियों जैसे "लाएबिलिटी प्रोजेक्ट टीम (पी टी)" ट्रांजिशन पी टी, उपभोक्ता संबंध पी टी, टर्मिनल शुल्क कार्यदल (टीडीएजी) और इसके उप-दलों, तकनीकी सहयोग कार्यदल (टीसीएजी), डाक सुरक्षा कार्यदल (पीएसएजी), अध्यक्ष, प्रशासन परिषद की समिति-1 अध्यक्ष, विश्व फिलैटली विकास संघ (डब्ल्यूएडीपी), आदि में भी नामित किया जाता है।

भारत-फ्रांस संयुक्त समिति

6.6 डाक पर भारत-फ्रांस संयुक्त समिति की तीसरी बैठक 23 और 24 अप्रैल, 2003 को नई दिल्ली में आयोजित हुई। यह निर्णय लिया गया कि (क) वित्तीय सेवाओं और बीमा; (ख) पार्सल डाक और डाटा आधारित प्रबंधन; (ग) मानव संसाधन विकास; (घ) डाक नेटवर्किंग का आधुनिकीकरण और तकनीकी सहायता के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग किया जाए।

6.7 दक्षिण अफ्रीका के वरीय अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय डाक के अधिकारियों के साथ 21 अप्रैल, 2003 को बैठक की। ईएमएस स्पीड पोस्ट सेवाओं को प्रयोग में लाने, बचत बैंक प्रचालनों, नए डाक उत्पादों, प्रत्यक्ष विपणन के लिए डाटाबेस जैसे क्षेत्रों में परस्पर सहयोग करने के लिए विचार-विमर्श हुआ।

Chapter 6

INTERNATIONAL RELATIONS

Universal Postal Union

6.1 Universal Postal Union (UPU) is a specialized agency of the United Nations having 190 member countries and is headquartered at Berne, Switzerland. The UPU was established in 1874 and India has been a member of the Union since 1876. The UPU promotes international cooperation in the field of postal affairs and regulates the international postal operations through its various bodies and multilateral agreements. The UPU has four main organs - Congress, Council of Administration (CA), Postal Operations Council (POC) and International Bureau (IB).

6.2 The 40 member Postal Operations Council is responsible for conducting studies on important operational, commercial, economic and technical cooperation problems, which are of interest to Postal Administrations of all countries. India has been member of the POC continuously since 1964. The Council of Administration (CA) is a 41 member elected body of the UPU and is responsible for ensuring the continuity of the Union work between two Congresses.

6.3 A four member Indian Delegation headed by the then Secretary (Posts) attended the Joint Session of Council of Administration and Postal Operation Council held at Berne, Switzerland from 29th January, 2004 to 13th February, 2004.

India Post – a Member of Quality of Service Fund Board of Trustees

6.4 During its annual Session of 2001, Postal Operations Council created the Board of Trustees to manage the work of the Quality of Service Fund (Quality of Service Fund was established by a 7.5% increase in the terminal dues rate of 3.427 SDR per Kg. applied to mail flows from the industrialised countries to the

developing countries). The powers of the Board of Trustees are enshrined in the Deed of Trust. The Board of Trustees comprises 9 members elected from different geographical regions. India is an elected member from the Asia Pacific Region. India participated in the meetings of Board of Trustees held at St. Petersburg, Russia and Berne in July and October, 2003 respectively. Three proposals submitted by India to the QSF Secretariat were approved by Board of Trustees. These relate to (i). High quality stamp cancellation and date stamping of mail; (ii). Integrated Quality Control Programme; (iii). Security of letter mail based on MARIA.

6.5 India has also been nominated in a number of important Committees of the Postal Operations Council (POC) like Liability Project Team (PT), Transition PT, Customer Relations PT, Terminal Dues Action Group (TDAG) and its sub-groups, Technical Cooperation Action Group (TCAG), Postal Security Action Group (PSAG), Chairman, Committee-I of Council of Administration (CA), Chairman World Association for Development of Philately (WADP), etc.

Indo French Joint Committee

6.6 The 3rd Indo-French Joint Committee Meeting on Posts was held in New Delhi on 23rd and 24th April, 2003. It was decided to improve co-operation in the areas of (a). Financial Services & Insurance; (b). Parcel Post and Date Base Management (c). Human Resource Development, (d). Modernisation of Postal Networking and Technical Assistance.

6.7 A delegation of Senior Officers from South Africa held a meeting with Officers of India Post on 21st April, 2003. Discussions were held for mutual cooperation in the areas of Introduction of EMS Speed Post Services, Savings Bank Operations, New Postal Products, Database for direct marketing.

6.8 निदेशक, डाक प्रशिक्षण केन्द्र मैसूर को नैरोबी, कीनिया में 05 से 08 मई, 2003 तक आयोजित हुई डाक सेवाओं में गुणवत्ता पर कार्यशाला में यू पी यू परामर्शदात्री चुना गया।

एशिया-प्रशांत डाक सहयोग प्रबंधन बोर्ड

6.9 भारत एशिया प्रशांत डाक सहयोग प्रबंधन बोर्ड (एपीपी-सीएमबी) का एक निर्वाचित सदस्य है। भारत ने बोर्ड की हनोई, वियतनाम में 28 जुलाई, 2003 को आयोजित हुई बोर्ड की बैठक में भाग लिया। बैठक के उपरांत एपीपीयू रीजनल टर्मिनल शुल्क कार्यशाला आयोजित हुई। कार्यशाला में विकासशील देशों के राजस्व को सुरक्षित करने के प्रस्तावों पर चर्चा की गई।

प्रतिनिधिमंडल

6.10 इस वर्ष ईरान और कोरिया के प्रतिनिधिमंडलों ने क्रमशः 17 से 20 जुलाई, 2003 और 15 से 16 सितंबर, 2003 तक भारत का दौरा किया। डाक क्षेत्र में आपसी सहयोग में सुधार लाने के लिए बैठकें आयोजित की गईं। फिलैटलिक डाक-टिकटों का संयुक्त विमोचन इन प्रतिनिधिमंडलों की चर्चा का मुख्य विषय था और इसके तौर तरीकों को अंतिम रूप दिया गया।

अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में प्रतिभागिता

6.11 भारत ने ब्रासिलिया, ब्राजील में 24 से 28 अक्टूबर, 2003 को आयोजित एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आफिसेज आफ एक्सचेंज पर कार्यदल और टर्मिनल शुल्क कार्यदल (टीडीएजी) की ट्रांजिट प्रोजेक्ट टीम की बैठक में भाग लिया।

6.12 भारत ने चियोनान, चुंगनम प्रांत, कोरिया गणराज्य में डाक लॉजिस्टिक स्वचलीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी पर 22 से 26 सितंबर, 2003 को आयोजित हुई संगोष्ठी में भाग लिया। भारत ने डाक लॉजिस्टिक्स स्वचलीकरण और डाक प्रशासन में सूचना प्रौद्योगिकी के अधिष्ठापन पर अपने अनुभव बताए।

6.13 भारत ने संचार एवं परिवहन पर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) की तकनीकी समिति की इस्लामाबाद, पाकिस्तान में 01 से 02 दिसंबर, 2003 को आयोजित तीसरी बैठक में भाग लिया।

6.14 डाक और दूरसंचार पर भारत-ईरान संयुक्त कार्यदल की तेहरान (ईरान) में 24 से 25 फरवरी, 2004 तक दूसरी बैठक आयोजित हुई। एक दो-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने इस बैठक में डाक विभाग का प्रतिनिधित्व किया जो विचार-विमर्श के केन्द्र में थे। उनमें फिलैटली के क्षेत्र में सहयोग करने और भारतीय डाक द्वारा ईरानी डाक कर्मचारियों को भारत में प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम शामिल थे।

6.15 एक दो-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें उपमहानिदेशक (आईआर) और जेएस एंड एफए शामिल थे, ने चेंगडु, चीन में 24 से 26 मार्च, 2004 तक आयोजित बीजिंग डाक कार्यनीति के क्रियान्वयन पर हुए सम्मेलन में भाग लिया। यह सम्मेलन बीजिंग डाक कार्यनीति के क्रियान्वयन पर बुखारेस्ट में आयोजित होने वाली 23 वीं यूपीयू कांग्रेस में प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित किया गया था। बीजिंग डाक कार्यनीति बीजिंग में 1999 में आयोजित हुए यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन कांग्रेस में अपनाई गई थी।

एशिया-प्रशांत डाक संघ

6.16 एशिया-प्रशांत डाक संघ-कार्यकारी परिषद (एपीपीयू-ईसी) के चार अंग हैं। कांग्रेस इसका सर्वोच्च निकाय है और इसकी पांच वर्षों में एक बार बैठक होती है जिसमें सभी प्रमुख निर्णय लिए जाते हैं। कार्यकारी परिषद की सिद्धांत रूप में वर्ष में एक बार बैठक होती है और यह दो कांग्रेसों के बीच संघ के कार्य की निरंतरता सुनिश्चित करती है।

6.17 इस वर्ष वार्षिक बैठक हैनान द्वीप, चीन में 08 से 12 दिसंबर, 2003 तक आयोजित की गई। भारतीय डाक ने तकनीकी

6.8 Director, Postal Training Centre, Mysore was chosen as UPU Consultant in the Workshop on Quality in Postal Services held at Nairobi, Kenya from 05th to 08th May, 2003.

Asia – Pacific Post Cooperative Management Board

6.9 India is an elected member of the Asia Pacific Post Cooperative Management Board (APP – CMB). India participated in the meeting of the Board held on 28th July, 2003 at Hanoi, Vietnam. The meeting was followed by APPU Regional Terminal Dues Workshop. In the workshop, proposals to safeguard the revenue of the developing countries were developed.

Delegations

6.10 This year delegations from Iran and Korea visited India from 17th to 20th July, 2003 and 15th to 16th September, 2003 respectively. Meetings were held to improve mutual cooperation in Postal Sector. Joint release of Philatelic Stamps was the main issue discussed by these delegations and the modalities for the same were finalised.

Participation in International Meetings

6.11 India participated in the meeting of the Working Group on Extra Territorial Offices of Exchange (ETOE) and Transit Project Team of the Terminal Dues Action Group (TDAG) held at Brasilia, Brazil from 24th to 28th October, 2003.

6.12 India participated in a Seminar on the Postal Logistics Automation and Information Technology held at Cheonan, Chungnam Province, Republic of Korea from 22nd to 26th September, 2003. India shared experiences on the postal logistic automation and the introduction of information technology to the Postal Administration.

6.13 India participated in the 3rd meeting of South Asian Association of Regional Countries (SAARC) Technical Committee on Communication and Transport held at Islamabad, Pakistan from 01st to 02nd December, 2003.

6.14 The 2nd meeting of the Indo-Iran Joint Working Group on Posts and Telecommunications was held at Tehran (Iran) from 24th to 25th February, 2004. A two member delegation represented the Department of Posts at this meeting. The discussions centred around cooperation in the field of Philately and Training Programmes for Iranian Postal Officials in India by India Post.

6.15 A two member delegation comprising Deputy Director General (IR) and JS&FA attended the Conference on implementation of the Beijing Postal Strategy at Chengdu, China from 24th to 26th March, 2004. The conference was convened to discuss the report to be presented to the 23rd UPU Congress in Bucharest on implementation of the Beijing Postal Strategy, adopted in the 1999 Universal Postal Union Congress in Beijing.

Asia – Pacific Postal Union

6.16 The Asian Pacific Postal Union – Executive Council (APPU – EC) has four organs – The Congress, which is the supreme body and meets once in five years to take all the major decisions, the Executive Council, which meets in principle once in a year and ensures the continuity of the work of the Union between two Congresses.

6.17 This year the annual meeting was held from 08th to 12th December, 2003 at Hainan Island, China.

सहायता, सेवा गुणवत्ता निधि, डाक सुरक्षा आदि पर विचार-विमर्श करने में सक्रियता से भाग लिया। भारत ने (क) व्यापार एवं सेवाओं पर सामान्य करार की चुनौतियां और अवसर; (ख) एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आफिसेंज ऑफ एक्सचेंज; (ग) टर्मिनल शुल्क का भविष्य; (घ) सेवा गुणवत्ता निधि पर हुई बैठकों के दौरान दस्तावेज प्रस्तुत किया। तकनीकी सहयोग और सेवा की गुणवत्ता पर एपीपीयू की स्थायी समिति के अध्यक्ष के तौर पर भारत ने इस विषय पर रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इस क्षेत्र में भावी दिशा के बारे में सुझाव दिया।

परियोजनाएं

6.18 डाक विभाग ढाका (बांग्लादेश), यांगून (म्यांमार) और काठमांडु (नेपाल) में जनरल पोस्ट आफिसों के डाकघर काउंटर्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजनाओं पर काम कर रहा है। इसके लिए धनराशि यूनिवर्सल पोस्टल यूनिन द्वारा उपलब्ध कराई गई है। कम्प्यूटरीकरण और साफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में क्षमताओं को मान्यता देते हुए यूपीयू द्वारा ये कार्यकलाप भारतीय डाक द्वारा पूरे करवाए जा रहे हैं।

6.19 परियोजनाएं तीन चरणों में पूरी की जाएंगी। पहला चरण साइट सर्वेक्षण और सिस्टम-अध्ययन से संबंधित है। जनवरी, 2004 माह के दौरान भारतीय डाक के तीन प्रतिनिधि मंडलों, जिनमें से प्रत्येक में चार सदस्य थे, ने क्रमशः म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल का दौरा किया। परियोजनाओं के लिए सिस्टम अध्ययन और साइट सर्वेक्षण के साथ ही परियोजनाओं का पहला चरण पूरा कर लिया गया है। द्वितीय चरण जो

हार्डवेयर की खरीद से संबंधित है, पर काम चल रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवा गुणवत्ता का निरंतर परीक्षण

6.20 यूनिवर्सल पोस्टल यूनिन ने अंतर्राष्ट्रीय प्राथमिकता वाले पत्र-डाक वस्तुओं के पारेषण समयों के निरंतर परीक्षण-कार्य को शुरू किया है। यह विधि अंतर्राष्ट्रीय सेवा गुणवत्ता को आंकने के लिए डाक प्रशासनों को एक सरल एवं प्रभावपूर्ण माध्यम प्रदान करती है। इसमें परीक्षण में भाग लेने वालों के निजी पत्तों पर परीक्षण पत्र डाले और वितरित किए जाते हैं। एक साधारण भौगोलिक वितरण को ध्यान में रखकर विभिन्न शहरों में रहने वाले भागीदारों के पत्तों पर एक सप्ताह में लगातार छह दिन परीक्षण पत्र डाले जाते हैं। पोस्ट करने तथा वितरण के आंकड़े अलग से संसाधित करके एक तटस्थ एवं स्वतंत्र निकाय (यूनिवर्सल पोस्टल यूनिन अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो) के माध्यम से इंटरनेट द्वारा पारेषित किए जाते हैं जिससे परिणामों की जांच की जा सके तथा परिणाम तैयार किए जा सकें।

6.21 भारतीय डाक ने फरवरी, 2004 से सतत परीक्षण में भाग लेने का निर्णय लिया है, तथा अभी फ्रांस, मालदीव व नेपाल के साथ परीक्षण पत्रों का सिलसिला जारी है।

अंतर्राष्ट्रीय परियात

6.22 अंतर्राष्ट्रीय ई एम एस का परियात तालिका-4 में दर्शाया गया है :

तालिका-4 अंतर्राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट- ई एम एस परियात			
	2000	2003	वृद्धि/कमी (% में)
1. आवक डाक वस्तुएं	357525	372655	(+) 4.23%
2. जावक डाक वस्तुएं	498880	576418	(+)15.54%

पत्र डाक

6.23 वर्ष के दौरान पत्र-डाक के भार में अंतर्राष्ट्रीय आवक व जावक में क्रमशः 6.65% तथा 6.48% की कमी आई है जिसे तालिका-5 में दर्शाया गया है।

पत्र लेखन प्रतियोगिता

6.26 33वीं पत्र लेखन प्रतियोगिता 04 जनवरी, 2004 को देश भर में आयोजित की गई। मार्च 2004 में प्रतियोगिता के परिणाम

India Post actively participated in discussions on Technical Assistance, Quality of Service Fund, Postal Security, etc. India also presented papers during the meeting on (a). Challenges and Opportunities through General Agreement on Trade and Services (GATS) for the Post; (b). Extra Territorial Offices of Exchange (ETOE), (c). The Future of the Terminal Dues; (d). Quality of Service Fund. As the Head of APPU Standing Committee on Technical Cooperation and Quality of Service, India presented the report on the subject and suggested future direction in this sphere.

Projects

6.18 The Department of Post is undertaking projects for computerising Post Office Counters at the General Post Offices in Dhaka (Bangladesh), Yangon (Myanmar) and Kathmandu (Nepal) with funds provided by the Universal Postal Union (UPU). These activities are being taken up by the UPU through India Post in recognition of its capabilities in the area of computerisation and software development.

6.19 The projects would be completed in three phases, the first phase relates to site survey and system study. During the month of January, 2004, three delegations from India Post comprising four members each visited Myanmar, Bangladesh and Nepal respectively. The first

phase of the projects has been completed with the system study and site survey for the projects. The second phase, relating to purchase of hardware for the projects, is on.

Continuous testing of International Postal Service Quality

6.20 The Universal Postal Union has introduced the continuous testing of transmission times for international priority letter-post items. This method has been developed in order to provide postal administrations with a simple, effective tool for measuring international quality of service. In this, test letters are posted and delivered to private addresses of test participants as an end-to-end test. The test letters are posted continuously over six days in a week to participants located in cities in order to achieve a simple geographical distribution. The data on posting and delivery are processed separately and transmitted through the Internet through a neutral and independent body (Universal Postal Union's International Bureau) to check and produce the results.

6.21 India Post has decided to participate in the continuous testing since February, 2004 and is currently testing letters with France, Maldives and Nepal.

International Traffic

6.22. The traffic of international EMS is reflected in Table 4.

TABLE 4 INTERNATIONAL SPEED POST – EMS TRAFFIC			
	2002	2003	Increase/Decrease (in %age)
1. Inward Articles	357525	372655	(+)4.23%
2. Outward Articles	498880	576418	(+)15.54%

Letter Mail

6.23 During the year, Weight of Letter Mail – Inward and Outward International has shown a decline of 6.65% and 6.48% respectively, as reflected in Table 5.

Letter Writing Competition

6.26 33rd UPU Letter Writing Competition was held on 04th January, 2004 throughout the country. Results of the competition were declared in the month of March, 2004 and the best national entry was

तालिका-5 पत्र, पोस्टकार्ड और अन्य वस्तुएं (मिलियन किलोग्राम में)			
	2002-03	2003-04	वृद्धि/कमी (% में)
1. आवक डाक वस्तुएं	3.46	3.23	(-) 6.65%
2. जावक डाक वस्तुएं	3.24	3.03	(-)6.48%

6.24 वर्ष 2003-04 के दौरान विदेशी परियात के आवक पार्सलों में 18.75% की कमी आई है, जबकि जावक पार्सलों में 24.66% की वृद्धि दर्ज की गई है जैसा कि तालिका-6 में दर्शाया गया है।

तालिका-6 विदेशी पार्सल परियात			
	2002-03	2003-04	वृद्धि/कमी (% में)
1. आवक डाक वस्तुएं	245942	199833	(-) 18.75%
2. जावक डाक वस्तुएं	86733	108118	(+)24.66%

मनीआर्डर

6.25 वर्ष 2003-04 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मनीआर्डर का परियात तालिका-7 में दर्शाया गया है।

तालिका-7 विदेश मनीआर्डर			
	2002	2003	वृद्धि/कमी (% में)
1. मनीआर्डर परियात	47277	42173	(-) 10.80%
2. पारेषित मनीआर्डरों का मूल्य(मिलियन रुपयों में)	233.32	241.82	(+)3.64%

घोषित किए गए तथा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय प्रविष्टि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचारार्थ यू पी यू को अग्रेषित किया गया। युवा लोगों के लिए यू पी यू और सार्क द्वारा आयोजित पत्र लेखन प्रतियोगिता का उद्देश्य, रचना में उनकी योग्यता का विकास करना है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को सुदृढ़ करने में योगदान देना है।

विदेशों से निवल प्राप्तियां

6.27 विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रचालनों पर टर्मिनल शुल्क, ट्रांजिट प्रभारों आदि के मद में विदेशी मुद्रा के रूप में 312 मिलियन रुपये प्राप्त किए।

TABLE 5
LETTERS, POSTCARDS AND OTHER ARTICLES

(In Million Kg.)

	2002-2003	2003-2004	Increase/Decrease (in %age)
1. Inward Articles	3.46	3.23	(-) 6.65%
2. Outward Articles	3.24	3.03	(-) 6.48%

6.24 During the year 2003-2004, foreign traffic of Inward Parcels decreased by 18.75% while Outward

Parcels has registered an increase of 24.66%, as reflected in Table 6.

TABLE 6
FOREIGN PARCEL TRAFFIC

	2002-2003	2003-2004	Increase/Decrease (in %age)
1. Inward Articles	245942	199833	(-) 18.75%
2. Outward Articles	86733	108118	(+)24.66%

Money Order

6.25 The traffic of international money orders for the year 2003-2004 is reflected in Table 7.

TABLE 7
FOREIGN MONEY ORDERS

	2002	2003	Increase/Decrease (in %age)
1. Money Order Traffic	47277	42173	(-) 10.80%
2. Value of Money Orders Transmitted(Rs. in Million)	233.32	241.82	(+)3.64%

forwarded to UPU for their consideration at the international level. The purpose of the letter writing competitions conducted by UPU and SAARC for young people is to develop their ability in composition and to contribute to the strengthening of international relations.

Net Receipts from Foreign Countries

6.27 The Department received Rs. 312 Million in foreign exchange on account of terminal dues, transit charges, etc. on International Mail Operations.

अध्याय 7

प्रौद्योगिकी

प्रस्तावना

7.1 भारतीय डाक जो अपने प्रचालन के 150वें वर्ष में प्रवेश कर चुकी है, देश का सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक विश्वसनीय सेवा तंत्र है। दूरसंचार क्रांति के दौर में भी 1,55,669 डाकघरों का तंत्र संचार के क्षेत्र में देश की आधारशिला है। तथापि, दूरसंचार क्रांति के परिप्रेक्ष्य में भारतीय डाक को अपनी सेवाओं को पुनर्निर्धारित तथा विभिन्न प्रीमियम सेवाओं को प्रारंभ करना पड़ा। अतएव, नवें दशक के प्रथम वर्षों के दौरान विभाग ने ग्राहक अनुकूल वातावरण तैयार करने एवं ग्राहकों को एकल खिड़की सेवा प्रदान करने के लिए डाकघरों एवं मेल आफिसों (एगोनोमिक्स सुधारने) के आधुनिकीकरण एवं बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों (एम पी सी एम) की स्थापना करके कम्प्यूटरीकरण प्रारंभ किया।

7.2 विभाग, 10वीं योजना के दौरान अपने सभी प्रधान डाकघरों एवं लगभग 8000 प्रमुख उप डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण करवाने की आशा करता है। विभाग दसवीं योजना के अंत तक, सर्किल प्रशासनिक कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, डिवीजनल कार्यालयों एवं लेखा कार्यालयों के अतिरिक्त सभी प्रधान डाकघरों तथा प्रमुख उप डाकघरों को सूत्रबद्ध करने में सक्षम होगा। इससे भारतीय डाक विभाग शहरी एवं ग्रामीण उपभोक्ताओं को, समग्र रूप से, नेटवर्क संचालित सेवाएं प्रदान करने में समर्थ होगा।

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

7.3 भारतीय डाक ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पीसी आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें (एमपीसीएम) लगाकर अपने डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण करना प्रारंभ किया। एमपीसीएम ने डाकघरों में पंजीकरण, धनादेश, पार्सल, स्पीड पोस्ट, डाक जीवन बीमा एवं बचत बैंक जैसे सभी काउंटर पर होने वाले लेन-देनों को एकीकृत करके ग्राहकों को एकल खिड़की सेवा प्रदान की है। एम पी सी एम के प्रति सकारात्मक रवैये ने भारतीय डाक को नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 506 प्रधान डाकघरों एवं 1266 विभागीय उप-डाकघरों को एमपीसीएम उपलब्ध करवाने के लिए प्रेरित किया। फ्रंट ऑफिस प्रचालनों के

कम्प्यूटरीकरण में सफलता प्राप्त करने के बाद ध्यान बैंक ऑफिस कम्प्यूटरीकरण पर केन्द्रित हुआ तथा लेखा, नकदी एवं डाक वितरण संबंधी कार्यों का भी कम्प्यूटरीकरण कर दिया गया। भारतीय डाक अब दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान सभी प्रधान डाकघरों एवं बड़े उप डाकघरों में अपने प्रचालनों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। अतएव, वर्ष 2003-04 के दौरान 26 प्रधान डाकघरों, तीन सर्किल कार्यालयों, लेखानिदेशक के 19 कार्यालयों और 31 क्षेत्रीय कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया। प्रौद्योगिकी डिवीजन ने, इन कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करने के अतिरिक्त, योजना अवधि के दौरान निर्धारित वास्तविक एवं वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, वर्ष के दौरान एक योजना तैयार की। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र, दूरसंचार विभाग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के आईटी विशेषज्ञों से युक्त प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की सलाह से मार्गदर्शन प्राप्त करके, भारतीय डाक अपने सभी 842 प्रधान डाकघरों एवं लगभग 8000 प्रमुख उप डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण की योजना बना रहा है तथा दसवीं योजना की समाप्ति तक इन कार्यालयों को जोड़ते हुए एक वास्तविक निजी नेटवर्क सृजित कर दिया जाएगा। इसके अलावा, भारतीय डाक अपनी सेवाओं के परिणाम को एकीकृत एवं समेकित करने के लिए एक "एन्टरप्राइज डाटा वेयरहाउस" (आंकड़ा केन्द्र) स्थापित करने के लक्ष्य भी रखती है। इससे भारतीय डाक को नई नेटवर्क सेवाएं प्रारंभ करने में मदद मिलगी तथा आगामी चुनौतियों का सामना करने के लिए मौजूदा सेवाओं को बल मिलेगा।

7.4 भारतीय डाक के मैसूर स्थित डाक प्रशिक्षण केन्द्र में एक आधुनिकतम सॉफ्टवेयर विकास केन्द्र है जो डाकघरों हेतु विभिन्न प्रायोगिक सॉफ्टवेयर विकसित करने में संलिप्त है। केन्द्र ने बचत बैंक के अतिरिक्त सभी डाक प्रचालनों के कम्प्यूटरीकरण में सक्षम एक समग्र सॉफ्टवेयर पैकेज-मेघदूत सफलतापूर्वक विकसित किया। यह पैकेज काउंटर प्रचालनों को बैंक ऑफिस प्रचालनों से जोड़ता है तथा ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए डाकघरों को सक्षम बनाता है। प्रौद्योगिकी डिवीजन ने विभिन्न डिवीजनों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वर्ष 2003-04 के दौरान चेन्नई, कोलकाता एवं हैदराबाद में भी तीन और सॉफ्टवेयर विकास केन्द्र स्थापित किए।

Chapter 7

TECHNOLOGY

Introduction

7.1 India Post, in its 150th year of operation, remains the largest and most reliable service network in the country. The 1,55,669 Post Offices Network forms the communication backbone of the country even in the era of telecommunication revolution. However, India Post had to redesign its services and introduce various premium services in the wake of Telecommunication revolution. Thus, during the early nineties, the Department initiated computerization by installing Multi Purpose Counter Machines (MPCMs) and modernization of Post Offices and Mail Offices (improving ergonomics) in order to provide a single window service to customers and to create a customer-friendly environment.

7.2 During the 10th Plan, the Department expects to computerize all its Head Post Offices and around 8,000 major Sub Post Offices. By the end of the 10th Plan, the Department would be able to link all the Head Post Offices and the major Sub Post Offices besides the Circle Administrative Offices, Regional Offices, Divisional Offices and Accounts Offices. This will enable India Post to offer network-driven services to urban and rural customers alike.

Computerisation of Post Offices

7.3 India Post initiated its computerisation of Post Offices by introducing PC Based Multi Purpose Counter Machines (MPCMs) during the 8th Five Year Plan. MPCMs provided single-window service to customers integrating all the counter transactions such as Registration, Money Orders, Parcels, Speed Post, Postal Life Insurance and Savings Bank in a Post Office. The positive response to MPCMs prompted India Post to provide MPCMs to 506 Head Post Offices and 1266 Departmental Sub Post Offices by the end of 9th Five Year Plan. Having tasted success in computerizing the

front office operations, the focus shifted to back office computerization and the work related to accounts, treasury and mail delivery were also computerized. India Post is now on the move to computerize its operations in all the Head Post Offices and large Sub Post Offices during the 10th Five Year Plan (2002-07). Thus, the year 2003-04 witnessed computerization of 26 Head Post Offices, 3 Circle Offices, 19 Offices of Director of Accounts and 31 Regional Offices. Besides computerizing these offices, Technology Division prepared a roadmap during the year to achieve the set physical and financial targets during the plan period. Guided by the advice of Standing Committee on Technology comprising IT experts from Indian Institute of Technology, National Informatics Centre, Department of Telecommunications and Department of Electronics, India Post is planning to computerize all its 842 Head Post Offices and around 8,000 major Sub Post Offices and create a virtual private network linking these offices by the end of 10th Plan. Further, India Post also aims to set up an Enterprise Data Warehouse (Data Centre) to consolidate and integrate the multitude of services. This will enable India Post to introduce new network-enabled services and add value to the existing services to meet the challenges ahead.

7.4 India Post has a state-of-the-art Software Development Centre in Postal Training Centre at Mysore, which is engaged in developing various application softwares for the Post Offices. The Centre successfully developed 'Meghdoot' - a comprehensive software package enabling computerization of all Postal Operations, except Savings Bank. The package integrates the counter operations with back office operations and enables the Post Office to provide better service to customers. During the year 2003-04, the Technology Division set up 3 more Software Development Centres at Chennai, Kolkata and Hyderabad also to meet the needs of various Divisions.

7.5 भारतीय डाक की वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंडियापोस्ट.ऑर्ग) ग्राहकों को न केवल सेवा के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाती है बल्कि विभिन्न कार्यालयों से जारी निविदाओं के संबंध में भी जानकारी उपलब्ध करवाती है। इसके अलावा, सभी अधिकारियों को ई-मेल आई डी भी दी गई है ताकि वे इंटरनेट पर संप्रेषण कर सकें। प्रौद्योगिकी डिवीजन ने ऑनलाइन शिकायतें प्राप्त करने के लिए तथा उनके सामयिक निपटान की निगरानी करने के लिए एक वेबसाइट की स्थापना करने में जन शिकायत डिवीजन की मदद भी की है।

वी-सेट नेटवर्क के माध्यम से मनीआर्डर पारेषण

7.6 भारतीय डाक ने धनादेशों के पारेषण में लगने वाले समय को कम करने संबंधी अपने प्रयास में नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देशभर में 150 टीडीएमए (टाइम डिवीजन मल्टीपल एैसेस) उच्च गति वी एस ए टी स्टेशनों की स्थापना की है। ये 150 स्टेशन डायल अप कनेक्शनों के द्वारा 1300 से अधिक विस्तारित सैटेलाइट धनादेश (ई एस एम ओ) स्टेशनों से जुड़े हैं। सॉफ्टवेयर विकास केन्द्र मैसूर ने नेटवर्क पर धनादेशों के पारेषण हेतु अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर का विकास किया है। वी एस ए टी नेटवर्क के द्वारा देश के डाकघरों में बुक अधिकांश धनादेशों का पारेषण करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वचालित मेल प्रोसेसिंग प्रणाली

7.7 भारतीय डाक ने मेट्रो नगरों में सृजित डाक के दक्ष संवहन के लिए नौवीं योजना के दौरान चैन्नई एवं मुंबई में दो स्वचालित डाक संसाधन केन्द्रों (ए एम पी सी) की स्थापना की। इन स्वचालित इकाइयों ने बड़ी मात्रा में डाक के संवहन के क्षेत्र में क्रांति ला दी है तथा उसे सुगम बना दिया है। कलिंग, फेसिंग और कैन्सिलिंग मशीनों ने इन इकाइयों की क्षमता को बढ़ा दिया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली एवं कोलकाता में दो और ए एम पी सी की स्थापना किए जाने की योजना है।

डाकघरों का आधुनिकीकरण (एगोनोमिक्स में सुधार)

7.8 डाकघरों के कम्प्यूटरीकरण ने, निसंदेह, डाक प्रचालनों को सुगम बनाया है जिससे ग्राहक में संतोष बढ़ा है। इसके अनुरूप ही, भारतीय डाक भी नौवें दशक के प्रारंभिक वर्षों से, विशेषकर फ्रंट ऑफिसों के आधुनिकीकरण द्वारा इस दिशा में प्रयास कर रहा है। नौवीं पंचवर्षीय योजना में 1800 डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया। दसवीं योजना के दौरान सेवा की गुणवत्ता तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक एवं यांत्रिक उपकरण उपलब्ध करवाकर तथा एगोनोमिक्स में सुधार लाकर 1600 डाकघरों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। वर्ष 2003-04 के दौरान 150 डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया तथा 120 डाकघरों में यांत्रिक उपस्कर लगाए गए।

7.5 The India Post website (www.indiapost.org) not only provides product information to customers but also enables publishing of information pertaining to tenders floated in various offices. Further, email id-s have been given to all the Officers so that they can communicate over internet. Technology Division also aided the Public Grievances Division to set up a website for receiving complaints online and monitoring their timely settlement.

Money Order transmission through VSAT Network

7.6 India Post, in its endeavor to reduce the transit time for transmission of money orders, set up 150 TDMA (Time Division Multiple Access) High Speed VSAT stations across the country during the 9th Five Year Plan. These 150 stations are in turn connected to more than 1300 Extended Satellite Money Order (ESMO) stations over dial-up connections. Software Development Centre, Mysore, developed the application software for transmission of money orders over the network. Efforts are on to transmit maximum money orders booked in the Post Offices of the country through the VSAT network.

Automatic Mail Processing System

7.7 India Post set up two Automatic Mail Processing Centres (AMPCs) at Chennai and

Mumbai during the 9th Plan for efficient handling of mail generated in metros. These automated units have revolutionized and streamlined handling of large volumes of mail. Providing culling, facing and canceling machines has enhanced the capability of these units. Two more AMPCs are planned for installation during the 10th Five Year Plan at Delhi and Kolkata.

Modernisation of Post Offices (Improving Ergonomics)

7.8 Computerization of Post Offices, no doubt, streamlined the postal operations resulting in customer satisfaction. In tune with this, India Post has also been trying since early nineties, to improve the Post Office especially by modernizing the front office. 1800 Post Offices were modernized up to 9th Five Year Plan. During the 10th Plan, modernization of 1600 Post Offices will be taken up by improving ergonomics and also by providing various electronic & mechanical equipments to increase the productivity and quality of service. During the year 2003-04, 150 Post Offices were modernized and 120 Post Offices were provided with mechanical equipments.

अध्याय 8

वित्तीय सेवाएं

8.1 डाकघर बचत बैंक देश का सबसे पुराना एवं सबसे बड़ा बैंकिंग संस्थान है। यह लगभग 140 मिलियन बचत खातों का प्रचालन करता है। डाकघर बचत बैंक योजना एक एजेंसी कार्य है जो डाक विभाग द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की ओर से निष्पादित किया जाता है। वित्त मंत्रालय इस एजेंसी कार्य के लिए डाक विभाग को एक नियत दर से समय-समय पर, पारिश्रमिक देता है। पिछले वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान, विभाग ने, बचत बैंक से संबंधित विभिन्न दायित्वों के निर्वहन के लिए, पारिश्रमिक के रूप में, लगभग 17000 मिलियन रु. अर्जित किये।

वार्षिक जमा राशि 9,70,000 मिलियन रु. से अधिक है। बचत बैंक सुविधा 1,54,000 डाकघरों के नेटवर्क की मार्फत उपलब्ध करवाई जाती है जो देश में सभी बैंकिंग इकाइयों को मिलाने के बाद प्राप्त होने वाली संख्या से भी दुगुनी है। आठ सेवाओं को देशभर में डाकघरों द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। डाकघर बचत बैंक के तहत अनेक योजनाएं हैं इनमें बचत खाता योजना, आवर्ती जमा योजना, सावधि जमा योजना, मासिक आय योजना, लोक भविष्य निधि योजना, किसान विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र एवं वरिष्ठ नागरिक योजना 2004 है। डाकघरों की सभी राष्ट्रीय बचत योजनाओं में बकाया राशि 3,750,000 मिलियन रु. से अधिक है। 6 बचत योजनाओं का ब्योरा तालिका-8 में दिया गया है।

8.2 डाकघर बचत बैंक की ग्राहक संख्या 140 मिलियन है तथा

तालिका-8 बचत योजना: ब्योरा (31.3.2004 को)		
योजना का नाम	खातों की संख्या	जमा की गई कुल राशि (मिलियन रु. में)
बचत खाते (बचत बैंक)	54742492	133,670
आवर्ती जमा खाते	60715388	339,630
सावधि जमा खाते	5776513	240,670
मासिक आय योजना खाते	16987828	1,133,860
राष्ट्रीय बचत पत्र खाते (87 एवं 92)	895838	41,330
लोक भविष्य निधि खाते	1730008	122,670

डाक विभाग द्वारा प्रारंभ किये गए नये उत्पाद एवं सेवाएं

8.3 डाक विभाग ने, हाल ही के वर्षों में, अपनी पहुंच तथा प्रेषण सुविधा को बढ़ाने तथा डाक विभाग द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली सेवाओं और वित्तीय उत्पादों का विधिकरण करने में अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाने का प्रयास किया है। प्रौद्योगिकी के प्रयोग तथा नेटवर्क के प्रगामी कम्प्यूटरीकरण से अधिक मूल्यवर्धित सेवा उपलब्ध करवाने की विभाग की क्षमता बढ़ी है। विभाग द्वारा फिलहाल प्रस्तावित कुछ सेवाओं का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

म्युचुअल फंड एवं बॉण्ड्स

8.4 म्युचुअल फंड उद्योग ने देश में बहुत प्रगति की है। इसकी परिसंपत्तियाँ लगभग 1,550,000 मिलियन रु. हैं। यह उद्योग विभिन्न एसेट मैनेजमेंट कम्पनियों के प्रबंधन के तहत है। भारतीय डाक ने चयनित डाकघरों की मार्फत बड़े पैमाने पर म्युचुअल फंड के कारोबार में प्रवेश किया है। फरवरी 2001 से 250 से अधिक डाकघरों का बढ़ता हुआ नेटवर्क चुनिंदा म्युचुअलफंड एवं बॉण्ड्स (प्रिंसिपल/पुडेंशियल-आईसीआईसीआई/ एसबीआई/ आईसीआईसीआई कैपिटल/आईडीबीआई/ आरबीआई बॉण्ड्स) वितरित कर रहा है। म्युचुअल फंड उद्योग वित्तीय सेवाओं में एक नया क्षेत्र है। इसलिए, भारतीय डाक, एक रिटेलर के

Chapter 8

FINANCIAL SERVICES

8.1 The Post Office Savings Bank is the oldest and largest banking institution in the country. It operates about 140 Million Savings Accounts. The Post Office Savings Bank Scheme is an agency function performed by the Department of Posts on behalf of the Ministry of Finance, Government of India. The Ministry of Finance remunerates Department of Posts for this agency work at a rate fixed from time-to-time. During the last financial year 2003-04, the Department earned approximately Rs. 17000 Millions as remuneration for discharging various responsibilities relating to the Savings Bank.

8.2 Post Office Savings Bank has a customer base of 140 Million account holders with annual deposits

exceeding Rs. 9,70,000 Million. Savings Bank facilities are provided through a network of 1,54,000 Post Offices, which is double the size of all banks outlets in the country, put together. Eight products are retailed from the Post Offices across the country. There are also a number of Schemes covered under the Post Office Savings Bank and these include Savings Account Schemes, Recurring Deposit Schemes, Time Deposit Schemes, Monthly Income Schemes, Public Provident Fund Schemes, Kisan Vikas Patras, National Savings Certificates and the Senior Citizen Scheme 2004. The outstanding balance under all national savings schemes in Post Offices is over Rs. 3,750,000 Million. Profile of the six Savings Schemes are given in Table 8 :-

TABLE 8
SAVINGS SCHEME :PROFILE (AS ON 31.03.2004)

Name of Scheme	Number of Accounts	Total Amount Deposited (Rs. in Million)
Saving Accounts(SB)	54,742,492	133,670
RD Accounts	60,715,388	339,630
TD Accounts	57,765,13	240,670
MIS Accounts	16,987,828	1,133,860
NSS Accounts(87 & 92)	895,838	41,330
PPF Accounts	1,730,008	122,670

New Products and Services introduced by Department of Posts

8.3 In recent years, the Department of Posts has tried to leverage its reach and remittance facility as well as the credibility it enjoys to diversify the range of financial products and services that the Department of Posts can offer to its customers. With the induction of technology and progressive computerisation of the network, the Department's capability to provide more value added services has increased. Details of some of the services being presently offered by the

Department are given below :-

Mutual Funds & Bonds

8.4 The Mutual Funds industry has made rapid strides in the country, with assets worth nearly Rs. 1,550,000 Million this industry is under the management of various Assets Management Companies. India Post has entered into the business of retailing mutual funds through select offices. Since February, 2001, a growing network of over 250 Post Offices are distributing select Mutual Funds and Bonds (Principal/Prudential-ICICI/

रूप में कमीशन एवं ट्रेल कमीशन की मार्फत उच्चतर राजस्व अंश प्राप्त करने की आशा कर रहा है। आज, भारतीय डाक की वित्तीय सेवाओं में आरबीआई इंडिया रिलीफ बॉन्ड, आईडीबीआई फ्लैक्सी बॉन्ड्स एवं आईसीआईसीआई पेंशन निधि आदि जैसे बड़ी मात्रा में अन्य संगत वित्तीय उत्पाद हैं। विभाग ने, हाल ही में, चयनित डाकघरों से यूटीआई एसएट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जोकि देश में म्युचुअल फंड बाजार की सबसे बड़ी कंपनी है, के साथ, प्रायोगिक आधार पर, अपनी पांच म्युचुअल फंड योजनाओं की रिटेलिंग के लिए एक समझौता किया है। डाकघर नेटवर्क द्वारा अभी तक 50 मिलियन रु. से अधिक का कारोबार किया गया है। इस सेवा से देश के पूंजी बाजार की पहुंच को बढ़ाने में मदद मिली है तथा इससे आम आदमी को बाजार आधारित निवेश विकल्पों के लिए सरल पहुंच उपलब्ध होती है।

इलैक्ट्रॉनिक निधि अंतरण

8.5 बैंकों द्वारा निगमित क्षेत्र एवं पूंजी बाजार की ओर से समग्र अंतरण (यूटीआई/ आईडीबीआई/एचडीएफसी) को पूर्णतया सुगम बनाने के लिए, विभाग के वीएसएटी नेटवर्क को बढ़ाने हेतु अक्टूबर 2001 में, इलैक्ट्रॉनिक धन अंतरण हेतु सुविधा प्रदान की गई है। बैंक इस सुविधा को उस स्थान पर निधियों को अंतरित करने में प्रयोग करते हैं जहां वे मौजूद नहीं हैं।

वारंट भुगतान

8.6 वारंट भुगतान योजना जनवरी 2002 में प्रारंभ की गई। उसने देश के पूंजी बाजार हेतु इस महत्वपूर्ण सेवा को चलाने के लिए विभाग की क्षमता स्थापित करने के लिए डाक नेटवर्क की मार्फत 1000 मिलियन रु. से अधिक राशि के यूटीआई तथा सिटीबैंक के 73000 से अधिक डिविडेड वारंट के भुनाने को सुगम बनाया है।

इलेक्ट्रॉनिक्स समाशोधन सेवा

8.7 डाक विभाग ने मुंबई शहर में 70 डाकघरों की मार्फत 9 अगस्त, 2003 से प्रायोगिक आधार पर इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा (ईसीएस) प्रारंभ की है। मासिक आय योजना (एसआईएस) के तहत, जमाकर्ता मासिक आय योजना खाते से स्वचालित ब्याज अंतरण की सुविधा प्राप्त करके उसे इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी निर्धारित बैंक के बचत खाते में आरबीआई समाशोधन केन्द्र की मार्फत देय तारीख तक क्रेडिट करने की सुविधा प्राप्त कर सकता है। इस सुविधा को चुनने वाले ग्राहक पर प्रति लेन-देन 20 रु. का मामूली प्रभार लगाया जाता है।

जैसा कि देश के विभिन्न भागों से ग्राहकों की बढ़ती मांग है कि विभाग मुंबई के अलावा 46 अन्य शहरों, जहां आरबीआई-ईएफटी सेवा फिलहाल उपलब्ध है, में इलैक्ट्रॉनिक समाशोधन योजना लागू करें। विभाग इस पर विचार कर रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय धन अंतरण सेवा

8.8 यह सेवा ग्राहकों को वास्तविक समय आधार पर 196 से अधिक देशों से धन प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करती है। फिलहाल यह सेवा 4500 से अधिक डाकघरों में उपलब्ध है। इस सेवा के द्वारा अप्रैल 2001 से लेकर 125 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इसके द्वारा अप्रैल 2003 से मार्च 2004 के दौरान 72 मिलियन अमरीकी डॉलर का भुगतान प्राप्त किया गया है तथा इससे 58.9 मिलियन रु. का राजस्व सृजित हुआ है।

8.9 वित्तीय सेवाओं के क्षेत्र में विभाग का ध्यान ऐसी सेवाएं प्रदान करने पर है जो नेटवर्क की वृहत पहुंच का विस्तार करें और ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें ताकि ऐसी सेवाओं के लिए डाकघर धीरे-धीरे एकल विक्रय केन्द्र बन जाएं।

8.10 सन् 1884 में प्रारंभ की गई डाक जीवन बीमा योजना (पीएलआई) सरकारी कर्मचारियों के लिए सबसे पुरानी डाक जीवन बीमा योजना है। प्रारंभ में केवल डाक कर्मचारियों के लिए ही शुरू की गई, यह स्कीम आज केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के सिविल तथा मिलिट्री कर्मिकों, स्थानीय निकायों, सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों, विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनेकों स्वायत्त तथा वित्त संस्थानों और केन्द्र व राज्यों के सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को सेवा प्रदान कर रही है। एक अभिनव परिवर्तन के तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लाभ के लिए वर्ष 1995 में ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजना (आरपीएलआई) शुरू की गई है।

8.11 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा निधि की स्थिति और वर्ष 2003-2004 के दौरान प्राप्त कारोबार की स्थिति नीचे तालिका-9 में दी गई है:-

8.12 डाक जीवन बीमा निम्नलिखित प्रकार की पालिसियों की सुविधा प्रदान करती है:-

- आजीवन बीमा (सुरक्षा)
- परिवर्तनीय आजीवन बीमा (सुविधा)
- बंदोबस्ती बीमा (संतोष)
- 15 वर्ष तथा 20 वर्ष की प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा (सुमंगल)
- संयुक्त जीवन बंदोबस्ती बीमा (युगल सुरक्षा)

SBI/ICICI Capital/IDBI/RBI Bonds). Mutual Fund industry is a new growth area in financial services. Therefore, as a retailer, India Post is expected to gain a higher revenue share through commissions and trail commissions. Today the financial services portfolio of India Post has a large number of other relevant financial products like RBI India Relief Bonds, IDBI Flexi Bonds and ICICI Pension Fund, etc. The Department has also recently entered into a tie up with the UTI Asset Management Company Limited, which is the largest player in the Mutual Fund market in the country, to retail its five mutual fund schemes, on a pilot basis, from select Post Offices. Till date business worth over Rs. 50 Million has been retailed by the post office network. This service has helped to extend the reach of the capital market of the country and provides the common man easy access to market based investment options.

Electronic Fund Transfer

8.5 A facility for Electronic Fund Transfer was launched in October, 2001, leveraging the VSAT network of the Department to facilitate end-to-end fund transfers by Banks (UTI/IDBI/HDFC) on behalf of the corporate sector as well as the Capital Market. Banks use this facility to transfer funds to locations where they do not have a presence.

Warrant Payment

8.6 The Warrant Payment Scheme was launched in January, 2002. It has facilitated redemption of over 73,000 dividend warrants of UTI and Citibank worth more than Rs. 1,000 Million through the postal network, establishing the ability of the Department to undertake this critical service, for the country's Capital Market.

Electronic Clearance Service (ECS)

8.7 The Department of Posts has introduced Electronic Clearance Service (ECS), on a pilot basis, in Mumbai City from 9th August, 2003 through 70 Post Offices. The Electronic Clearance Service is being offered in connection with payment of interest under the Monthly Income Scheme (MIS). The depositor can have the facility of automatically transferring interest from the MIS account and crediting it into the SB account at any designated bank electronically, by due date, through the RBI Clearing House. A nominal charge of Rs. 20/- per transaction is levied on the customers opting for this facility. As there is a growing demand from customers

in different parts of the country, the Department proposes to extend the ECS scheme beyond Mumbai to 46 more cities where the RBI-EFT (Electronic Fund Transfer) facility is currently available.

International Money Transfer Service

8.8 This service provides customers the facility of receiving remittances from more than 196 countries on a real time basis. The service is currently available from more than 4500 post offices. Remittances in excess of US Dollars 125 Million have been delivered through this service since April 2001. It has brought in remittance worth 72 Million US Dollars from April 2003 to March 2004 and has generated a revenue of Rs.58.9 Million.

8.9 The focus of the Department's initiatives in the area of financial services is to provide a bouquet of services that will cater to the needs of the customer, leveraging the retailing outreach of the network, so that the Post Office gradually becomes a one-stop shop for a range of such services.

Postal Life Insurance

8.10 Postal Life Insurance (PLI), introduced in 1884, is the oldest life insurance scheme for the benefit of Government employees. Initially meant only for the Postal employees, today it caters to employees of the civil and military personnel of the central and state governments, local bodies, government aided educational institutions, universities, nationalized banks, many autonomous and financial institutions, and public sector undertakings of the central and state governments. In a major innovation, Rural Postal Life Insurance (RPLI) scheme was also introduced in 1995 for the benefit of the entire rural populace.

8.11 The status of PLI/RPLI funds as on 31.03.2004, and the business procured during the year 2003-2004 is as given in

8.12 PLI offers the following types of policies: -

- (i) Whole Life Assurance (Suraksha)
- (ii) Convertible Whole Life Assurance (Suvidha)
- (iii) Endowment Assurance (Santosh)
- (iv) Anticipated Endowment Assurance for 15 & 20 years (Sumangal)
- (v) Joint Life Endowment Assurance (Yugal Suraksha)

तालिका - 9

डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा द्वारा किया गया कार्य-निष्पादन

योजना का नाम	प्राप्त पालिसियों की संख्या	बीमित राशि (मिलियन रु. में)	क्रियाशील पालिसियों की कुल संख्या (सक्रिय)	बीमित सकल राशि (मिलियन रु. में)
डाक जीवन बीमा	276880	28466.6	2208683	158176.1
ग्रामीण डाक जीवन बीमा	1083152	59499.8	2666485	123851.1

8.13 ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत पहली चार योजना समान हैं और एक अतिरिक्त योजना "10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा" भी उपलब्ध है। उनका व्यापारिक (ट्रेड) नाम निम्नानुसार है:

- (i) आजीवन बीमा (ग्राम सुरक्षा)
- (ii) परिवर्तनीय आजीवन बीमा (ग्राम सुविधा)

(iii) बंदोबस्ती बीमा (ग्राम संतोष)

(iv) 15 वर्ष तथा 20 वर्ष का प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा (ग्राम सुमंगल)

(v) 10 वर्षीय ग्रामीण डाक जीवन बीमा (ग्राम प्रिय)

8.14 अंत में डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा योजनाओं को चालू रखने के लिए बोनस निम्न दरों पर घोषित किया गया है:

तालिका-10

बोनस की दर

प्रकार	प्रति 1000/-रु. की बीमित राशि पर बोनस की दर		
	आजीवन बीमा	बंदोबस्ती बीमा	प्रत्याशित बंदोबस्ती बीमा
31.3.2002 की स्थिति के अनुसार डाक जीवन बीमा	95	77	75
31.3.2000 की स्थिति के अनुसार ग्रामीण डाक जीवन बीमा	60	50	50

8.15 वर्ष 2003-2004 के दौरान डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के संबंध में निपटाए गए दावे इस प्रकार हैं:

तालिका-11

निपटाए गए दावे

विवरण	डाक जीवन बीमा	ग्रामीण डाक जीवन बीमा
दावों की संख्या	108662	9231
भुगतान की गई राशि (मिलियन रु. में)	3018.4	149.5

8.16 01.04.1992 से अतिरिक्त विभागीय एजेंट समूह बीमा योजना प्रारंभ की गई थी और इसके लाभार्थी के वेतन से 10/-रु. का मासिक शुल्क काटा जाता है। 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार, इस योजना के 2,57,695 सदस्य हैं। इसके लाभार्थी की

मृत्यु होने पर, ब्याज के साथ बचत खाते में अभिवृद्धि के अतिरिक्त बीमा निधि से 10,000/-रु. की राशि का भुगतान किया जाता है। 31.3.2004 की स्थिति के अनुसार इस योजना में 530.1 मिलियन रु. शेष हैं।-

**TABLE 9
PERFORMANCE OF PLI/RPLI**

Name of Plan	No of Policies Procured	Sum Assured (Rs. in Million)	Aggregate No. of Active Policies	Aggregate Sum Assured (Rs. in Million)
PLI	276,880	28,466.6	2,208,683	158,176.1
RPLI	1,083,152	59,499.8	2,666,485	123,851.1

8.13 Under RPLI, there are first four common plans and one additional plan "10 year RPLI". Their trade names are as indicated below: -

- (i) Whole Life Assurance (Gram Suraksha)
- (ii) Convertible Whole Life Assurance (Gram Suvidha)
- (iii) Endowment Assurance (Gram Santosh)

(iv) Anticipated Endowment Assurance for 15 & 20 years (Gram Sumangal)

(v) 10 year RPLI (Gram Priya)

8.14 The bonus for continuing PLI and RPLI policies were last declared at the following rates :-

**TABLE 10
RATE OF BONUS**

Type	Rates of bonus per Rupees 1000/- sum assured		
	Whole Life Assurance	Endowment Assurance	Anticipated Assurance
PLI as on 31.03.2002	95	77	75
RPLI as on 31.03.2000	60	50	50

8.15 Details of claim under PLI and RPLI policies, settled during the year 2003-2004, are as given below: -

**TABLE 11
CLAIMS SETTLED**

Details	PLI	RPLI
No. of Claims	108,662	9,231
Amount Paid (Rs. in Million)	3,018.4	149.5

8.16 An Extra Departmental Agents Group Insurance Scheme was introduced with effect from 01.04.1992 and a monthly subscription of Rupees 10/- is deducted from the salary of its beneficiaries. As on 31.03.2004 there were 257,695 members under

this scheme. In the event of death of its beneficiary, an amount of Rupees 10,000/- is paid out of the insurance fund, in addition to accretion in the savings and the interest on it. On 31.03.04 the balance in this scheme was Rs. 530.1 Million.

अध्याय 9

वित्तीय प्रबंधन

परिचय

9.1 डाक विभाग जनता को डाकघरों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क द्वारा विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराता है। पूर्णतया डाक सुविधाएं प्रदान करने के अतिरिक्त डाकघर भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य संगठनों की ओर से बचत बैंक, पेंशन का भुगतान, बचत प्रमाण पत्रों की बिक्री आदि जैसी एजेन्सी कार्य भी करते हैं।

9.2 विभाग ने 42,569.29 मिलियन रु. का कुल राजस्व अर्जित किया जिसमें से डाक सेवाओं से 23,687.27 मिलियन रु. प्राप्त हुए, जबकि अन्य मंत्रालयों/विभागों से एजेंसी प्रभार के रूप में प्राप्त राशि

1,039.09 मिलियन रुपये है। (देखें तालिका-13)। बाद की राशि को "वसूलियों" के अंतर्गत दर्शाया गया है। बचत बैंक तथा बचत पत्रों से 17,625 मिलियन रुपये का पारिश्रमिक प्राप्त हुआ। पिछले वर्ष में 54,761.5 मिलियन रुपये के व्यय की तुलना में वर्ष 2003-04 में कुल कार्यकारी-व्यय 57,360.61 मिलियन रुपये है (लगभग 4.75% की वृद्धि)। व्यय में बढ़ोतरी मुख्य रूप से बढ़े हुए महंगाई भत्ते/महंगाई राहत तथा संबंधित पेंशनरी प्रभार के भुगतान के कारण है। पिछले पांच वर्षों की भांति, इस वर्ष भी विभाग वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीलिंग के अंदर व्यय को रखने में सफल रहा, ऐसा कड़े बजटीय नियंत्रण और व्यय की सूक्ष्म मानीटरिंग के कारण संभव हुआ। अतः वेतन और पेंशनरी प्रभार में वृद्धि के बावजूद विभाग का घाटा 13,752.23 मिलियन रुपये आंका गया है।

Chapter 9

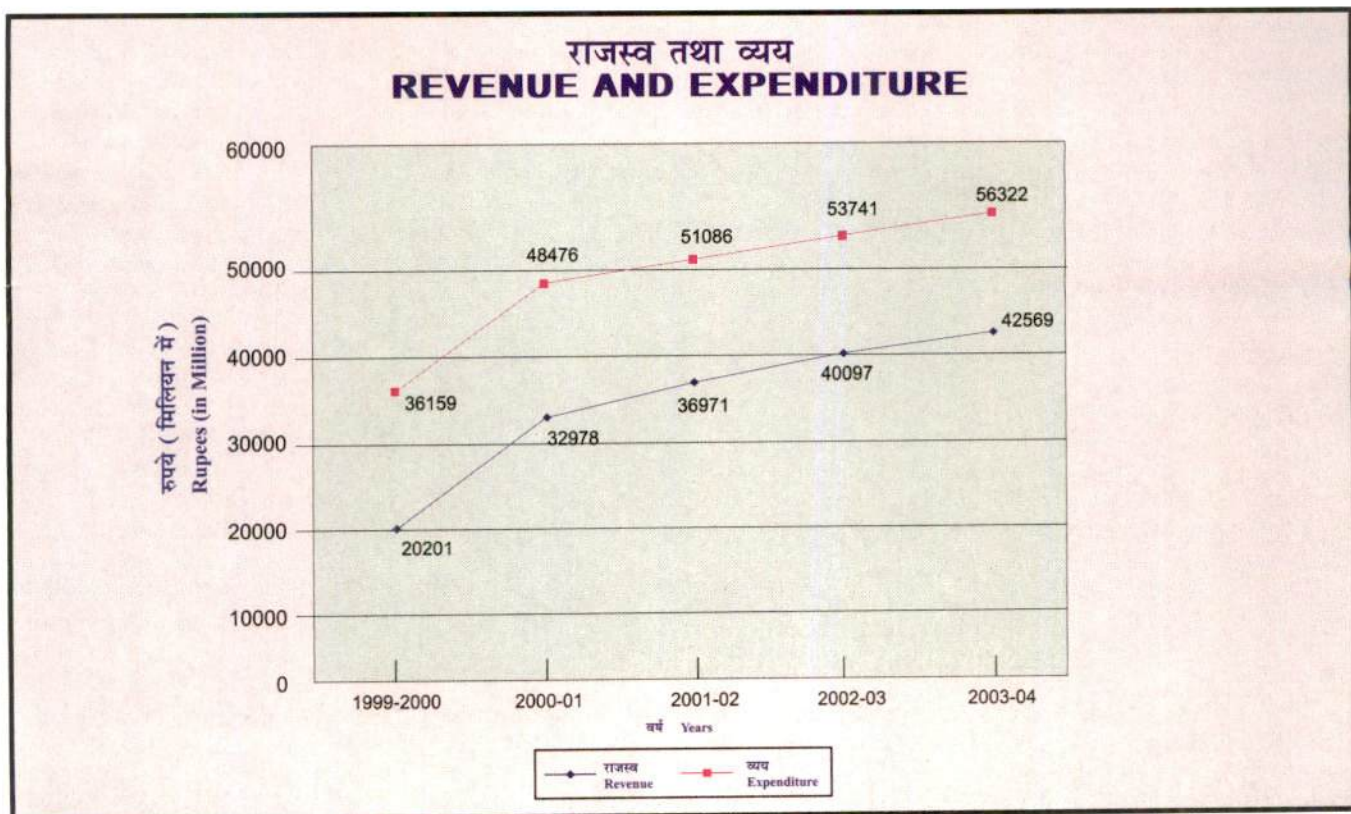
FINANCIAL SERVICES

Introduction

9.1 The Department of Post provides services to the public through a large nation wide network of Post Offices. Besides providing purely postal services, Post Offices perform agency functions like Savings Bank, Payment of Pension, Sale of Cash Certificates etc. on behalf of other Ministries/Departments of the Government of India and other organisations.

9.2 The Department earned a total revenue of Rs. 42,569.29 Million, of which Rs. 23,687.27 Million came from Postal Services while the amount received from other Ministries/Departments as Agency charges was Rs. 1,039.09 Million (see table 13). The latter amount

has been reflected under "recoveries". Remuneration from Savings Bank and Savings Certificates was Rs. 17,625 Million. Gross working expenditure for the year 2003-2004 was Rs. 57,360.61 Million against the previous year's expenditure of Rs. 54,761.5 Million (i.e. an increase of about 4.75%). This increase in expenditure was mainly due to enhanced payment of Dearness Allowance/Dearness Relief and related Pensionary charges. In keeping with the trend of the last five years, this year also the Department was able to keep the expenditure within the ceiling fixed by the Ministry of Finance through strict budgetary control and close monitoring of expenditure. Therefore, despite increase in salaries and Pensionary charges, the deficit of the Department was pegged at Rs. 13,752.23 Million.



तालिका-12
राजस्व और व्यय (वर्ष 2003-04 के लिए)

(रुपये मिलियन में)

व्योरा	वास्तविक आंकड़े 2002-03	वास्तविक आंकड़े 2003-04	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि (+)/ प्रतिशत कमी (-)
राजस्व			
डाक-टिकटों की बिक्री	9,810.4	8,946.62	(-)8.80%
नकदी के रूप में प्राप्त डाक शुल्क	10,173.4	11,559.31	13.62%
मनीआर्डर और भारतीय पोस्टल आर्डर आदि पर कमीशन	3,011.0	3,181.34	5.66%
बचत बैंक/बचत पत्र कार्य के लिए पारिश्रमिक	15,770.0	17,625.00	11.76%
* अन्य प्राप्तियां	1,331.7	1,257.02	(-)5.61%
कुल राजस्व	40,096.5	42,569.29	6.17%
व्यय			
सामान्य प्रशासन	3,205.0	3,306.95	3.18%
प्रचालन	36,205.3	37,838.19	4.51%
एजेंसी सेवाएं	1,948.3	1,967.95	1.01%
** अन्य	13,402.9	14,247.52	6.30%
कुल सकल व्यय	54,761.5	57,360.61	4.75%
घटाएं वसूलियां	1,021.0	1,039.09	1.77%
निवल व्यय	53,740.5	56,321.52	4.80%
घाटा (निवल व्यय-राजस्व)	13,644.0	13,752.23	0.79%

* इसमें डाक विभाग द्वारा बिक्री किए गए पासपोर्ट आवेदन फार्म, पासपोर्ट शुल्क टिकट एवं केन्द्रीय भर्ती फीस टिकट के सेवा प्रभार तथा अन्य डाक प्रशासनों आदि से हुई आय शामिल है।

** इसमें मजदूरी, कार्यालय व्यय, समयोपरि भत्ता, किराया एवं कर, व्यावसायिक सेवाएं, अनुरक्षण, स्टाफ को सुविधाएं, पेंशन संबंधी प्रभार, आपूर्ति और सामग्री, यांत्रिक एवं उपस्कर तथा अन्य प्रशासनिक व्यय आदि शामिल हैं।

TABLE 12
REVENUE AND EXPENDITURE
(FOR THE YEAR 2003-2004)

(Rs. in Million)

Particulars	Actuals 2002-03	Actuals 2003-04	%age Inc(+)/Dec(-) over previous year.
Revenue			
Sale of Stamps	9,810.40	8,946.62	(-)8.80%
Postage Realised in Cash	10,173.40	11,559.31	13.62%
Commission on Money Orders and Indian Postal Orders etc.	3,011.00	3,181.34	5.66%
Remuneration for Saving Bank/ Saving Certificates Work	15,770.00	17,625.00	11.76%
*Other Receipts	1,331.70	1,257.02	(-)5.61%
Total	40,096.50	42,569.29	6.17%
Expenditure			
General Administration	3,204.98	3,306.95	3.18%
Operation	36,205.31	37,838.19	4.51%
Agency Services	1,948.31	1,967.95	1.01%
**Others	13,402.88	14,247.52	6.30%
Total Gross Expenditure	54,761.50	57,360.61	4.75%
Less Recoveries	1,021.00	1,039.09	1.77%
Net Expenditure	53,740.50	56,321.52	4.80%
Deficit (Net Expenditure-Revenue)	13,644.00	13,752.23	0.79%

* This includes service charges retained by the Department of Posts from sale of Passport Application Form, Passport Fee Stamps, Central Recruitment Fee Stamps, receipts from other Postal Administrations etc.

** This includes Wages, Office Expenses, Overtime Allowance, Rent and Taxes, Professional Services, Maintenance, Amenities to Staff, Pension charges, Supplies, Material, Machinery and Equipment and Other Administrative Expenses etc.

तालिका-13
2002-03 और 2003-04 में एजेंसी सेवाओं पर कार्यकारी-व्यय की वसूली
(मिलियन रुपये में)

क्रम सं.	लेखा शीर्ष	2002-03 वास्तविक आंकड़े	2003-04 वास्तविक आंकड़े
1.	सैनिक पेंशन	0.00	0.00
2.	कोयला खनिकों तथा ईपीएफ/परिवार पेंशन तथा विविध सेवाओं का भुगतान	37.50	42.10
3.	रेलवे पेंशन का भुगतान	187.80	111.26
4.	डाक जीवन बीमा	579.10	709.33
5.	सीमा शुल्क वसूली	34.80	72.79
6.	महिला समृद्धि योजना	0.00	0.00
7.	अंतर्राष्ट्रीय धनांतरण खातों पर कमीशन-वेस्टर्न यूनियन स्कीम	18.60	38.75
8.	संयुक्त डाक-तारघरों का टेलीग्राफ हिस्सा	139.00	36.06
9.	अन्य *	24.20	28.80
	कुल	1021.00	1039.09

* इसमें दिल्ली प्रशासन के गैर-डाक-टिकटों की बिक्री पर कमीशन, सेना डाक सेवा लेखा और अन्य सरकारी विभागों से वसूलियां आदि शामिल हैं।

9.3 विभाग की आय "वसूलियां" और "राजस्व" के रूप में होती हैं तथा वसूलियों के ब्योरे तालिका-13 में दर्शाए गए हैं। "राजस्व" में आय, डाक सामग्री की बिक्री, मनीआर्डर तथा भारतीय पोस्टल आर्डर पर कमीशन, अन्य प्रीमियम सेवाओं से प्राप्तियां, बचत बैंक तथा बचत पत्रों से प्राप्त पारिश्रमिक से होती है। डाक घाटे में क्रमिक वृद्धि की यह प्रवृत्ति तथा परिणामस्वरूप बजटीय समर्थन पर निर्भरता को विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न नई सेवाओं के माध्यम से अधिक राजस्व अर्जित करके और वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर व्यय को नियंत्रित

रखकर रोका गया है। अतः वित्तीय वर्ष 2003-04 के दौरान राजस्व प्राप्तियां तथा वसूलियों में दर्ज साराहनीय वृद्धि के कारण, कार्यकारी-व्यय में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद विभाग का घाटा पिछले वर्ष के 13,644 मिलियन रुपये की तुलना में केवल 13,752.23 मिलियन रुपये रहा जो कि पहले से मात्र 0.79% अधिक है।

9.4 वित्त मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान "कार्यकारी-व्यय" और "पूँजीगत परिव्यय" के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों का वर्ष के दौरान समुचित रूप से उपयोग कर लिया गया था। निधि उपयोग पर निरंतर तथा समय से मानीटरिंग करने के परिणामस्वरूप, अधिशेष निधि को समय पर वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित कर दिया गया था।

TABLE-13
RECOVERY OF WORKING EXPENSES ON ACCOUNT OF AGENCY
SERVICES IN 2002-03 AND 2003-04

(Rs. in Million)

Sl. Head of Account No	2002-03 Actuals	2003-04 Actuals
1. Military Pension	0.00	0.00
2. Payment of Coal Miners and EPF/Family Pension & other Misc. Services	37.50	42.10
3. Payment of Railway Pension	187.80	111.26
4. Postal Life Insurance	579.10	709.33
5. Custom Duty Realisation	34.80	72.79
6. Mahila Samridhi Yojna	0.00	0.00
7. Commission on A/c. of International Money Transfer – Western Union Scheme	18.60	38.75
8. Telegraph share of Combined Offices	139.00	36.06
9. *Others	24.20	28.80
Total	1,021.00	1,039.09

* This includes Commission on sale of Non-Postal stamps of Delhi Administration, Recoveries from Army Postal Service Accounts and other Government Departments.

9.3 The earnings of the Department are in the form of 'Recoveries' and 'Revenue' and the details of the latter are listed in Table 13. Earnings from 'Revenue' accrue from sale of postal articles, commission on Money Orders and Indian Postal Orders, receipts from other premium services, remuneration for Saving Bank and Saving Certificates work etc. This trend of gradual increase in postal deficit and the consequent dependency on budgetary support has been arrested by generating more revenue through different new services introduced

by the Department, besides containing the expenditure within the ceiling fixed by the Ministry of Finance. Therefore, in the financial year 2003-04, the deficit of the Department was only Rs. 13,752.23 Million, i.e. 0.79% more than previous year's deficit of Rs. 13,644 Million, despite an appreciable increase in Working Expenses, due to the appreciable increase registered in Revenue Receipt and Recoveries.

9.4 The funds made available by the Ministry of Finance for 'Working Expenses' and 'Capital Outlay' during the year, were appropriately utilized. Surplus funds were surrendered in time to the Ministry of Finance as a result of continuous and timely monitoring of fund utilisation.

तालिका-14
2003-2004 के दौरान अभ्यर्पित निधियां तथा बचत

(मिलियन रुपए में)

व्यय की प्रकृति	बजट प्राक्कलन	पुनः अनुमोदित अनुपूरक अनुदान	कुल	वास्तविक व्यय	अधिक (+)/ बचत (-)	अभ्यर्पित/ पुनः अनुमोदित राशि	बचत
3201-कार्यकारी-व्यय	55940.10	2127.10	58067.20	57360.61	-706.59	103.74	-602.85
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान	13.40	0.00	13.40	0.00	-13.40	13.40	0.00
कुल कार्यकारी व्यय	55953.50	2127.10	58080.60	57360.61	-719.99	117.14	-602.85
5201-पूंजीगत परिव्यय	1215.21	78.80	1294.01	483.60	-810.41	680.50	-129.91
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए प्रावधान	76.40	0.00	76.40	0.00	-76.40	76.40	0.00
कुल कार्यकारी-व्यय	1291.61	78.80	1370.41	483.60	-886.81	756.90	-129.91
कुल कार्यकारी-व्यय+ पूंजीगत व्यय	57245.11	2205.90	59451.01	57844.21	-1606.80	874.04	-732.76

पूंजीगत परिव्यय

9.5 वर्ष 2003-2004 में नियत परिसम्पत्तियों पर 489.10 मिलियन रुपए का व्यय हुआ जिसमें से 30.46% भूमि और भवनों पर और 39.31% डाक सेवाओं के यांत्रिकीकरण और आधुनिकीकरण

पर 25.37% रेल डाक वाहनों और 4.86% मेल मोटर वाहनों और अन्य पर हुआ। वर्ष के अंत में नियत परिसम्पत्तियों पर पूंजीगत मूल्य बढ़कर 11,561.50 मिलियन रुपए हो गया। वर्ष के अंत तक निवल प्रगामी नियत परिसम्पत्ति मूल्य 9,827.80 मिलियन रुपए हो गया।

TABLE 14
FUNDS SURRENDERED AND SAVINGS DURING 2003-04

(Rs. in Million)

Nature of Expenditure	Budget Est.	Suppl. Grant/ Re-app.	Total	Actual Expd.	Excess(+)/ Saving(-)	Amount Surrendered/ Re-app.	Savings
3201 Working Exp	55,940.10	2,127.10	58,067.20	57,360.61	-706.59	103.74	-602.85
2552 Prov. For the Development of North East Region	13.40	0.00	13.40	0.00	-13.40	13.40	0.00
Total working Exp.	55,953.50	2,127.10	58,080.60	57,360.61	-719.99	117.14	-602.85
5201 Capital Exp.	1,215.21	78.80	1,294.01	483.60	-810.41	680.50	-129.91
4552 Prov. for the Development of North East Region	76.40	0.00	76.40	0.00	-76.40	76.40	0.00
Total Capital Exp.	1,291.61	78.80	1,370.41	483.60	-886.81	756.90	-129.91
Total Working Exp. + Capital Exp.	57,245.11	2,205.90	59,451.01	57,844.21	-1606.80	874.04	-732.76

Capital Outlay

9.5 The expenditure on fixed assets in the year 2003-04 was Rs. 489.10 Million, of which 30.46% was on Land and Buildings, 39.31% on Mechanization and Modernisation of Postal Services, 25.37% on

Railway Mail Vans and 4.86% on other items including Mail Motor Vehicles. The value of Gross Capital on fixed assets rose to Rs. 11,561.50 Million at the end of the year. The net progressive fixed asset value upto the end of the year was Rs. 9,827.80 Million.

तालिका-15
सेवाओं की लागत

(रुपयों में)

क्र. सं.	सेवा का नाम	2001-2002 (वास्तविक)		2003-04 (प्रक्षेपण)	
		औसत लागत	औसत राजस्व	औसत लागत	औसत राजस्व
1.	पोस्टकार्ड	6.65	0.46	6.64	0.50
2.	मुद्रित पोस्टकार्ड	6.67	2.83	6.66	6.00
3.	प्रतियोगिता पोस्टकार्ड	4.63	4.83	4.72	10.00
4.	पत्र कार्ड (अंतर्देशीय पत्र)	6.65	2.00	6.63	2.50
5.	पत्र	7.43	7.28	7.33	9.46
6.	पंजीकृत समाचार पत्र - एकल	8.29	0.37	8.25	0.39
7.	पंजीकृत समाचार पत्र - बंडल	12.89	0.85	13.03	0.88
8.	बुक पोस्ट - बुक, पैटर्न एवं सैम्पल पैकेट	8.28	7.53	8.25	7.67
9.	बुक पोस्ट - मुद्रित पुस्तकें	12.90	3.36	13.03	3.85
10.	बुक पोस्ट - अन्य पत्रिकाएं	12.91	7.40	13.05	14.15
11.	पावती	5.98	2.83	5.85	3.00
12.	पार्सल	62.43	50.08	67.36	55.28
13.	पंजीकरण	32.98	16.50	33.03	17.00
14.	स्पीड पोस्ट	45.05	37.17	44.60	35.64
15.	मूल्यदेय डाक	21.84	4.04	20.43	3.98
16.	बीमा	42.59	65.97	44.09	53.47
17.	मनीआर्डर	52.71	25.35	53.80	25.35
18.	तार मनीआर्डर	67.74	27.35	70.28	27.35
19.	भारतीय पोस्टल आर्डर	19.99	1.36	21.63	1.36
20.	विदेश डाक	16.51	23.88	13.92	22.42

Table 15
COST OF SERVICES

(In Rs.)

Sl. No.	Name of Service	2001-02 (Actual)		2003-04 (Projection)	
		Average Cost	Average Revenue	Average Cost	Average Revenue
1.	Postcard	6.65	0.46	6.64	0.50
2.	Printed Postcard	6.67	2.83	6.66	6.00
3.	Competition Postcard	4.63	4.83	4.72	10.00
4.	Letter Card (Inland Letter)	6.65	2.00	6.63	2.50
5.	Letter	7.43	7.28	7.33	9.46
6.	Regd. Newspaper-Single	8.29	0.37	8.25	0.39
7.	Regd. Newspaper-Bundle	12.89	0.85	13.03	0.88
8.	Book Post-Book, Pattern & S.Pkts.	8.28	7.53	8.25	7.67
9.	Book Post-Printed Books	12.90	3.36	13.03	3.85
10.	Book Post-Other Periodicals	12.91	7.40	13.05	14.15
11.	Acknowledgement	5.98	2.83	5.85	3.00
12.	Parcel	62.43	50.08	67.36	55.28
13.	Registration	32.98	16.50	33.03	17.00
14.	Speed Post	45.05	37.17	44.60	35.64
15.	Value Payable Post	21.84	4.04	20.43	3.98
16.	Insurance	42.59	65.97	44.09	53.47
17.	Money Order	52.71	25.35	53.80	25.35
18.	Telegraphic Money Order	67.74	27.35	70.28	27.35
19.	Indian Postal Order	19.99	1.36	21.63	1.36
20.	Foreign Mail	16.51	23.88	13.92	22.42

क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्र

10.10 कुल छह क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जिनकी स्थापना डाक सर्किलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की गई। क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्रों के मुख्य उद्देश्य हैं:

- डाक निरीक्षकों और डाक सहायकों एवं छंटाई सहायकों को प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान करना ;
- डाक एवं छंटाई सहायकों , पर्यवेक्षकों , निरीक्षकों, सहायक अधीक्षक डाकघर, पोस्टमास्टर्स आदि को सेवाकालीन और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना; तथा
- विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों को कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा उचित साफ्टवेयर प्रणालियों को समझने, उनका प्रचालन करने के लिए अपेक्षित दक्षता और जानकारी प्रदान करना।

10.11 2003-2004 के दौरान, छह क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा कुल

11316 कर्मचारियों को सेवाकालीन और प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कार्य-स्थल पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण सुविधाएं

10.12 पोस्टल स्टाफ कालेज भारत तथा छह डाक प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा सर्किलों/क्षेत्रों के मुख्यालयों में 39 कार्य-स्थल कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (डब्ल्यू सी टी सी) कार्य कर रहे हैं। ये डब्ल्यू सी टी सी बुनियादी कम्प्यूटर दक्षता में प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ हमारे अनुप्रयोग साफ्टवेयर जैसे मेघदूत 98, संचय पोस्ट, वी 2 एस बी सी ओ, वी एस ए टी, सी ए एम पी (सी आर सी) आदि का रखरखाव भी करते हैं, इनका उद्देश्य अधिक से अधिक कर्मचारियों को उनके कार्य-स्थल के निकट ही कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना है।

10.13 वर्ष 2003-2004 के दौरान छह क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों और 39 डब्ल्यू सी टी सी द्वारा कुल 33,265 कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया।

Table 15
COST OF SERVICES

(In Rs.)

Sl. No.	Name of Service	2001-02 (Actual)		2003-04 (Projection)	
		Average Cost	Average Revenue	Average Cost	Average Revenue
1.	Postcard	6.65	0.46	6.64	0.50
2.	Printed Postcard	6.67	2.83	6.66	6.00
3.	Competition Postcard	4.63	4.83	4.72	10.00
4.	Letter Card (Inland Letter)	6.65	2.00	6.63	2.50
5.	Letter	7.43	7.28	7.33	9.46
6.	Regd. Newspaper-Single	8.29	0.37	8.25	0.39
7.	Regd. Newspaper-Bundle	12.89	0.85	13.03	0.88
8.	Book Post-Book, Pattern & S.Pkts.	8.28	7.53	8.25	7.67
9.	Book Post-Printed Books	12.90	3.36	13.03	3.85
10.	Book Post-Other Periodicals	12.91	7.40	13.05	14.15
11.	Acknowledgement	5.98	2.83	5.85	3.00
12.	Parcel	62.43	50.08	67.36	55.28
13.	Registration	32.98	16.50	33.03	17.00
14.	Speed Post	45.05	37.17	44.60	35.64
15.	Value Payable Post	21.84	4.04	20.43	3.98
16.	Insurance	42.59	65.97	44.09	53.47
17.	Money Order	52.71	25.35	53.80	25.35
18.	Telegraphic Money Order	67.74	27.35	70.28	27.35
19.	Indian Postal Order	19.99	1.36	21.63	1.36
20.	Foreign Mail	16.51	23.88	13.92	22.42

अध्याय 10

मानव संसाधन विकास

10.1 किसी भी संगठन की शक्ति उससे जुड़े व्यक्तियों में निहित होती है। इस 2,50,714 नियमित कर्मचारियों की जनशक्ति वाले विभाग के पास सुविकसित आधारभूत प्रशिक्षण ढांचा उपलब्ध है। विभाग मानव संसाधन विकास पर निरंतर सर्वाधिक ध्यान देता है जिसे डाक प्रचालनों में प्रौद्योगिकी के समावेश के कारण हाल के वर्षों में और अधिक प्रोत्साहन दिया गया है। इसने प्रबंधक एवं प्रचालक तथा अन्य कर्मचारियों की दक्षता के निरंतर उन्नयन और उनका व्यावसायिक ज्ञान बढ़ाने के प्रयोजन से ऑन द जॉब और संस्थागत, दोनों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया है।

प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत ढांचा

10.2 विभाग के प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत ढांचे में निम्नलिखित प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं :

- गाजियाबाद पोस्टल स्टाफ कालेज, भारत
- दरभंगा, मदुरै, मैसूर, सहारनपुर, वडोदरा और गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्र
- सर्किल/क्षेत्रीय मुख्यालय में कार्य-स्थल कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र

पोस्टल स्टाफ कालेज

10.3 पोस्टल स्टाफ कालेज, भारत विभाग के प्रबंधकीय संवर्गों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शीर्ष प्रशिक्षण संस्था है। इस कालेज का मुख्य उद्देश्य भारतीय डाक सेवा और डाक सेवा समूह 'ख' के अधिकारियों में अपेक्षित ज्ञान, दक्षता और आचार-व्यवहार का विकास करना है ताकि वे डाक प्रणाली को अधिक कार्यकुशल और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रियाशील बना सकें। यह कालेज सेवाओं के प्रबंधन दक्षता में सुधार लाने के लिए इन क्षेत्रों में अनुसंधान करने के साथ-साथ उसका प्रसार करता है। यह कालेज पोस्टल डाटा बैंक और डाक्यूमेंटेशन केन्द्र का भी प्रचालन कर रहा है।

10.4 यह कालेज यूनिवर्सल पोस्टल यूनिन (यू.पी.यू.), एशियन पैसिफिक पोस्टल कालेज, बैंकाक(थाइलैंड) के परामर्श पर तथा दक्षेस देशों के साथ हुए करार के अंतर्गत विदेशी डाक प्रशासनों से संबंधित अधिकारियों के लाभ के लिए डाक सेवाओं के विभिन्न पहलुओं पर कार्यशाला का आयोजन भी करता है।

10.5 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कालेज ने 9 प्रवेश (इंडक्शन) तथा 15 सेवाकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किए जिसमें 411 अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान डाक विभाग के 237 अधिकारियों को कम्प्यूटर का प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।

विदेशों में प्रशिक्षित किए भारतीय डाक सेवा के अधिकारी

10.6 वर्ष 2003-2004 में ग्यारह भारतीय डाक अधिकारियों ने एशियन पैसिफिक पोस्टल कालेज, बैंकाक(थाइलैंड) में तथा तेहरान (ईरान) में एक अधिकारी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

विदेशी भागीदारों के लिए प्रशिक्षण

10.7 अंतर्राष्ट्रीय सेवा गुणवत्ता पर यू पी यू प्रशिक्षण 20 नवंबर, 2003 से 27 नवंबर, 2003 तक आयोजित किया गया जिसमें विदेशों अर्थात् अफगानिस्तान, ईरान, मलेशिया, मंगोलिया, नेपाल तथा फिलीपीन प्रत्येक से एक अधिकारी तथा भारत से दस अधिकारियों ने भाग लिया।

10.8 पोस्टल स्टाफ कालेज, इंडिया में 03 नवंबर, 2003 से 14 नवंबर, 2003 तक एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यपालक विकास कार्यक्रम (ई पी डी) भी आयोजित किया गया जिसमें छह विदेशी भागीदारों भूटान, बुरुंडी, ईरान, नेपाल, सीरियालिऑन तथा जाम्बिया प्रत्येक देश से एक तथा भारत के छह भागीदारों ने भाग लिया।

10.9 डाक प्रशिक्षण केन्द्र सहारनपुर में दिनांक 21 जुलाई, 2003 से 16 अगस्त, 2003 तक भूटान पोस्ट के कनिष्ठ स्तर के 15 डाक कर्मचारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

Chapter 10

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

10.1 The strength of an organization lies in its people. The Department with a manpower of 2,50,714 regular employees has a well-developed training infrastructure. Priority has been accorded to human resource development, which in recent years, received added stimulus in view of induction of technology in postal operations. Extensive training programmes have been prepared for both on the job as well as institutional modules for managers, operatives and other functionaries, for continually upgrading skills and professional competence.

Training Infrastructure

10.2 The training infrastructure of the Department consists of the following Training Institutes :-

- Postal Staff College India at Ghaziabad;
- Regional Postal Training Centres at Darbhanga, Madurai, Mysore, Saharanpur, Vadodara and Guwahati;
- Workplace Computer Training centres at Circle/Regional Headquarters.

Postal Staff College

10.3 The Postal Staff College, India is the apex training institution catering to the training needs of the managerial cadres of the Department. The primary objective of the College is to impart induction as well as in-service training to the officers of the Indian Postal Service and Postal Service Group "B" with a view to inculcating requisite knowledge, skills and attitude to enable them to make the postal system effective and responsive to customers' needs. The College also undertakes and promotes research in the sphere of improving the efficiency and management of postal services. It operates a Postal Data Bank and Documentation Center.

10.4 In addition, the College also organizes workshops on different aspects of postal services at the behest of the Universal Postal Union (UPU), Asia Pacific Postal College, Bangkok (Thailand) and under an agreement with SAARC countries for the benefit of officers belonging to foreign postal administrations.

10.5 During the period under review, the College conducted 9 Induction and 15 In-service training programmes, in which 411 officers participated. 237 officers were imparted training in computers during the period.

Indian Postal Service Officers Trained Abroad

10.6 Eleven Indian Postal Officers were trained at the Asian Pacific Postal College, Bangkok (Thailand) and one officer at Tehran (Iran) during the year 2003-2004.

Training for Foreign Participants

10.7 UPU training on International Service Quality was organised from 20th November, 2003 to 27th November, 2003 with participation of six officers from abroad one each from Afghanistan, Iran, Malaysia, Mongolia, Nepal and Philippines and ten officers from India.

10.8 An International Executive Development Programme (EDP) was also organised from 03rd November, 2003 to 14th November, 2003 at the Postal Staff College, India with six foreign participants, one each from Bhutan, Burundi, Iran, Nepal, Sierra Leone and Zambia and six participants from India.

10.9 A training programme for fifteen junior level postal officials of Bhutan Post was organised at PTC, Saharanpur from 21st July, 2003 to 16th August, 2003.

क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्र

10.10 कुल छह क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्र हैं, जिनकी स्थापना डाक सर्किलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की गई। क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्रों के मुख्य उद्देश्य हैं:

- डाक निरीक्षकों और डाक सहायकों एवं छंटवाई सहायकों को प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान करना ;
- डाक एवं छंटवाई सहायकों , पर्यवेक्षकों , निरीक्षकों, सहायक अधीक्षक डाकघर, पोस्टमास्टर्स आदि को सेवाकालीन और पुनश्चर्या प्रशिक्षण प्रदान करना; तथा
- विभाग की आवश्यकताओं के अनुरूप कर्मचारियों को कम्प्यूटर हार्डवेयर तथा उचित साफ्टवेयर प्रणालियों को समझने, उनका प्रचालन करने के लिए अपेक्षित दक्षता और जानकारी प्रदान करना।

10.11 2003-2004 के दौरान, छह क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा कुल

11316 कर्मचारियों को सेवाकालीन और प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कार्य-स्थल पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण सुविधाएं

10.12 पोस्टल स्टाफ कालेज भारत तथा छह डाक प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा सर्किलों/क्षेत्रों के मुख्यालयों में 39 कार्य-स्थल कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र (डब्ल्यू सी टी सी) कार्य कर रहे हैं। ये डब्ल्यू सी टी सी बुनियादी कम्प्यूटर दक्षता में प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ हमारे अनुप्रयोग साफ्टवेयर जैसे मेघदूत 98, संचय पोस्ट, वी 2 एस बी सी ओ, वी एस ए टी, सी ए एम पी (सी आर सी) आदि का रखरखाव भी करते हैं, इनका उद्देश्य अधिक से अधिक कर्मचारियों को उनके कार्य-स्थल के निकट ही कम्प्यूटर प्रशिक्षण देना है।

10.13 वर्ष 2003-2004 के दौरान छह क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों और 39 डब्ल्यू सी टी सी द्वारा कुल 33,265 कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया।

Regional Postal Training Centres

10.10 There are six Regional Postal Training Centres, which have been established taking into account the requirement of the Postal Circles. The main objectives of the Regional Postal Training Centres are:-

- To impart induction training to Inspectors of Posts, Postal Assistants and Sorting Assistants;
- To impart in-service and refresher training to Postal and Sorting Assistants, Supervisors, Inspectors, Assistant Superintendent of Posts, Postmasters, etc; and
- To impart the skills and knowledge required for understanding and operating computer hardware and software systems relevant to the needs of the Department.

10.11 A total number of 11,316 officials were imparted in-service and induction training during 2003-2004 by the six Regional Training Centres.

Workplace Computer Training Facilities

10.12 Thirty-nine Workplace Computer Training Centres (WCTCs) are functioning at the Headquarters of Circles/ Regions in addition to the facilities at the Postal Staff College, India and six Postal Training Centres. These WCTCs impart training in basic computer skills and application software packages like Meghdoot 98, Sanchay Post, V2 SBCO, VSAT, CAMP(CRC) etc., to postal staff nearer to their workplace.

10.13 A total number of 33,265 officials were imparted computer training during 2003-2004 by the six Regional Postal Training Centres and thirty-nine WCTCs.

अध्याय - 11

सतर्कता कार्यकलाप

11.1 डाक विभाग में सत्यनिष्ठा और कार्यकुशलता बनाए रखने के उद्देश्य से सचिव, डाक विभाग की अध्यक्षता में एक पूर्ण विकसित सतर्कता स्थापना है। सचिव, डाक विभाग की सहायता के लिए उप महानिदेशक (सतर्कता) हैं जो कि विभाग के मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता संबंधी मामलों में सचिव के विशेष सहायक के रूप में कार्य करते हैं और डाक विभाग तथा मुख्य सतर्कता आयोग के बीच कड़ी का काम करते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता के लिए मुख्यालय में निदेशक (सतर्कता), तीन सहायक महानिदेशक और एक डेस्क अधिकारी हैं।

11.2 सर्किल, क्षेत्रीय और डिविजनल स्तर पर सतर्कता संबंधी कार्य इनके प्रमुख यानि प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, क्षेत्रीय पोस्टमास्टर जनरल और डिविजनल अध्यक्ष द्वारा अपने समग्र कार्यों और उत्तरदायित्वों के ही एक भाग के रूप में किए जाते हैं।

11.3 मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता मामलों को देखने के अलावा निवारक सतर्कता के एक भाग के रूप में संवेदनशील स्थानों का नियमित और अचानक निरीक्षण करने, ऐसी कार्यविधियों की समीक्षा करने और उन्हें दोषरहित बनाने के लिए भी जिम्मेदार हैं जिनमें भ्रष्टाचार या कदाचार की आशंका हो। वे विभाग और इसके फील्ड कार्यालयों में भ्रष्टाचार और दूसरे प्रकार के अनाचारों की रोकथाम, इनका पता लगाने

और दण्ड देने के लिए भी उत्तरदायी है।

11.4 विभिन्न स्तरों पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के साथ समय-समय पर बैठकें होती हैं और सी बी आई के साथ परामर्श करके संदेहास्पद अधिकारियों की सूची तैयार की जाती है। संदेहास्पद निष्ठा वाले राजपत्रित अधिकारियों की एक सूची भी तैयार की जाती है।

11.5 महत्वपूर्ण मामलों में निदेशालय के अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है और जहां आवश्यक हो मामलों की सूचना पुलिस/सी बी आई को भी दी जाती है।

11.6 राजस्व की चोरी का पता लगाने के लिए केन्द्रीय सतर्कता दल द्वारा जांच की जाती है। कदाचार और राजस्व की चोरी रोकने के लिए आवश्यक उपयुक्त कार्रवाई की जाती है। वर्ष के दौरान सतर्कता कार्यकलाप (सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालय सहित) इस प्रकार रहे:-

- (i) 10 अधिकारियों और 1322 अन्य कर्मचारियों को बड़ा दण्ड और 20 अधिकारियों और 7445 अन्य कर्मचारियों को छोटा दण्ड दिया गया।
- (ii) 40 रिपोर्टों की जांच हुई और उन्हें केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा गया।

Chapter 11

VIGILANCE ACTIVITIES

11.1 The Department of Posts has a full-fledged vigilance set up at its headquarters at New Delhi headed by the Secretary, Department of Posts for maintenance of integrity and efficiency in the Department. He is assisted by the Deputy Director General (Vigilance) who is the Chief Vigilance Officer (CVO) of the Department. The CVO acts as the Special Assistant to the Secretary in all matters pertaining to vigilance and provides a link between the Department of Posts and the Chief Vigilance Commission (CVC). The CVO is assisted by a Director (Vigilance), three Assistant Directors General and one Desk Officer at the Headquarter.

11.2 At the Circle, Regional and Divisional levels, vigilance related functions are discharged by heads of these formations, viz. Principal Chief Postmaster General/ Chief Postmaster General, Regional Postmaster General and Divisional Heads, as part of their overall duties and responsibilities.

11.3 Besides, dealing with vigilance cases, as a part of preventive vigilance the CVO arranges regular and surprise inspections of sensitive areas, review and streamlining of procedures which appear to afford scope

for corruption or misconduct, initiate measures for prevention, detection of corruption and other malpractices in the Department and its field offices.

11.4 Periodical meetings with the CBI at various levels are held and Agreed Lists of suspected officers drawn up in consultation with CBI. List of Officers of doubtful integrity has also been also prepared.

11.5 Investigations by deputing officers from the Directorate are carried out in important cases and are also reported to Police/CBI, where necessary.

11.6 Surprise visits are carried out in offices through Central Checking Squad to detect leakage of revenue. Appropriate action is taken to prevent malpractices and leakage of revenue. Vigilance activities during the year (including attached and subordinate office) were as follows:-

- (i). 10 Officers and 1322 other staff were awarded major penalty while 20 Officers and 7445 other staff were awarded minor penalty.
- (ii). 40 reports were examined and sent to CVC.

अध्याय-12

महिलाओं से संबंधित मुद्दे

12.1 31.3.2004 को विभाग में कुल 2,50,714 विभागीय कर्मचारी थे जिसमें विभिन्न ग्रेडों में 33,001 महिला कर्मचारी शामिल हैं (देखें तालिका 22)। डाक विभाग के सभी प्रवेश और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभाग में महिलाएं प्रचालक से लेकर नीति और निर्णय लेने के स्तरों पर कार्यरत हैं। वे सभी दायित्वों का समान रूप से निर्वहन करती हैं, चाहे यह कार्यालय में बैठकर हो या इसके बाहर काम करके।

12.2 लैंगिक समानता, समता और महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण का सिद्धांत डाक विभाग के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय रहे हैं। उनकी आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनने और उन्नतिशील एवं सहयोगपूर्ण

परिवेश सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इससे वे अपने घर और कार्य की जिम्मेदारियों में संतुलन रखने में सक्षम हो पाएंगी। इसमें महिला कर्मचारियों के लिए अलग से आराम कक्षों और मनोविनोद कक्षों की व्यवस्था करना और जहां संभव हो, शिशु सदनों की व्यवस्था करना सम्मिलित है।

12.3 महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए निदेशालय में एक समिति स्थापित की गई है। समिति की अध्यक्ष निदेशक रैंक की एक महिला अधिकारी हैं। इसमें चार सदस्य हैं। फील्ड में भी डिवीजन स्तर पर समान प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की गई है।

Chapter 12

GENDER ISSUES

12.1 On 31.03.2004 there were 2,50,714 departmental employees, which includes 33,001 women employees in various grades in the Department (see Table 20). Gender sensitization modules have been included in all Induction and In-service Training programmes of the Department of Posts. Women hold positions at all levels in the Department ranging from operative to policy and decision-making levels. They partake equally in all responsibilities, be it office based or outdoor.

12.2 The principles of gender equality, equity and protection of the rights of women are a matter of prime concern of the Department of Posts. Every effort is

being made to be sensitive to their needs and ensure a thriving and supportive environment, which will enable them to balance their responsibilities at work with those at home. This includes providing separate rest rooms and recreation rooms for women employees and providing crèche facilities where possible.

12.3 To look into the matter of prevention of sexual harassment of women a committee chaired by a lady officer of the rank of Director has been set up in the Directorate with four other members. Similar bodies have been set up at every level up to the Division level in the field.



उत्तरांचल के माननीय राज्यपाल श्री सुदर्शन अग्रवाल नैनीताल में 18 जून, 2004 को जिला स्तरीय फिलेटली प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए। साथ में श्रीमती सुनीता त्रिवेदी, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, उत्तरांचल सर्किल भी उपस्थित रहीं हैं।

The Hon'ble Governor of Uttranchal Shri Sudarshan Aggrawal inaugurating the District Level Philatelic Exhibition at Nainital on 18th June, 2004. Also seen in the picture is Smt. Suneeta Trivedi, CPMG, Uttranchal Circle.

अध्याय 13

अन्य कार्यकलाप

कर्मचारी संबंध

13.1 अवधि के दौरान विभाग ने अपने कर्मचारियों के परिसंघों और यूनियनों/संघों से आत्मीय और सार्थक संबंध बनाने का पूरा प्रयास किया। 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 की अवधि के दौरान इस संबंध में एक बड़ा कार्य यह हुआ कि लगभग 9 वर्ष के अंतराल के बाद तदर्थ आधार पर विभागीय परिषद (जे सी एम) का पुनर्गठन किया गया। विभागीय परिषद (जे सी एम) की प्रथम साधारण बैठक 18 नवंबर, 2003 को हुई। बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई जिसमें कार्य-सूची के सभी मुद्दों पर सूक्ष्मतापूर्वक विचार किया गया और कर्मचारी पक्ष की परस्पर सहमति भी ली गई जो कि स्कीम का मूल आधार है।

13.2 जहां तक जन शिकायत निवारण कार्य का संबंध है यह उल्लेख किया जाता है कि डाक विभाग में परिसंघों/यूनियनों को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए औपचारिक एवं अनौपचारिक बैठकों के रूप में पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं। इसके अलावा, सरकारी कामकाज में अधिक खुलापन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग में हो रहे परिवर्तनों से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को, विशेष बैठकों और मंत्रियों/वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकों के दौरान अवगत कराया जाता है।

कर्मचारी कल्याण

13.3 डाक सेवा कर्मचारी कल्याण बोर्ड का उद्देश्य विभाग के कर्मचारियों के लिए कल्याण, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यकलापों को आयोजित करना, बढ़ावा देना और विकसित करना है। बोर्ड को इसके लिए भारत की समेकित निधि से सहायता अनुदान प्राप्त होता है। अधीनस्थ संघटकों द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यकलापों तथा खेलकूद के माध्यम से धन प्राप्त होता है और कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक अंशदान भी दिया जाता है।

13.4 कल्याण बोर्ड के कोषों का उपयोग खेलकूद, मनोरंजन क्लबों, बीमारी, मृत्यु तथा प्राकृतिक आपदाओं में वित्तीय सहायता प्रदान करने, शैक्षणिक छात्रवृत्ति, पर्यटन यात्राओं के लिए सब्सिडी, विकलांग

कर्मचारियों तथा उनके बच्चों की सहायता करने, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, क्रेशों आदि के लिए किया जाता है। वर्ष 2003-2004 के दौरान इस प्रयोजनार्थ सरकार से 40 मिलियन रु. प्राप्त हुए थे।

13.5 केन्द्रीय कल्याण निधि से सभी सर्किल कल्याण निधियों और निदेशक कल्याण निधि को वर्ष 2003-04 के दौरान संवितरित राशि 30.2 मिलियन रु. थी और वर्ष के दौरान केन्द्रीय खेल निधि से सभी सर्किल खेल निधियों को संवितरित राशि 11.8 मिलियन रु. थी। विभाग के कल्याण और खेलकूद कार्यकलापों पर कुल व्यय वर्ष 2003-04 के दौरान 42.5 मिलियन रु. था।

डकैती, आतंकवादी हमलों, दंगों आदि के कारण मारे गए विभागीय कर्मचारियों के मामले में केन्द्रीय कल्याण निधि से सहायता।

13.6 1 अप्रैल, 2003 से 31 मार्च, 2004 की अवधि के दौरान इस प्रकार के दो मामले हुए और प्रत्येक मामले के लिए मृतक कर्मचारी के परिवार को मौजूदा अनुदेशों के अनुसार सर्किल कल्याण निधियों से संस्वीकृत 7000/- रु. के अलावा केन्द्रीय कल्याण निधि से 43,000/- रु. भुगतान किए गए।

हॉलिडे होम

13.7 कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित के लिए देश के विभिन्न स्थानों में 29 हॉलिडे होम काम कर रहे हैं। ये काफी लोकप्रिय हैं और स्टाफ द्वारा प्रायः प्रयोग किए जाते हैं। अगरतला से सोहरा (चेरापूँजी), पूर्वोत्तर सर्किल के मेघालय स्थित हॉलिडे होम का स्थान बदलने के संबंध में विभाग का अनुमोदन 14.7.2003 को संप्रेषित कर दिया गया है।

चिकित्सा

13.8 डाक विभाग द्वारा 48 शहरों में लगभग 56 डाक एवं तार औषधालय चलाए जा रहे हैं। दोनों विभागों अर्थात् डाक विभाग तथा

Chapter 13

OTHER ACTIVITIES

Staff Relation

13.1 During the period, the Department endeavoured to maintain harmonious and meaningful relations with the Federations and Unions/Association of its employees. The major development during the period from 1st April, 2003 to 31st March, 2004 is that the Department reconstituted Departmental Council (JCM) on an ad-hoc basis after a gap of about 9 years. First ordinary meeting of the Departmental Council (JCM) was held on 18th November, 2003. The meeting was held in a congenial atmosphere wherein all agenda items were discussed threadbare and in mutual agreement with the staff side, as per spirit of the scheme.

13.2 In so far as Public Grievances Redressal work is concerned, it is to mention that in the Department of Posts, the Federations/Unions have been provided with enough opportunities in the form of formal as well as informal meetings to redress their grievances. Further, with a view to ensuring greater openness in the government functioning, the staff representatives are kept apprised about the new developments taking place in the Department by way of granting special meetings as well as during periodical meetings with Minister/Sr. Officers.

Staff Welfare

13.3 The objective of the Postal Services Staff Welfare Board is to promote, develop and organise welfare, sports and cultural activities for the employees of the Department. The Board receives grant-in-aid for this purpose from the Consolidated Fund of India. Voluntary contributions from the staff and collections through sports and cultural activities are also arranged.

13.4 The funds of the Welfare Board are utilised for activities like sports, recreation clubs, financial assistance in cases of illness, death and natural calamities, educational scholarships, subsidy for excursion trips,

grants to help handicapped staff and their children, vocational training centres, creches, etc. For the year 2003-2004 an amount of Rs. 40 Million was received from the government for the purpose.

13.5 The amount disbursed from Central Welfare Fund to all Circle Welfare Funds including Directorate Welfare Fund during the year 2003-04 was Rs. 30.2 Million and the amount disbursed to all Circle Sports Funds from Central Sports Fund during the year was 11.8 Million. Total expenditure on Welfare and Sports activities of the Department during the year 2003-04 was Rs. 42.5 Million.

Financial assistance from Central Welfare Fund in cases of Departmental Official's death due to attack by robbers, terrorists, riots, etc.

13.6 During the period from 1st April, 2003 to 31st March, 2004 two such cases occurred and for each case Rs. 43,000/- has been sanctioned for payment to the family of the deceased officials from Central Welfare Fund besides Rs. 7,000/- sanctioned from Circle Welfare Funds, as per existing instructions.

Holiday Homes

13.7 29 Holiday Homes are functioning at various places of the country for the benefit of the employees and their families. These are quite popular and are frequently used by the staff. Approval of the Department was conveyed for shifting of the Holiday Home from Agartala to Sohra (Cheerapunji), Meghalaya of the N. E. Circle on 14.7.2003. Heads of Circles have been delegated powers for opening of Holiday Homes subject to the terms & conditions as laid down by the Department.

Medical

13.8 There are 56 P&T dispensaries in 48 cities being run by the Department of Posts. Employees and

दूरसंचार विभाग के सभी कर्मचारी तथा पेंशनर जो इन औषधालयों के क्षेत्राधिकार में रह रहे हैं, को इन औषधालयों से आउटडोर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाती है। 3 लाख लाभार्थियों को कवर करते हुए लगभग 60,000/- कार्डधारक हैं जिसमें कर्मचारियों तथा पेंशनरों सहित उन पर आश्रित उनके परिवार के सदस्य भी शामिल हैं। सेवारत कर्मचारियों को यह सुविधा सी एस (एमए) नियम के एवज में, बिना किसी शुल्क/अंशदान के प्रदान की जाती है जबकि पेंशनरों से 9/- रु. प्रति माह का नाममात्र का अंशदान लिया जाता है। ये औषधालयों भारत सरकार के परिवार कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में भी अपना योगदान देती हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान इन औषधालयों पर लगभग 211 मिलियन रुपये खर्च किए गए। अन्य स्थानों पर जहां डाक एवं तार औषधालयों मौजूद नहीं हैं, वहां विभाग के कर्मचारी कें.स.स्वा.यो. औषधालयों या प्राधिकृत मेडिकल अटेंडेंटों की सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं।

खेल

13.9 वर्ष के दौरान 12 खेलों के लिए जैसे कि टेबिल टेनिस, बास्केटबाल, हाकी, फुटबाल, बैडमिंटन, चैस व कैरम, एथलेटिक्स और साइक्लिंग, कबड्डी, कुश्ती, वालीबाल, क्रिकेट तथा भारोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग तथा सर्वश्रेष्ठ शारीरिक सौष्ठव के लिए भारतीय डाक खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अतिरिक्त एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया।

13.10 पुनरीक्षा अवधि के दौरान भारतीय डाक टीमों ने कई विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय समारोहों में भाग लिया।

समाचार पत्र तथा इन-हाउस पत्रिका

13.11 इस अवधि के दौरान महानिदेशक के समाचार पत्र (द्विभाषीय) को विभाग के महत्वपूर्ण कार्यकलापों तथा नीतिगत निर्णयों से संबंधित सूचना को परिचालित करने के उद्देश्य से आरंभ किया गया तथा इसका प्रकाशन किया जा रहा है।

13.12 डाक विभाग की त्रैमासिक इन-हाउस पत्रिका का प्रकाशन द्विभाषा में होता है। यह अंतर विभागीय संचार का एक सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से कर्मचारियों को विभाग की नीतियों, समस्याओं तथा विकास से संबंधित सूचना प्रदान की जाती है। वर्ष के दौरान पत्रिका में नया कालम "टैलेन्ट गैलरी" नाम से शुरू किया गया है, जिसमें विभाग के अज्ञात उत्कृष्ट व्यक्तित्वों का विशिष्ट उल्लेख किया जाता है। ज्ञानपीठ

पुरस्कार विजेता लेखक श्री निर्मल वर्मा द्वारा रचित "टिकटों का संग्रह" नामक एक विशेष लेख भी प्रकाशित किया गया है। इसके अलावा 50 वर्ष पुराना डाक-तार जर्नल के नाम से अंग्रेजी और हिन्दी में एक नया कालम आरंभ किया गया है। इस पत्रिका में डाक विभाग से संबंधित विभिन्न समाचार पत्रों में छपी खबरों व विचारों के क्लिप छापे जाते हैं।

सर्किल के अध्यक्षों को प्रत्यायोजित शक्तियां

13.13 16-17 जून, 2003 को आयोजित सर्किल अध्यक्षों के सम्मेलन में एक सुझाव दिया गया था कि सर्किलों के अध्यक्षों को ऐसी शक्तियां प्रत्यायोजित की जाएं, जोकि प्रधान डाकघर निर्धारित मानदंडों को पूरा नहीं कर पाते हैं उन अवमानक प्रधान डाकघरों का दर्जा वे कम कर सकें। प्रस्ताव के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के बाद डाक सेवा बोर्ड ने सर्किलों के अध्यक्षों को ऐसे प्रधान डाकघर का दर्जा घटाने की शक्तियां प्रदान करने का अनुमोदन दे दिया है जिनके अधीन विहित प्रावधानों को पूरा करने वाले 20 उप डाकघर नहीं हैं।

13.14 डाक विभाग में सर्किलों के अध्यक्षों तथा विभाग के प्रमुखों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन है तथा डाक विभाग के आंतरिक वित्त विंग के साथ सलाह करके यह निर्णय लिया गया है कि सी एस (एम ए) नियमावली 1944 के अंतर्गत सर्किलों के अध्यक्षों/ विभाग प्रमुखों को यह शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं कि वे डाक कर्मचारियों द्वारा स्वयं के लिए या अपने परिवार के आश्रित सदस्यों के इलाज के लिए, उपचार प्रदान करने वाले सरकारी चिकित्सक/सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल से इलाज का प्रमाण पत्र/इलाज पर खर्चा होने वाली राशि का आकलन प्राप्त होने पर अग्रिम संस्वीकृत कर सकते हैं।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

13.15 वर्ष के दौरान (क) असम, उत्तर पूर्व, उड़ीसा, तमिलनाडु तथा उत्तरांचल सर्किल (ख) निदेशक लेखा डाक का कार्यालय, कटक (ग) पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय, कोयम्बतूर के आरक्षण रोस्टरों का निरीक्षण किया गया तथा उसमें पाई गई कमियों/चूक का निपटान सर्किल द्वारा किया गया। विभागीय पदोन्नति समिति की जांच की गई तथा पाया गया कि बहुत से सर्किलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को भी शामिल किया गया है। सभी सर्किलों को सलाह दी गई है कि विभागीय पदोन्नति समिति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एक सदस्य को शामिल किया जाए।

Pensioners of both the Departments i.e. Department of Posts and Department of Telecom residing in the jurisdiction of these dispensaries are provided outdoor medical facilities by these dispensaries. There are about 60,000 Card holders covering about 3 Lakhs beneficiaries, which include the dependant family members of the employees as well as Pensioners. Serving employees are being provided these facilities free of cost/contribution in lieu of CS(MA) Rules but a nominal contribution of Rs. 9/- per month is being charged from the Pensioners. These dispensaries also help in implementation of the family welfare programme of the Government of India. During the year 2003-2004, an expenditure of about Rs. 211 Million was incurred on these dispensaries. In other places, where P&T dispensaries are not available, the employees of the Department can avail comprehensive health care facilities from CGHS dispensaries wherever available or from authorised medical attendant.

Sports

13.9 During the year India Postal Sports Tournaments for 12 events viz. Table-Tennis, Basketball, Hockey, Football, Badminton, Chess & Carrom, Athletics & Cycling, Kabaddi, Wrestling, Volleyball, Cricket and Weightlifting, Powerlifting & Best Physique were organised. In addition, a Cultural Meet was also organised.

13.10 During the period under review India Post Teams participated in various International and National Events.

Newspaper and In-house Magazine

13.11 Director General's Newsletter (bi-lingual) circulating information relating to important activities of the Department as well as policy decisions was introduced during this period and is being published.

13.12 Dak Patrika, a quarterly in-house magazine of the Department of Posts, is published bilingually. It is an effective medium of intra-departmental communication, which keeps the employees informed about the policies, problems and developments in the Department. During the year a new column "Talents Galore" for highlighting

the unknown eminent personalities of the Department has been introduced. A special article on "Ticketon ka Sangrah" in Hindi written by Gyanpeeth award winner writer Shri Nirmal Verma has been published. In addition, a new column in English and Hindi both pertaining to 50 years old Dak Tar Journal has also been started. Press clippings from various newspapers concerning News & Views about the Department of Posts are being reproduced in the Journal.

Delegation of powers to the Heads of Circles

13.13 In the Heads of Circles Conference held on 16th – 17th June, 2003, a suggestion was made to delegate powers to the Heads of Circles to downgrade Sub-Standard Head Offices not conforming to the prescribed norms. The Postal Services Board after considering all relevant aspects of the proposal has accorded its approval to empower the Heads of the Circles to downgrade a Head Office not having 20 Sub-Offices(SOs) under it, with certain provisions.

13.14 The proposal for delegation of powers to the Heads of the Circles and HODs in the Department of Posts has been under consideration of the Department and it has now been decided in consultation with the IF Wing of the Department of Posts to delegate the powers under CS(MA) Rules, 1944 to the Heads of the Circles/HODs in the Department of Posts to sanction advances to the Postal employees in respect of their treatment and treatment of dependant members of their family on receipt of a certificate/estimate from the treating physician of a Government/Government recognized hospital.

Scheduled Castes/ Scheduled Tribes

13.15 The reservation rosters in respect of a). Assam, North-East, Orissa, Tamil Nadu and Uttaranchal Circles; b). Office of the Director of Accounts, Cuttack; c). Postmaster General, Coimbatore were inspected during the year and the shortcomings/lapses noticed were settled by the Circles. Departmental Promotion Committees(DPCs) were checked and found that one Member of SCs/STs was also included in most of the Circles. All the Circles have been advised to include one Member from SCs/STs during DPCs.

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, भूतपूर्व सैनिकों तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व

13.16 31.03.2004 तक विभाग में विभिन्न ग्रेडों में अनुसूचित जनजाति के 46,641, अनुसूचित जनजाति के 17349, भूतपूर्व सैनिक के 2178, विकलांग भूतपूर्व सैनिक 52 तथा 33001 महिला कर्मचारी हैं (देखें तालिका 19 व 20)।

कार्य-अध्ययन

13.17 वर्ष के दौरान डाक-टिकट विक्रेताओं, ए.बी.सी. मैसेज तथा कम्प्यूटरीकृत पंजीकरण केन्द्र (सी आर सी) के मानदंड तैयार करने संबंधी कार्य-अध्ययन पूरा किया गया। इसके अलावा मेघदूत लोकल एरिया नेटवर्क (एमडीएलएएन) तथा बचत बैंक लोकल एरिया नेटवर्क (एस बी एल ए एन) के मानदंड तैयार करने संबंधी कार्य अध्ययन भी आरंभ किया गया। पेंशन, हिन्दी, एस पी बी-II, सी पी, डी (डाक) तथा एस पी बी-I अनुभाग के कार्यों का भी आकलन किया गया तथा इसकी अंतिम रिपोर्ट भी जारी की गई।

राजभाषा

13.18 केन्द्र सरकार की नीति के अनुसरण में विभाग, सरकारी पत्राचार में हिन्दी के अधिकतम प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। राजभाषा अधिनियम 1963 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों तथा द्विभाषी रूप या केवल हिन्दी में जारी होने वाले सभी अपेक्षित दस्तावेजों के अनुवाद का दायित्व राजभाषा शाखा पर है। दिन-प्रति-दिन के अनुवाद के अलावा राजभाषा शाखा ने विभाग की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंडियापोस्ट.ऑर्ग का अनुवाद पूरा किया है।

13.19 वार्षिक रिपोर्ट, बजट, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठकों से संबंधित सामग्री, फिलैटलिक विवरणिकाओं व फिलैटलिक समाचार बुलेटिन, संसदीय प्रश्नों, आश्वासनों, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संदर्भों आदि का अनुवाद कुछ ऐसे मुख्य कार्य हैं जिन्हें पुनरीक्षाधीन अवधि के दौरान पूरा किया गया। डाक निदेशालय में किए जाने वाले कार्यों के अनुवाद कार्य के अतिरिक्त विभाग के व्यवसाय विकास निदेशालय तथा डाक जीवन बीमा निदेशालय द्वारा किए जाने वाले कार्यों का भी अनुवाद राजभाषा अनुभाग द्वारा ही किया जाता है।

13.20 विभाग के कार्यालयों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को सुचारु रूप से मॉनीटर करने के लिए मुख्यालयों तथा अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियां कार्य कर रही हैं।

13.21 राजभाषा अनुभाग ने डाक विभाग (मुख्यालय) के सभी अनुभागों, सर्किल मुख्यालयों तथा डाक विभाग के अन्य संबंधित कार्यालयों को राजभाषा अधिनियम तथा पुनरीक्षाधीन वर्ष में राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अनुपालनार्थ जारी संबंधित नियमों एवं निर्देशों से भी अवगत कराया है।

13.22 हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में डाक विभाग (मुख्यालय) के सभी अनुभागों, सर्किल मुख्यालयों, डाक प्रशिक्षण केन्द्रों, पोस्टल स्टाफ कालेज, डाक जीवन बीमा निदेशालय तथा व्यवसाय विकास निदेशालय से प्राप्त त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट की पुनरीक्षा भी राजभाषा अनुभाग में की जाती है तथा जहां कहीं भी त्रुटियां पाई गईं उनमें सुधार लाने के लिए आवश्यक उचित उपाय किए गए।

13.23 राजभाषा के संबंध में संसदीय समिति की द्वितीय उप समिति भी राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को मॉनीटर करती है। अवधि के दौरान समिति ने 20 डाकघरों का निरीक्षण किया।

13.24 राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2003-04 में दिए निर्देशों का अनुपालन करते हुए सत्रह कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

13.25 दिनांक 15 सितंबर, 2003 को विभाग में हिन्दी दिवस आयोजित किया गया तथा 15 से 29 सितंबर, 2003 को हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। हिन्दी पखवाड़ा में आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार भी बांटे गए। पखवाड़े के दौरान एक चार दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

जन शिकायतें

13.26 वर्ष 2003-2004 के दौरान, विभाग में 7,98,220 जन शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 7,45,720 मामलों का निपटान किया गया। वरीयता आधार पर शिकायतों का निवारण करने के लिए पूरे वर्ष उपाय किए जाते हैं। डाक अदालत तथा पोस्ट फोरम की तिमाही बैठकें आयोजित की गईं।

Representation of SC, ST, Ex-Serviceman and Women

13.16 As on 31.03.2004 there were 46,641 SC, 17,349 ST, 2,178 Ex-Servicemen, 52 Disabled Ex-servicemen and 33,001 Women employees in various grades in the Department (see Table 19 & 20).

Work Study

13.17 During the year the studies of evolution of norms of Stamp Vendor, ABC Messages and Computerised Registration Centre(CRC) were completed. Besides, the studies of Evolution of Norms for Megh Doot Local Area Network(MDLAN) and Savings Bank Local Area Network(SB LAN) were initiated. Work Measurement Studies of Pension, Hindi, SPB-II, CP, D(Mails) and SPB-I Sections, were conducted and final report issued.

Official Language

13.18 In pursuance of the policy of the Central Government, the Department has been making sustained effort to ensure optimum use of Hindi in official correspondence. The Official Language Branch is responsible for the implementation of Official Languages Act, 1963 and the Rules made thereunder as well as translation of all kinds of documents required to be issued either in bilingual form or in Hindi only. Besides routine nature of translation, OL Branch has completed the voluminous translation of the Department's web site namely www.indiapost.org.

13.19 The translation of the Annual Report, Budget, material in connection with the meetings of the Standing Committee of the Ministry of Communications and IT, Philatelic Brochures and Philatelic news bulletin, Parliament Questions, Assurances, VIP reference are some of the major works accomplished during the period under review. In addition to the translation work generated in the Directorate of Posts, translation support has also been provided to the BD Directorate and PLI Directorate of the Department.

13.20 In order to effectively monitor the progressive use of Hindi in the offices of the Department, Official

Language Implementation Committees are functioning in the headquarters as well as in all the subordinate offices.

13.21 OL Branch acquainted all the Sections of the Department of Posts(HQ), Circle Headquarters and other concerned offices of Department of Posts with the OL Act, Rules and instructions issued thereunder for their compliance for achieving the targets fixed by the Department of Official Language in their Annual Programme for the year under review.

13.22 The Quarterly Progress Reports received from all the Sections of Department of Posts(HQ), Circle Headquarters, Postal Training Centres, Postal Staff College, PLI Directorate and Business Development Directorate regarding the progressive use of Hindi was also reviewed by the OL Branch and necessary corrective measures were taken in respect of those wherein discrepancies were noticed.

13.23 The Second Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language also monitors the implementation of Official Language Policy. During the period the Committee inspected twenty Post Offices.

13.24 In pursuance of the directives laid down in the annual programme 2003-04 issued by the Department of Official Language (Ministry of Home Affairs), seventeen offices were inspected.

13.25 Hindi Diwas was observed in the Department on 15th September, 2003 and Hindi Fortnight was observed from 15th to 29th September, 2003. Prizes were distributed to the winners of various competitions held during the Hindi Fortnight. A four day Hindi Workshop was also organised during the fortnight.

Public Grievances

13.26 During the year 2003-2004, the Department handled 798,220 cases of public grievances and a total of 745,720 cases were settled during the same period. Measures to resolve grievances on priority basis continued throughout the year. Quarterly meetings of Dak Adalat and Post Forum were held.

13.27 विभाग ने अपने ग्राहकों को डाकघर में आए बिना ही अपनी वेबसाइट (डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.इंडियापोस्ट.ऑर्ग.) पर ऑन लाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान की है। शिकायतों के तीव्र निपटान के लिए इंडियापोस्ट.ऑर्ग./सीसीसी लॉगइन.एसपी पर ऑनलाइन शिकायतों पर कार्रवाई करके उसकी सूचना ग्राहकों के ई-मेल पते पर भेज दी जाती है। वीआईपी से प्राप्त होने वाली शिकायत, उसके तीव्र निपटान तथा उनको भेजे जाने वाले जवाब को विभाग इस इंडियापोस्ट.ऑर्ग./वीआईपीलॉगइन.एसपी. पर प्रोसेस करता है।

13.28 डाकघर के कर्मचारियों को सुग्राही बनाने, ग्राहकों को लेन-देन संबंधी मानदंडों से परिचित कराने तथा शिकायतों के निवारण के साथ में सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नागरिक चार्टर का क्रियान्वयन 600 से अधिक महत्वपूर्ण डाकघरों में किया गया है। मौजूदा 171 सीसीसी (ग्राहक सुविधा केन्द्र) पर इंटरनेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे शिकायतों का ऑन लाइन निपटान किया जा सके। वर्ष 2003-

04 के दौरान 886 नए सी सी सी स्थापित किए गए हैं। इन सभी को इंटरनेट के माध्यम से इंटरलैंक किया गया है। जन शिकायत का निवारण शीघ्रता से करने के लिए एक ऐसा कंप्यूटरीकृत ग्राहक सुविधा केन्द्र प्रत्येक मुख्यालय में खोला गया है।

स्थापना

13.29 वर्ष 2003-04 के दौरान श्री विजय भूषण को बतौर सचिव (डाक) पदोन्नत किया गया। दो अधिकारियों की पदोन्नति बतौर सदस्य के की गई। प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के ग्रेड में चार अधिकारी, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल/वरिष्ठ उप महानिदेशक के पद पर सात अधिकारियों को तथा भारतीय डाक सेवा के जे ए जी ग्रेड में पन्द्रह अधिकारियों को पदोन्नत किया गया। प्रवेश प्रशिक्षण सफलतापूर्वक समाप्त करने पर आई पी ओ ग्रुप 'क' के ग्यारह परीक्षार्थियों को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया। आई आर एम/ आई पी ओ के तीन सौ चौतीस अधिकारियों की पदोन्नति डी पी सी द्वारा पी एस ग्रुप 'ख' में की गई।

13.27 The Department has offered its valued customers the facility to register complaints on-line on our web site (www.indiapost.org), without visiting any Post Office. Further they also got their reply on their e-mail address. In order to settle all complaints expeditiously by processing them on-line, the Department has started handling of complaints on-line(www.indiapost.org/cccllogin.asp). In the interest of handling VIP cases on-line for their prompt settlement, the Department has started processing VIP cases on-line(www.indiapost.org/viplogin.asp).

13.28 With a view to sensitize the staff of POs, orient the customers about norms of transactions and redressal of grievances as well as obligations on their part for improving the quality of service, the Citizen's Charter has been implemented in more than 600 important Post Offices. 171 existing Customer Care Centres(CCCs) have been provided with internet connectivity to process on-line handling of complaints. 886 new CCCs were set

up during the year 2003-2004. All these are interlinked through the Internet. Each District Headquarter has at least one such computerized Customer Care Centre to ensure speedy redressal of public grievances.

Establishment

13.29 During the year 2003-04 Shri Vijay Bhushan was promoted as Secretary(Posts). Two Officers were promoted to the post of Member. Four Officers were promoted in the grade of Principal Chief Postmaster General, Seven in Chief Postmaster General/Sr. Deputy Director general, Twelve in the SAG Grade, Nine in NFSG Grade and Fifteen Officers in JAG Grade of Indian Postal Service. Eleven probationers of IPOs Group 'A' were given independent charge on them after successful completion of inductive training. Three Hundred and Thirty Four Officers of IRM/IPOs were promoted to PS Group 'B' through DPC.

अध्याय 14

पूर्वोत्तर में विकासात्मक कार्यकलाप

14.1 भारतीय डाक ने, सरकार के नीतिगत मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलापों के लिए विशेष पहल की है।

14.2 पहले पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में केवल एक डाक सर्किल द्वारा सेवा उपलब्ध कराई जाती थी। तथापि, इस क्षेत्र के सामरिक महत्व पर विचार करते हुए एवं विकासात्मक कार्यकलापों पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से तत्कालीन सर्किल को दो स्वतंत्र डाक सर्किलों में विभाजित कर दिया गया। इसमें एक असम सर्किल है जो असम राज्य के साथ कोटमिनस है तथा दूसरा पूर्वोत्तर डाक सर्किल है, जिसमें छः राज्य-अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आते हैं। हर सर्किल मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

14.3 असम डाक सर्किल में 4,008 डाकघर हैं, जिसका मुख्यालय गुवाहाटी में है। प्रत्येक डाकघर औसतन 6647 की जनसंख्या को तथा 19.56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सेवा प्रदान करता है। पूर्वोत्तर डाक सर्किल का मुख्यालय शिलांग में है और इसके अधिकार क्षेत्र में कुल 2942 डाकघर हैं। प्रत्येक डाकघर औसतन 59.89 वर्ग किलोमीटर और 4,027 की जनसंख्या को सेवा उपलब्ध कराता है।

योजना कार्यकलाप

14.4 पिछले वर्षों में शुरू किए गए विकासात्मक कार्यक्रमों को दसवीं योजना के दौरान जारी रखा गया। पिछले तीन वर्षों के दौरान समूचे देश भर में योजना कार्यकलापों पर किए गए कुल व्यय के दृष्टिगत पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया गया व्यय निम्नवत है:

तालिका-16 पूर्वोत्तर क्षेत्र में योजनागत व्यय (मिलियन रु. में)			
वार्षिक योजना	कुल योजना व्यय	पूर्वोत्तर में व्यय	कुल व्यय का प्रतिशत
2001-02	823.3	48.60	5.90%
2002-03	459.10	25.30	5.51%
2003-04	633.04	39.13	6.18%

Chapter 14

DEVELOPMENT ACTIVITIES IN NORTH EAST

14.1 India Post has taken up special initiatives for developmental activities in the North-Eastern Region, in accordance with the policy guidelines of the Government.

14.2 The North Eastern Region was previously served only by one Postal Circle. However, considering the strategic importance of the region, and to ensure focussed attention on developmental activities, the erstwhile Circle was bifurcated into two independent Postal Circles namely – Assam Circle, coterminous with the State of Assam, and the North-Eastern Postal Circle, covering the six states of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Tripura. Each Circle is under the administrative control of a Chief Postmaster General.

14.3 Assam Postal Circle, with its headquarters at Guwahati, has a network of 4,008 Post Offices. On an average, each Post Office serves a population of 6,647 persons and an area of 19.56 Sq. Kms. North-Eastern Postal Circle has its headquarters at Shillong. It has within its jurisdiction a total of 2,942 Post Offices. On an average, each Post Office serves an area and population of 59.89 Sq. Kms. and 4,027 persons respectively.

Plan Activities

14.4 The developmental programmes initiated in previous years were continued in the Tenth Plan. The expenditure in the North-Eastern region vis-a-vis the total expenditure on plan activities throughout the country during the last three years is given below: -

Table 16 PLAN EXPENDITURE IN NORTH EASTERN REGION (Rs. in Million)			
Annual Plan	Total Plan Expenditure	Expenditure in North-East	%age over total expenditure
2001-02	823.30	48.60	5.90%
2002-03	459.10	25.30	5.51%
2003-04	633.04	39.13	6.18%

14.5 योजनागत कार्यकलापों के अंतर्गत वर्ष 2003-04 के दौरान, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में इस वर्ष के दौरान फिलैटलिक प्रदर्शनियां, फिलैटलिक सेमिनार और कार्यशालाएं जैसी विभिन्न योजना गतिविधियां आयोजित की

गई थीं। पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विभिन्न डाकघरों पर फिलैटलिक ब्यूरो को उपकरण एवं उपस्कर भी प्रदान किए गए थे। 2003-2004 के दौरान कर्मचारियों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विवरण नीचे तालिका-17 में दिया गया है:-

तालिका-17					
क्र.सं.	राज्य	समह 'ग' कर्मचारियों को सेवाकालीन प्रशिक्षण	कंप्यूटर प्रशिक्षण	डाकिए के लिए प्रशिक्षण	ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर के लिए प्रशिक्षण
1.	असम	147	772	360	196
2.	अरुणाचल प्रदेश	7	10	50	20
3.	मणिपुर	11	34	-	29
4.	मेघालय	16	47	105	37
5.	मिजोरम	4	37	5	20
6.	नागालैंड	9	21	55	7
7.	त्रिपुरा	19	40	114	60

14.6 पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्यों में 2003-2004 के दौरान निम्नलिखित मुख्य विकास गतिविधियां की गई थीं।

पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पी एस एस के) खोले गए हैं। वर्ष के दौरान, रोड़ंग में एक डाकघर भवन का निर्माण किया गया। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत 46 शाखा डाकघरों को ढांचागत उपस्कर उपलब्ध करवाया गया था।

असम

14.7 असम में डाक नेटवर्क का और विस्तार किया गया तथा दो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर, एक विभागीय उप डाकघर तथा 15 पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पी एस एस के) खोले गए। चार स्पीड पोस्ट बुकिंग/वितरण कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण किया गया तथा व्यवसाय विकास को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक एंड ट्रेस स्पीड नेट के साथ दो केन्द्रों का उन्नयन किया गया। इस वर्ष के दौरान 75 शाखा डाकघरों को ढांचागत उपस्कर उपलब्ध करवाया गया।

अरुणाचल प्रदेश

14.8 राज्य में वर्ष के दौरान एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर (ईडीवीओ) और एक विभागीय उप डाकघर (डी एस ओ) तथा दस

मणिपुर

14.9 दो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर एवं 10 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलकर डाक नेटवर्क का और विस्तार किया गया। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यवसाय विकास के संवर्धन हेतु तीन स्पीड पोस्ट बुकिंग/वितरण कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण और ट्रैक एवं ट्रेस स्पीड नेट वाले दो केन्द्रों का उन्नयन किया गया। एक डाकघर का आधुनिकीकरण और इम्फाल डाकघर में एक डाकघर भवन का निर्माण पूरा किया गया जबकि चन्दल डाकघर में एक भवन का निर्माण कार्य जारी है। 20 शाखा डाकघरों को ढांचागत उपस्कर उपलब्ध करवाया गया।

मेघालय

14.10 मेघालय में वर्ष के दौरान दो अतिरिक्त विभागीय डाकघर

14.5 During this year various plan activities like Philatelic exhibitions, Philatelic seminars and workshops were organized at Arunchal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, and Sikkim during 2003-04 under the Plan Activities.

Philatelic Bureau were also provided with tools and equipment at various Post offices of North Eastern Regions. Officials were imparted training in various fields during the year 2003-04 and the details are as given in Table 17.

TABLE 17

S.No.	State	In Service Training to Group C Officials	Computer Training	Training For Post man	Training for GDSBPMs
1	Assam	147	772	360	196
2	Arunchal Pradesh	7	10	50	20
3	Manipur	11	34	-	29
4	Meghalaya	16	47	105	37
5	Mizoram	4	37	5	20
6	Nagaland	9	21	55	7
7	Tripura	19	40	114	60

14.6 The following major developmental activities were undertaken during 2003-04 in each of the States of the North Eastern Region:-

Assam

14.7 The Postal network in Assam was further expanded by opening two Extra Departmental Branch Offices, one Departmental Sub-Post Office and fifteen Panchayat Sanchar Sewa Kendras(PSSKs). Four Speed Post booking/delivery Offices were computerised and two centres were upgraded with Track and Trace Speed Net, to promote Business Development. Infrastructural equipments were provided to Seventy Five Branch Post Offices during this year.

Arunachal Pradesh

14.8 One Extra Departmental Branch Office(EDBO) and one Departmental Sub Post Office (DSO) and ten Panchayat Sanchar Sewa Kendras(PSSKs) have been opened in the State during the year. One Post Office

building was constructed at Roing during the year. Under the modernization programme Infrastructural equipments were provided to Forty Six Branch Post Offices.

Manipur

14.9 In the State of Manipur, further expansion of Postal Network was carried out by opening two EDBOs and ten Panchayat Sanchar Sewa Kendras. Under the modernisation programme, three Speed Post booking/delivery offices were computerised and two centres were upgraded with Track and Trace Speed Net, to promote Business Development. One Post Office was modernised One Post Office building was constructed and completed at Imphal Post Office while one building at Chandal Post Office is under construction. Twenty Branch Post Offices were provided Infrastructural equipments during this year.

Meghalaya

14.10 Two Extra Departmental Post Offices have

खोले गए। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, पांच शाखा डाकघरों को ढांचागत उपस्कर उपलब्ध करवाया गया। तीन स्पीड पोस्ट बुकिंग/वितरण कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण और ट्रैक एवं ट्रेस स्पीड नेट वाले तीन केन्द्रों का उन्नयन किया गया। वर्ष के दौरान दो डाकघर भवनों का निर्माण किया गया।

मिजोरम

14.11 एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर एवं 10 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोले गए। आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, 34 शाखा डाकघरों को ढांचागत उपकरण उपलब्ध करवाया गया। तीन स्पीड पोस्ट बुकिंग/वितरण कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण और ट्रैक एवं ट्रेस स्पीड नेट वाले एक केन्द्र का उन्नयन किया गया। सैतुल डाकघर के लिए डाकघर भवन का निर्माण किया गया।

नागालैंड

14.12 वर्ष के दौरान नागालैंड में दो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर एवं दस पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पी एस एस के) खोले गए।

डाक के पारेषण को सुविधाजनक बनाने हेतु वर्ष के दौरान एक स्पीड पोस्ट बुकिंग/वितरण कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण और ट्रैक एवं ट्रेस स्पीड नेट वाले एक केन्द्र का उन्नयन किया गया तथा दो मेल बैनों को खरीदा गया। पुराना बाजार में एक डाकघर भवन और दीमापुर में स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया गया।

त्रिपुरा

14.13 वर्ष के दौरान एक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर एवं नौ पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पी एस एस के) खोले गए तथा दो शाखा डाकघरों में ढांचागत उपकरण उपलब्ध करवाए गए।

सिक्किम

14.14 पांच स्पीड पोस्ट बुकिंग/वितरण कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण किया गया। दो अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर एवं एक पंचायत संचार सेवा केन्द्र (पी एस एस के) खोले गए। वर्ष के दौरान सिक्किम में दो डाकघरों का आधुनिकीकरण किया गया तथा पांच शाखा डाकघरों को ढांचागत उपस्कर उपलब्ध करवाए गए।

been opened in Meghalaya during the year. Under the modernization programme Five Branch Post Offices were provided Infrastructural equipments. Three Speed Post booking/delivery offices were computerised and three centres were upgraded with Track and Trace Speed Net, and one post office was modernised. Two Post Office buildings were constructed during the year.

Mizoram

14.11 One Extra Departmental Branch Office and ten Panchayat Sanchar Sewa Kendras were opened. Under the modernization programme, thirty four Branch Post Offices were provided Infrastructural equipments, three Speed Post booking/delivery offices were computerised and one centre was upgraded with Track and Trace Speed Net, one Post Office building was constructed for Saitual Post Office.

Nagaland

14.12 Two Extra Departmental Branch Post Offices (EDBOs) and ten Panchayat Sanchar Sewa Kendras

(PSSKs) were opened in Nagaland during the year. One Speed Post booking/delivery office was computerised and one centre was upgrded with Track and Trace Speed Net, two Mail Vans were purchased during the year to facilitate transmission of mails. One Post Office building at Purana Bazaar and Staff quarters at Dimapur have also been under construction.

Tripura

14.13 During the year One Extra Departmental Branch Office and nine Panchayat Sanchar Sewa Kendras (PSSKs) were opened and Two Branch Post Offices were provided Infrastructural equipments.

Sikkim

14.14 Five Speed Posts booking/delivery offices were computerised. Two Extra Departmental Branch Offices and one Panchayat Sanchar Sewa Kendra (PSSK) were opened. Two Post Offices were modernised at Sikkim during the year and Five Branch Post Offices were provided Infrastructural equipments.



शिमला (हिमाचल प्रदेश) में अखिल भारतीय कबड्डी टूर्नामेंट-2004-05
All India Postal Kabaddi Tournament - 2004-05 at Shimla (Himachal Pradesh).



मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) के कार्यालय में हिन्दी पखवाड़े का आयोजन।
Observing Hindi Fortnight in the office of the CPMG, Lucknow (Uttar Pradesh).



प्रधान डाकघर, अम्बाथुर (तमिलनाडु सर्किल) में 15 अक्टूबर, 2004 को डाक दिवस समारोहों में भाग लेते बच्चे।
Children attending Mail Day Celebrations on 15th October, 2004 at Head Post Office, Ambathur (Tamilnadu Circle).



इन्दौर जनरल पोस्ट आफिस (मध्य प्रदेश) में डाक-टिकट डिजाइन प्रतियोगिता का पुरस्कार समारोह।
Award Ceremony of Stamp Design Competition at Indore General Post Office (Madhya Pradesh).

भाग - II

कार्यकलाप

(अप्रैल-दिसम्बर 2004)

डाक नेटवर्क का विस्तार

1.1 वर्ष के दौरान दसवीं योजना के अंतर्गत नीति निर्देशों के अनुसार डाक नेटवर्क को युक्तिसंगत और औचित्यसम्मत बनाने हेतु प्रयत्न किए गए। तदनुसार, नीति के अनुसार अनुमोदित पहुँच को कम किए बिना मैनपॉवर एवं संसाधनों को पुनः तैनात कर डाक नेटवर्क का विस्तार किया गया। यह एक अनवरत प्रक्रिया है तथा अब तक 91 डाकघरों का विलय किया गया है तथा 34 डाकघरों को विभिन्न सर्किलों में पुनःअवस्थित किया गया है।

डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण

1.2 वर्ष के दौरान, 29 डाकघरों का, जिनका वित्तीय परिव्यय 4.3 मिलियन रुपये है, का आधुनिकीकरण किया जाना है (कार्य वातावरण में सुधार किया जाना है)। 10 प्रधान रिकार्ड कार्यालयों (एच आर ओ) का 6.5 मिलियन रुपये के वित्तीय परिव्यय से कम्प्यूटरीकरण किया जाना है।

मेल मोटर डिपुओं का कम्प्यूटरीकरण

1.3 30 मेल मोटर डिपुओं के 44 स्थलों के आधुनिकीकरण के अंतर्गत शामिल कार्यकलाप हैं : (क) ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष सॉफ्टवेयर का विकास एवं संस्थापन (ख) भंडार गृह इनवैन्टरी सॉफ्टवेयर का विकास एवं संस्थापन (ग) गैरेज उपकरणों की खरीद। पूरी परियोजना की लागत का आकलन 10 मिलियन रुपये किया गया है जिसमें 2.1 मिलियन रु. ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष सॉफ्टवेयर तथा भंडार गृह इनवैन्टरी सॉफ्टवेयर के विकास तथा संस्थापन हेतु व्यय किया गया है। ट्रैफिक नियंत्रण कक्ष के लिए सॉफ्टवेयर इन-हाउस विकसित किया गया है तथा डिपु में उसकी परीक्षा जांच चल रही है। इसे चालू वित्त वर्ष के अन्त तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। जबकि, भंडार गृह इनवैन्टरी सॉफ्टवेयर को विकसित किया जा रहा है। गैरेज उपकरण की खरीद वर्कशॉप को मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। यह कार्य 31 मार्च, 2006 से पहले करने का लक्ष्य है।

फिलैटली

1.4 डाक विभाग की 150वीं वर्षगांठ मनाने हेतु डाक विभाग ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड, 2005 में एक झांकी प्रस्तुत की।

1.5 53 स्मारक/विशेष डाक-टिकट जारी किए गए हैं। इस अवधि के दौरान विभाग ने कला एवं संस्कृति, अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, अंतर्राष्ट्रीय संबंध इत्यादि पर सुंदर डाक-टिकट जारी किए जैसे भारत-ईरान संबंधों पर दो डाक-टिकटों का सेट, आई एन एस तरंगिणी का परिनौसंचालन, ओलिम्पिक्स 2004 पर चार डाक-टिकटों का सेट, भारतीय डाक के 150 वर्ष पूरे होने पर भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्वारा चार डाक-टिकटों का सेट, अशोक चक्र पुरस्कार विजेताओं पर दो डाक-टिकटों का सेट, आगरा के किले पर दो डाक-टिकटों का सेट, ताज महल पर डाक-टिकट तथा संयुक्त राष्ट्र शान्ति सेना में भारतीय सेना के योगदान पर डाक-टिकट।

1.6 फिलैटलिक मदों का विक्रय पूरे देश में 66 फिलैटलिक ब्यूरो के 900 फिलैटलिक काउन्टरों के माध्यम से किया जाता है जिसमें देश के मुख्य डाकघर/प्रधान डाकघर सम्मिलित हैं। वर्ष 2003-04 के दौरान अर्जित फिलैटलिक राजस्व 33.19 करोड़ रुपये है। "कोई डाक-टिकट डिजाइन करें" प्रतियोगिता का आयोजन पूरे देश में सर्किल-वार 14 नवम्बर, 2004 को किया गया।

1.7 भारतीय डाक ने क्रमशः वेलन्सिया और सिंगापुर में आयोजित ऐसपाना-04 तथा विश्व डाक-टिकट चैंपियनशिप-04 में एक स्टॉल किराए पर ले कर तथा अपने प्रदर्शनों को आमंत्रित वर्ग में प्रदर्शित कर इनमें भाग लिया। भारतीय डाक ने घरेलू प्रदर्शनियों/संयुक्त फिलैटलिक प्रदर्शनियों में प्रदर्शन हेतु अपने प्रदर्श भेजकर इसमें भी भाग लिया (i) ईएफआइआरओ, बुखारेस्ट, रोमानिया (ii) बीजीग, चीन में आयोजित भारतीय फिलैटलिक प्रदर्शनी (iii) इन्डिया इवनिंग स्वीडन (iv) राष्ट्रीय कला एवं संस्कृति प्रदर्शनी डेनमार्क।

1.8 डाक सर्किलों में जिला/राज्य स्तर पर 19 क्षेत्रीय प्रदर्शनियां आयोजित की गईं।

1.9 छत्तीसगढ़ डाक सर्किल द्वारा की गई एक शुरुआत में राज्य के विभिन्न संग्रहालयों में फिलैटली सैक्शन स्थापित किए गए। ऐसे संग्रहालयों में प्रदर्शन हेतु छत्तीसगढ़ सर्किल को प्रदर्शों के 22 फ्रेम भेजे गए।

1.10 अगस्त 2004 तक "विश्व फिलैटली विकास संघ" (डब्ल्यू ए डी पी) में सचिव (डाक), भारत अध्यक्ष के पद पर आसीन रहे।

1.11 चार स्मारक डाक-टिकटों के एक सेट के अतिरिक्त भारतीय डाक ने अपने 150 वर्ष के उपलक्ष्य में क्रमशः 100/- रु. एवं 1/- रु. अंकित मूल्य के स्मारक सिक्के भी जारी किए जिन्हें 4 अक्टूबर, 2004 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा जारी किया गया।

1.12 भारत पर डाक-टिकट : श्वानों की प्रजातियां, पांडिचेरी का वास्तविक अंतरण, कृष्णकान्त, पद्मपत सिंघानिया, माधवराव सिन्धिया, रोटरी इंटरनेशनल तथा अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी वर्ष पर डाक-टिकट (नियत) जारी करना संस्वीकृत किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू)

1.13 यू पी यू की 23वीं कांग्रेस 15.09.2004 से 05.10.2004 तक बुखारेस्ट, रोमानिया में आयोजित की गई। कांग्रेस में माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयानिधि मारन के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय दल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। कांग्रेस के दौरान भारत को डाक प्रचालन परिषद के लिए पुनः चयनित किया गया। 40 सदस्यों वाले डाक प्रचालन परिषद पर, अन्य सदस्य डाक प्रशासनों के बीच महत्वपूर्ण प्रचालनात्मक, वाणिज्यिक, आर्थिक तथा अंतर्राष्ट्रीय डाक प्रचालनों के तकनीकी मुद्दों का, दायित्व होता है।

भारतीय डाक -ए मेम्बर ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस फंड बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज

1.14 27 से 28 अप्रैल, 2004 को लिस्बन, पुर्तगाल में आयोजित यू पी यू के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस फंड (क्यू एस एफ) की बैठक में सचिव (डाक) ने डाक विभाग का प्रतिनिधित्व किया। यू पी यू द्वारा स्थापित सेवा निधि की गुणवत्ता का उद्देश्य विकासशील देशों में सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई

परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए औद्योगिक देशों से विकासशील देशों में निधियां अंतरित करना है। न्यासी बोर्ड विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के नौ निर्वाचित सदस्यों से बना होता है। यह गुणवत्ता सेवा निधि (क्यू एस एफ) के कार्य की देखरेख करता है। भारत इस बोर्ड का निर्वाचित सदस्य है। इस बैठक का भारतीय डाक के लिए विशेष महत्व था क्योंकि सचिव (डाक) जुलाई, 2004 से जून 2005 तक के लिए न्यासी-बोर्ड के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। वाशिंगटन, यूएसए में 5 से 8 जुलाई, 2004 तक आयोजित हुई बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता सचिव (डाक) द्वारा की गई।

एशिया-प्रशांत डाक संघ

1.15 भारत एशिया-प्रशांत डाक संघ (एपीपीयू) के क्रियाकलापों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 29 देशों का सीमित संघ है। एपीपीयू कांग्रेस संघ का सर्वोच्च अंग है और इसकी प्रत्येक पांच वर्ष में बैठक होती है। कार्यकारी परिषद (ईसी) की सिद्धांततः वर्ष में एक बार बैठक होती है और यह दो कांग्रेसों के बीच संघ के कार्य की निरंतरता सुनिश्चित करती है। इस वर्ष एपीपीयू-कार्यकारी परिषद/शासी बोर्ड की बैठक 9-14 मई, 2004 तक क्वींसटाउन, इंग्लैंड में आयोजित की गई। सचिव (डाक) और उपमहानिदेशक (आईआर) ने बैठक में भारतीय डाक का प्रतिनिधित्व किया। एशिया प्रशांत क्षेत्र से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और मुद्दों जैसे टर्मिनल शुल्क, तकनीकी सहायता, डाक वित्तीय सेवाओं पर विचार-विमर्श किया गया।

एशिया-प्रशांत डाक सहयोग प्रबंधन बोर्ड

1.16 भारतीय डाक सात सदस्यीय एशिया-प्रशांत डाक सहयोग प्रबंधन बोर्ड (एपीपी सीएमबी) का भी सदस्य है। एपीपी सीएमबी एक ऐसी संरचना है जो एशिया प्रशांत डाक सहयोग के कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करने के लिए बनाई गई है। भारत इसके क्रियाकलापों के संचालन में बोर्ड के सदस्य की अपनी हैसियत से सक्रिय भूमिका निभा रहा है। सिंगापुर में नवम्बर, 2004 में आयोजित हुई इसकी बैठक में सहायक महानिदेशक (आईआर) ने भारतीय डाक का प्रतिनिधित्व किया। बैठक के दौरान यूपीयू के बुखारेस्ट कांग्रेस से उत्पन्न क्षेत्रीय डाक मुद्दों, एपीपी 2004-05 बिजनेस प्लान क्रियाकलापों में प्रगति और वर्ष 2004-05 के लिए आरएससीएपी (एशिया प्रशांत के लिए क्षेत्रीय सहयोग केन्द्र) क्रियाकलापों पर चर्चा की गई।

PART II

ACTIVITIES

(April - December 2004)

Expansion of Postal Network

1.1 During the year, efforts were made to rationalise and right size the postal network in consonance with the policy initiatives under the 10th Plan. Accordingly, the network was expanded by redploying manpower and resources without reducing the access approved as per policy. This is a continuing process and so far 91 Post Offices have been merged and 34 Post Offices have been relocated in various Circles.

Computerisation of Mail Offices

1.2 During the year, 29 Mail Offices with financial outlay of Rs. 4.3 million are to be modernized (improving ergonomics). 10 Head Record Offices (HROs) are to be computerised with a financial outlay of Rs. 6.5 million.

Computerisation of Mail Motor Depots

1.3 The activities covered under Modernisation of 44 locations of 30 number of Mail Motor Depots are (a) Development and installation of Traffic Control Room Software (b) Development and installation of store inventory software (c) Procurement of Garage Equipment. The cost of the entire project has been estimated as Rs. 10 Million, out of which 2.1 Million has been spent for Development and installation of Traffic Control Room Software and Store Inventory Software. The software for traffic control room has been developed in house and is on test-run in the Depots. This is expected to be completed before the end of the current financial year. While the Store inventory-software is being developed. Procurement of Garage equipment has been initiated to strengthen the workshop. These tasks are targeted to be completed before 31st March, 2006.

Philately

1.4 For the first time ever the Department of Posts presented a Tableau for the Republic Day Parade, 2005 to mark the Sesquicentennial Anniversary of India Post.

1.5 Fifty-Three(53) Commemorative/Special Postage Stamps have been issued. During the period, the Department released beautiful stamps on art and culture, international sporting event, international relations, etc., such as – set of two stamps on Indo-Iran Joint Issue, Circumnavigation of INS Tarangni, a set of four stamps on Olympics 2004, a set of four stamps on 150 Years of India Post released by His Excellency, the President of India, a set of two stamps on Ashok Chakra Awards Winners, a set of two stamps on Agra Fort, Stamp on Taj Mahal and Stamp on Role of Indian Army in UN Peace Keeping Operations.

1.6 Sale of Philatelic items is carried out all over the country through 66 Philatelic Bureaux, around 900 Philatelic Counters including all the Head Post Offices/ Mukhya Dak Ghars of the country. Philatelic revenue earned during the year 2003-04 is Rs. 33.19 Crores. The “Design a Stamp Competition, 2004” was held Circle-wise all over the country on 14th November, 2004.

1.7 India Post participated in Espana-04 and World Stamp Championship-04 held at Valencia and Singapore respectively by way of hiring a stall and exhibiting our exhibits of stamps in the invitee class. India Post also participated in (i) EFIRO, Bucharest, Romania; (ii) Indian Philatelic Exhibition in Beijing, China; (iii) India Evening, Sweden; (iv) Exhibition of National Art & Culture, Denmark by sending its exhibits for display in domestic exhibitions/joint philatelic exhibitions.

1.8 19 Exhibitions were held at District/State/ Regional Level in Postal Circles.

1.9 In an initiative taken by the Chhatisgarh Postal Circle, Philately Section was established in various Museums in the State. Exhibits of 22 Frames were sent to Chhatisgarh Circle for display in such museums.

1.10 India Post has held the prestigious post in the World Association for the Development of Philately(WADP) as Secretary Posts, India as the Chairperson up to August, 2004. India Post attended the meeting of WADP held at Berne, Switzerland and Singapore.

1.11 Apart from a set of 4 commemorative stamps, India Post also brought out commemorative coins of denominations for Rs. 100/- and Re. 1/- respectively on the occasion of 150 years of India Post, which were released on 04th October, 2004 by Hon'ble Prime Minister of India.

1.12 Postage Stamps on India : Breeds of Dogs; De Facto Transfer of Pondicherry; Krishan Kant; Padampat Singhania; Madhavrao Scindia; Rotary International and International Year of Physics (Definitive) have been approved for issue.

INTERNATIONAL RELATIONS

Universal Postal Union(UPU)

1.13 The 23rd Congress of the UPU was recently held at Bucharest, Romania from 15.09.2004 to 05.10.2004. A high level Indian delegation led by Shri Dayanidhi Maran, Hon'ble Minister of Communications & IT represented India at the Congress. During the Congress, India was re-elected to the Postal Operations Council. The 40 Member Postal Operations Council is responsible for important operational, commercial, economic and technical aspects of international postal operations among other member postal administrations.

India Post – a Member of Quality of Service Fund Board of Trustees

1.14 Secretary, Department of Posts represented India Post in the meeting of Board of Trustees of Quality of Service Fund (QSF) of the UPU held in Lisbon, Portugal from 27th to 28th April, 2004. The Quality of Service Fund established by UPU seeks to channelise

funds from the industrialized countries to the developing countries for financing projects designed to improve the quality of service in the developing Countries. The Board of Trustees, comprising nine elected members from different geographical regions, manages the work of QSF. India is an elected member of the Board. This meeting was specially important for India Post as Secretary (Posts) was elected Chairman of the Board of Trustees for the year July, 2004 – June, 2005. The meeting of the Board held in Washington, USA from 5th to 8th July, 2004 was chaired by Secretary (Posts).

Asia –Pacific Postal Union

1.15 India plays a significant role in the affairs of the Asian Pacific Postal Union (APPU), a restricted Union comprising 29 countries of the Asian and the Pacific Region. The APPU Congress is the supreme organ of the Union and meets every five years. The Executive Council(EC) meets once in a year, in principle, and ensures the continuity of the work of the Union between two Congresses. This year the APPU-Executive Council/ Governing Board meeting was held from 9th to 14th May, 2004 in Queenstown, New Zealand. Secretary (Posts) and Deputy Director General (IR) represented India Post in the meeting. Several important proposals and issues in the context of the Asian Pacific Region such as Terminal Dues, Technical Assistance, Postal Financial Services were discussed.

Asia-Pacific Post Cooperative Management Board

1.16 India Post is also a member of the seven-member Cooperative Management Board of Asia Pacific Post Cooperative (APP CMB). The APP CMB is the structure designated to supervise the activities of the Asia Pacific Post Cooperative. India has been playing an active role in its capacity as a Board Member in managing the affairs of the Cooperative. In its meeting held at Singapore in November, 2004 Assistant Director General (IR), represented India Post. During the meeting regional postal issues arising from the UPU Bucharest Congress, progress on the APP 2004-2005 Business Plan activities and RSCAP (Regional Support Centre for Asia Pacific) activities for 2004-2005 were discussed.

परियोजनाएं

1.17 डाक विभाग ने बंगलादेश, म्यांमार और नेपाल के जनरल पोस्ट ऑफिसों के डाकघर काउंटरों का कम्प्यूटरीकरण करने के लिए परियोजनाएं हाथ में ली हैं। इसके लिए यूपीयू द्वारा धनराशि उपलब्ध कराई गई। कम्प्यूटरीकरण और सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में भारतीय डाक की क्षमताओं को मान्यता देते हुए यूपीयू ये कार्य भारतीय डाक के माध्यम से करवा रहा है। ये परियोजनाएं तीन चरणों में पूरी की जाएंगी। इसका पहला चरण साइट सर्वेक्षण और प्रणाली-अध्ययन से संबंधित है। पहले चरण में भारतीय डाक के तीन प्रतिनिधिमंडलों, जिनमें से प्रत्येक में चार सदस्य थे, ने जनवरी, 2004 में म्यांमार, बंगलादेश और नेपाल का दौरा किया। द्वितीय चरण सॉफ्टवेयर संस्थापित करने और सॉफ्टवेयर प्रचालित करने के लिए इन तीनों डाक प्रशासनों के संबंधित स्टाफ को प्रशिक्षण देने से संबंधित था। दिसम्बर, 2004/जनवरी, 2005 में इनमें से प्रत्येक देश में एक प्रतिनिधिमंडल के दौरे पर जाने के साथ ही यह चरण पूरा कर लिया गया है। संस्थापना और एप्लीकेशन की समीक्षा और जांच करने से संबंधित तीसरा चरण भी फरवरी/मार्च, 2005 माह के दौरान पूरा कर लिया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में सहभागिता

1.18 श्री फैज-उर-रहमान, पोस्टमास्टर जनरल, जोधपुर को 18.7.2004 से 30.7.2004 तक काउंटर-स्वचलीकरण के क्षेत्र में कम्बोडिया डाक प्रशासन के लिए यूपीयू सलाहकार के रूप में चुना गया।

1.19 श्री टी.बी. रेड्डी, पोस्टमास्टर जनरल, मदुरै को 9.8.2004 से 13.8.2004 तक दारुस्सलाम में आयोजित डाक सेवा गुणवत्ता पर कार्यशाला के लिए यूपीयू के सलाहकार तथा 3.10.2004 से 15.10.2004 तक नासू, बहमास में पाठ्यक्रम विकसित करने वालों के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का नेतृत्व करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया।

1.20 इस अवधि के दौरान तंजानिया डाक निगम से एक चार-सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 24 अक्टूबर से 2 नवम्बर, 2004 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने भारतीय डाक द्वारा विकसित काउंटर स्वचलीकरण के सॉफ्टवेयर तथा अन्य सॉफ्टवेयर से स्वयं को परिचित कराने के लिए भारत का दौरा किया। इस दल ने न केवल काउंटर स्वचलीकरण के सॉफ्टवेयर में बल्कि मेघदूत सॉफ्टवेयर के दूसरे माड्यूल के साथ-साथ ई-पोस्ट और वीएसएटी मनीआर्डर प्रणाली में भी अत्यंत रुचि दिखायी। इस प्रतिनिधिमंडल ने दोनों

देशों के बीच आपसी सहयोग के मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए भारतीय डाक के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। हाल में, तंजानिया डाक निगम ने अपने सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करने के लिए भारतीय डाक से अनुरोध किया है।

1.21 इस अवधि के दौरान उप महानिदेशक (सीपी) और सहायक महानिदेशक (आईआर) ने 8 से 10 जून, 2004 तक बैंकाक में हुए एशिया प्रशान्त क्षेत्र के महानिदेशक और वरिष्ठ डाक प्रबंधन के सेमिनार में भाग लिया। इसका आयोजन ला पोस्ट, फ्रांस द्वारा किया गया था। सेमिनार के दौरान जिन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई थी, वे थे रेगुलेटर और ऑपरेटर की भूमिकाओं सहित डाक सुधारों के लिए मॉडल्स, विश्व सेवा दायित्व (यू एस ओ) आदि। इसके अलावा, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एण्ड सर्विसेज (जीएटीएस) से संबंधित विषयों पर भी एक सत्र चलाया गया था।

1.22 अन्य डाक प्रशासनों के साथ संबंध सुदृढ़ करने के प्रयासों के एक भाग के रूप में, सचिव (डाक) और उप महानिदेशक (आईआर) ने 8 से 11 नवंबर, 2004 तक भूटान का दौरा किया। इस दौरे का प्रयोजन भूटान में डाकघरों में ई-पोस्ट और ई-बिल सेवाओं की व्यवस्था सहित विविध विकास कार्यों के लिए भारतीय डाक द्वारा भूटान पोस्ट को दिए जाने वाले सहयोग की प्रकृति को अंतिम रूप देना भी था।

पत्र लेखन प्रतियोगिता

1.23 19वीं सार्क पत्र लेखन प्रतियोगिता 10 अक्टूबर, 2004 को आयोजित की गई। समिति ने सर्किलों से प्रथम पांच प्रविष्टियों का मूल्यांकन किया। सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय प्रविष्टि सार्क स्तर पर विचार करने के लिए पाकिस्तान पोस्ट को भेजी गई। भारत ने सभी सार्क देशों की प्रविष्टियों में पहला स्थान प्राप्त किया।

1.24 34वीं यूपीयू पत्र लेखन प्रतियोगिता 30 जनवरी, 2005 को आयोजित की गई और प्रत्येक सर्किल में सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों का मूल्यांकन करने के बाद उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा तथा सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय प्रविष्टि यूपीयू को भेजी जाएगी। यूपीयू और सार्क द्वारा आयोजित ऐसी पत्र लेखन प्रतियोगिता प्रत्येक देश के युवाओं को अपने साहित्यिक लेखन की क्षमता विकसित करने, संचार सुविधाएं प्रदान करने में डाकघर की भूमिका के प्रति अपनी जानकारी तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ाने में योगदान देने के लिए समर्थ बनाएगी।

Projects

1.17 The Department of Posts has undertaken projects for computerising post office counters at General Post Offices in Bangladesh, Myanmar and Nepal with funds being provided by the Universal Postal Union. These activities are being taken up by the UPU through India Post in recognition of its capabilities in the area of computerisation and software development. The Projects would be completed in three phases. In the first phase, which was related to site survey and system study, three delegations from India Posts comprising four members each visited Myanmar, Bangladesh and Nepal in January, 2004. The second phase, which was related to installation of software and training of the concerned staff of these three postal administrations to operate the software, has also been completed with the visits of one delegation each to these countries in Dec 2004/ January 2005. The third phase relating to review and checking of installation and application would be undertaken during the months of February/March, 2005.

Participation in International Meetings

1.18 Shri Faiz-ur-Rehman, Postmaster General, Jodhpur was chosen as an UPU consultant to Postal Administration of Cambodia in the field of counter-automation from 18.07.2004 to 30.07.2004.

1.19 Shri T.B. Reddy, Postmaster General, Madurai was also deputed as UPU consultant for a workshop on Postal Service quality held at Dar-es-Salaam, Tanzania from 09.08.2004 to 13.08.2004 and to lead a training workshop for course developers at Nassau, Bahamas from 03.10.2004 to 15.10.2004.

1.20 During the period a four-member delegation from Tanzania Posts Corporation visited India from 24th October to 2nd November, 2004. They visited India to familiarize themselves with the software of counter automation and other software developed by India Post. The team evinced keen interest in not only the counter automation software but also other modules of Meghdoot software as well as e-post and the VSAT money order system. The delegation also met the senior officers of

India Post to discuss matters of mutual cooperation between the two countries. Tanzania Posts Corporation has recently sent a request to India Post to customizing their software.

1.21 During the period Deputy Director General (CP) and Assistant Director General (IR) attended a Seminar for Director General's and Senior Postal Management in Asia Pacific Region held at Bangkok, from 8th to 10th June, 2004, which was hosted by La Poste, France. The main topics, which were discussed during the seminar, were models for postal reforms including regulator and operator roles, structure, Universal Service Obligation (USO) etc. In addition, there was a Session on issues concerning World Trade Organisation (WTO) and General Agreement on Trade and Services (GATS).

1.22 As a part of the effort to strengthen relations with other postal administrations, Secretary (Posts) and Deputy Director General (IR) visited Bhutan from 8th to 11th November, 2004. This visit was also to finalize the nature of assistance by India Posts to Bhutan Post for various development activities including provision of e-post and e-bill services for Post Offices in Bhutan.

Letter Writing Competition

1.23 19th SAARC Letter Writing Competition was held on 10th October, 2004. Committee evaluated the first five entries from the circles. Best national entry was forwarded to Pakistan Post for consideration at the SAARC Level. India, has won the first place among entries from all SAARC countries.

1.24 34th UPU Letter Writing Competition was held on 30th January, 2005 and after evaluation the best entries in each circle will be awarded prizes and the best national entry will be forwarded to UPU. Such Letter Writing Competition conducted by UPU and SAARC enable the youth of every country to develop their capacity for literary composition, improve their awareness of the role of Post Office in providing communication facilities and contribute to fostering international relations.

प्रौद्योगिकी

1.25 अपने ग्राहकों को बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय डाक 839 प्रधान डाकघरों, 1448 उप डाकघरों का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण करेगा। इसके अतिरिक्त, 53 सर्किलों और क्षेत्रीय प्रशासनिक कार्यालयों तथा 19 निदेशक लेखा (डाक) के कार्यालयों के कार्यों का भी पर्याप्त कम्प्यूटरीकरण किया जायेगा। इस समय 150 वीएसएटी स्टेशन तथा 1327 एक्सटेंडेड सेटेलाइट मनीआर्डर स्टेशन काम कर रहे हैं तथा मार्च 2005 के अंत तक औसतन हर रोज लगभग 85,000 मनीआर्डर पारेषित किये जाने की संभावना है। समूचे भारत में ग्राहकों को अब ई-पोस्ट सेवा उपलब्ध है। इसी प्रकार, मांग होने पर समूचे देश में सेवा प्रदाताओं को ई-बिल-पोस्ट सेवा भी प्रदान की जा सकती है। बेहतर डाक सेवा प्रदान करने के लिए कार्यकुशलता में सुधार करके 150 डाकघरों को आधुनिक बनाने का लक्ष्य रखा गया है तथा 580 डाकघरों को नये यांत्रिक उपस्कर सप्लाई किये जायेंगे।

व्यवसाय विकास निदेशालय परम्परागत उत्पादों का विपणन

1.26 व्यवसाय विकास निदेशालय को परम्परागत डाक उत्पादों के विपणन का काम सौंपा गया है जो अब तक व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा है। विपणन के पर्याप्त प्रयास करने के लिए ग्राहकों की आवश्यकताओं के संदर्भ में उत्पादों की विशेषताएं और उनका वर्गीकरण सर्किलों को सूचित किया गया है। परम्परागत उत्पादों में राजस्व वृद्धि के लिए डाकघर व लक्ष्य निर्धारित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इससे कुछ सर्किलों में परम्परागत उत्पादों में राजस्व विकास में वृद्धि हुई है।

एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट दरों में परिवर्तन

1.27 एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट (ईपीपी) की व्यवहार्यता को बनाये रखते हुए इस सेवा के समेकन की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 25.10.2004 से इसकी दरों में परिवर्तन किया गया है। दिसम्बर, 2004 तक ईपीपी से अर्जित राजस्व में पर्याप्त वृद्धि हुई है।

स्पीड पोस्ट केन्द्रों/ स्पीड पोस्ट बुकिंग तथा वितरण डाकघरों को उपस्कर की सप्लाई

1.28 अप्रैल, 2004 से दिसम्बर, 2004 तक, 18 राज्य स्पीड पोस्ट केन्द्रों को, जिनका राष्ट्रीय केन्द्रों के रूप में उन्नयन किया गया है, ट्रैक एंड ट्रेस प्रयोजनों के लिए कम्प्यूटर और सहायक उपस्कर सप्लाई किये गये हैं। इसके अलावा 70 स्पीड पोस्ट केन्द्रों को ट्रैक एंड ट्रेस सुविधाओं का

उन्नयन करने के लिए अतिरिक्त नोड दिये गये हैं। 410 डाकघरों को, जो स्पीड पोस्ट वस्तुएं बुक करते हैं और स्पीड पोस्ट वस्तुएं वितरित करते हैं उन्हें ट्रैक एंड ट्रेस प्रयोजनों के अलावा स्पीड पोस्ट बुकिंग और वितरण के लिए कम्प्यूटर तथा सहायक उपकरण दिये गये हैं।

प्रचार एवं संवर्धन

1.29 व्यवसाय विकास निदेशालय, डाक विभाग भारतीय डाक के साथ उसके 150 वर्ष मनाने के लिए उसके प्रचार से घनिष्ठ रूप से जुड़ा रहा। इसके अलावा भारतीय डाक के प्रीमियम उत्पादों के संवर्धन के लिए आकाशवाणी और एफएम चैनलों पर जिगल्स और स्पॉट के साथ प्रिंट मीडिया में विज्ञापन भी जारी किये गये। यह प्रक्रिया मुख्यालय के साथ-साथ सर्किल स्तरों पर व्यवस्थित ढंग से शुरू की गई।

पार्सल डिवीजन

1.30 भारत में पार्सल डिवीजन की भारतीय डाक के लिए एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है। व्यवसाय विकास निदेशालय में एक पार्सल डिवीजन स्थापित करने का प्रस्ताव है। इससे सभी पार्सल उत्पादों का केन्द्रीय प्रबंधन सुनिश्चित हो सकेगा।

ई-पोस्ट

1.31 30 जनवरी, 2004 से पूरे देश में शुरू की गई ई-पोस्ट सेवाओं का विस्तार सॉफ्टवेयर संशोधनों के जरिए बढ़ाने का प्रस्ताव है। इससे दोनों प्रयोक्ताओं, जैसे कारपोरेट्स पूरे देश में डाकघरों के माध्यम से अपने संदेशों को डिजिटल रूप में तथा पूरे विश्व में ई-मेल पत्तों पर भेज सकेंगे।

लॉजिस्टिक्स पोस्ट

1.32 अगस्त, 2004 में एक नई सेवा "लॉजिस्टिक्स पोस्ट" अधिसूचित की गई जो मार्च, 2005 तक चालू होगी। इस सेवा के अंतर्गत प्राप्तकर्ताओं को वितरण के लिए वस्तुएं बुक की जा सकेंगी जिसके लिए कोई अधिकतम भार सीमा नहीं होगी। लॉजिस्टिक्स पोस्ट वस्तुओं पर वही न्यूनतम प्रभार लिया जायेगा जो 50 कि.ग्राम भार की वस्तुओं के सामान के लिए लिया जाता है। ग्राहकों के नये वर्ग को बेहतर सेवा प्रदान करते हुए, इस क्षेत्र में अत्यधिक व्यावसायिक संभावनाओं को टैप करने के लिए भारतीय डाक के विस्तृत बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जायेगा।

Technology

1.25 India Post will computerize 839 Head Post Offices, 1448 Sub Post Offices fully by end-March, 2005 to provide improved quality of services to its customers. In addition, substantial computerization of works will also take place in 53 Circle & Regional Administrative Offices & 19 offices of the Director of Accounts (Postal). 150 VSAT stations & 1327 Extended Satellite Money Order Stations are in operation now and by end March, 2005 about 85,000 money orders are expected to be transmitted on an average daily. e-Post service is now available to customers throughout India. Similarly, e-Bill Post Service can also be provided to service providers throughout the country on demand. 150 Post Offices have been targeted to be modernized by improving ergonomics & 580 Post Offices will be supplied new mechanical equipment to provide better postal service.

BUSINESS DEVELOPMENT DIRECTORATE

Marketing of Traditional Products

1.26 Business Development Directorate was entrusted with the marketing of traditional postal products which was hitherto not being done in a systematic manner. Products features and their placement with respect to customer needs has been informed to Circles for sustained marketing efforts. To increase revenue growth in traditional products, practice of setting Post Office-wise targets has been commenced. It has resulted in an increase in revenue growth in traditional products in some Circles.

Revision of Express Parcel Post Rates

1.27 The Express Parcel Post(EPP) rates have been revised effective from 25.10.2004 keeping with the need for consolidation of the service while retaining its viability. Revenue earned from EPP has increased considerably till December, 2004.

Supply of equipment to Speed Post Centres/ Speed Post Booking and Delivery Post Offices

1.28 From April, 2004 to December, 2004, 18 State Speed Post Centres which were upgraded as National Centres have been supplied computers and peripheral

equipment for Track and Trace purposes. In addition, 70 Speed Post Centres have been given additional nodes to upgrade Track and Trace facilities. 410 Post Offices, which book Speed Post articles and deliver Speed Post articles have been given computers and peripherals for Speed Post Booking and Delivery purposes besides for Track and Trace purposes.

Publicity and Promotion

1.29 Business Development Directorate, Department of Post was intimately involved in the publicity connected with India Post celebrating its Sesquicentennial Year. In addition, advertisements have been released in the print media along with jingles and spots on AIR and FM Channels to promote the premium products of India Post. This exercise has been undertaken systematically at both the Headquarters as well as Circle levels.

Parcel Division

1.30 Parcel Division in India was identified as a core area for attention of India Post. A Parcel Division is proposed to be set up in the Business Development Directorate. This will ensure a focused management of the full range of parcel products.

e-Post

1.31 The scope of e-Post services launched nationwide from 30th January, 2004 is proposed to be enhanced through software modifications. These will enable both users, like corporates, to digitally convey their messages through the Post Offices across the country or to e-mail addresses worldwide.

Logistics Post

1.32 A new service 'Logistics Post' was notified in August, 2004, which will be operationalised by March, 2005. Under the service, articles may be booked for delivery to addressee for which there will not be any maximum weight limit. The minimum charges on Logistics Post articles shall be the same as charged for a consignment of articles of weight of 50 Kgs. The vast infrastructure of India Post will be utilized to tap the huge business potential in this field, while offering a quality service to a new segment of customers.

डायरेक्ट पोस्ट

1.33 विभाग का राजस्व बढ़ाने के अपने प्रयासों में व्यवसाय विकास निदेशालय इस वित्तीय वर्ष के अंत तक अनएड्रेस्ड मेल का वितरण करने के लिए डायरेक्ट पोस्ट नामक एक नई सेवा शुरू करेगा। इस सेवा का सामाजिक और वाणिज्यिक दोनों प्रयोजनों के लिए, सूचना के प्रचार-प्रसार हेतु सरकारी और निजी क्षेत्र द्वारा व्यापक रूप से प्रयोग किये जाने की आशा है।

आंतरिक कार्य-अध्ययन

1.34 एसटीटी, जीडीएस और लागत एवं दर अनुभागों की रिपोर्टें जारी की जा चुकी हैं। डीए, सीएफ, पीजी, आई आर, पीओ तथा डी (मेल्स) अनुभागों का कार्य-अध्ययन किया जा रहा है। एबीसी संदेश अध्ययन पूरा हो चुका है। बचत बैंक लोकल एरिया नेटवर्क (एसबी लैन), मेघदूत लैन, कम्प्यूटरीकृत रजिस्ट्रेशन केन्द्र (सीआरसी), वीएसएटी के लिए मानक बनाने का कार्य-अध्ययन, डाकियों के लिए संशोधित मानक विचाराधीन है। डाकघरों के जरिए ओआईसी प्राइवेट लिमिटेड के गैर-जीवन बीमा उत्पादों की बिक्री से संबंधित कार्यकलापों के लिए अध्ययन कार्य मार्च 2005 तक पूरा हो जाने की आशा है। एसबीआई-जी कैपिटल के लिए स्पीड पोस्ट वस्तुओं के प्रोसेसिंग के लिए अध्ययन कार्य पूरा हो गया है और रिपोर्ट वित्तीय सहमति के लिए प्रस्तुत की गई है। अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2005-06 में एचआरओ और ग्राहक सुविधा केन्द्र के लिए मानक बनाने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति

1.35 कर्नाटक, केरल तथा पंजाब सर्किल के कार्यालयों से संबंधित

सभी आरक्षण रोस्टरों की जांच की गई तथा निरीक्षण के दौरान उसमें पाई गई कमियों/चूक का निपटान कर दिया गया है। डाक विभाग में सेवारत अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.जातियों के कर्मचारियों के संबंध में सूचना कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग तथा राष्ट्रीय आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को भेज दी गई है। इन सभी सर्किलों में शिकायत रजिस्ट्रारों की भी जांच की गई तथा इसमें कोई शिकायत नहीं पाई गई। पश्चिम बंगाल सर्किल का आरक्षण रोस्टर फरवरी 2005 में तैयार करने का प्रस्ताव है।

वित्तीय सेवाएं

1.36 वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करने तथा निवेश एवं लाभ के नए अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 2 अगस्त 2004 से "वरिष्ठ नागरिक बचत स्कीम-2004" के नाम से एक नई लघु बचत योजना आरंभ की है। इस स्कीम में जमाकर्ताओं को 9% की दर से विशेष ब्याज दर प्रदान की जाती है तथा इसे डाकघरों के माध्यम से चलाया जाता है। विभाग ने, सितम्बर 2004 में यूटीआई ऐसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के साथ, जो कि देश में म्युचुअल फंड मार्केट के सबसे बड़े प्रचालक हैं, करार किया है जिसमें चुने हुए डाकघरों से प्रायोगिक आधार पर पांच म्युचुअल स्कीमों की रिटेलिंग की जाएगी।

1.37 सैकेण्ड्री मार्केट में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्था के साथ करार की प्रक्रिया जारी है।

डाक जीवन बीमा

1.38 वर्ष 2004-05 में व्यवसाय के लक्ष्य तथा अप्रैल से दिसम्बर 2004 तक हासिल व्यवसाय के ब्योरे नीचे दिए गए हैं :-

तालिका -18			
डाक जीवन बीमा/ग्रामीण डाक जीवन बीमा व्यवसाय 2004-05			
श्रेणी	लक्ष्य (मिलियन रु. में)	उपलब्धि (दिसम्बर 2004 तक)	
		पालिसियों की संख्या	बीमा राशि (मिलियन रु. में)
डाक जीवन बीमा	47850	219,091	24,005.4
ग्रामीण डाक जीवन बीमा	133,000	431,888	27,805.0

Direct Post

1.33 Business Development Directorate in its endeavour to increase revenue of the Department will be launching a new service called Direct Post for delivery of unaddressed mail by the end of this financial year. This service is likely to be extensively used by Government and the private sector for dissemination of information for both social and commercial purposes.

inspected and the shortcomings/lapses noted during the inspection have been settled. The information in respect of SC/ST/OBC employees in service in respect of Department of Posts have been supplied to the Department of Personnel and Training and National Commission of SCs/STs. The grievances registers in all these Circles were checked and no complaint was found. Reservation Rosters of West Bengal Circle is being proposed in the month of February, 2005.

Financial Services

Internal Work Study

1.34 The reports of the STT, GDS and Costing & Rates Sections have been issued. Work Study of DA, CF, PG, IR, PO and D(Mails) Sections are being conducted. ABC Message Study has been completed. Work Study of Evolution norms for Savings Bank Local Area Network (SB LAN), Meghdoot LAN, Computerised Registration Centre(CRC), VSAT, revised norms for Postman Staff are under consideration. Work-Study for activities relating to sale of non-life insurance products of OIC Pvt. Ltd. through Post Offices is likely to be completed by March, 2005. Study for processing of Speed Post Articles for SBI-GE Capital has been completed and the report has been submitted for financial concurrence. It is proposed to evolve norms for HRO and Customer Care Centre in the next financial year i.e. 2005-06.

1.36 With a view to provide relief and a new avenue of investment & return to Senior Citizens, the Government of India introduced a new small savings scheme, "The Senior Citizens Savings Scheme-2004" w.e.f. 2nd August, 2004. The scheme provides for special rate of interest of 9% for depositors and is vended through post offices. The Department has also tied-up in September, 2004 with the UTI Asset Management Co. Ltd., which is the largest player in the Mutual Fund market in the country to retail five Mutual Fund Schemes on a pilot basis from selected post offices.

1.37 Sale of Government Securities in the secondary market in a tie-up with a leading financial institution is under process.

Scheduled Castes & Scheduled Tribes

Postal Life Insurance

1.35 All the reservation rosters in respect of the Karnataka, Kerala and Punjab Circle Offices were

1.38 The Business targets for the year 2004-2005 and business secured from April to December, 2004 is detailed below: -

Table 18
PLI/RPLI BUSINESS : 2004-2005

Category	Target (Rs. in million)	Achievement (Up to December, 2004)	
		No. of Policies	Sum Assured (Rs. in million)
PLI	47,850	219,091	24,005.4
RPLI	133,000	431,888	27805.0

1.39 व्यवसाय के प्रभावी प्रापण के उद्देश्य से सहायक अधीक्षक डाकघर/अधीक्षक (डाक) तथा पोस्टमैनों को कार्यालय समय के बाद तथा रविवार/अवकाश के दिनों में भी प्रोत्साहन आधार पर व्यवसाय प्रापण के लिए प्राधिकृत किया गया है।

1.40 उत्तरी क्षेत्र की बैठक लखनऊ में 1 जुलाई, 2004 को आयोजित की गई, जिसमें संबंधित मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, निदेशक तथा उप मंडल प्रबंधकों ने भाग लिया।

स्टाफ संबंध

1.41 अवधि के दौरान विभाग ने कर्मचारियों की फेडरेशनों तथा यूनियनों/संघों के साथ सदभावपूर्ण तथा सार्थक संबंध बनाए रखने के लिए सभी प्रयास किए। सचिव (डाक) ने डाक कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ (एनएफपीई), राष्ट्रीय डाक संगठन परिसंघ (एफएनपीओ) तथा भारतीय डाक कर्मचारी परिसंघ के साथ बैठकें कीं। माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के साथ भी डाक कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ की एक बैठक 17 नवम्बर, 2004 को आयोजित की गई जिसमें डाक कर्मचारियों की समस्याओं पर विचार किया गया।

1.42 पोस्टल स्टाफ कालेज, भारत में 19 व 20 अक्टूबर, 2004 को यूनियन संबंधी मामलों पर एक सेमिनार आयोजित किया गया। डाक विभाग के सभी तीनों परिसंघों से संबद्ध यूनियनों के यूनियन नेताओं ने सेमिनार में भाग लिया।

1.43 विभागीय परिषद (जेसीएम) की पहली आम बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में यूनियन के लीडरों ने डाक प्रशिक्षण केन्द्र, मैसूर का दौरा किया तथा केन्द्र में प्रदत्त प्रशिक्षण कार्यक्रम पर संतुष्टि दर्शायी। फरवरी 2005 में परिसंघों/एसोसिएशन के लीडरों के लिए "भारतीय डाक की पहुंच" पर डाक सेमिनार आयोजित किया गया।

स्टाफ कल्याण

1.44 लेखा-परीक्षित लेखाओं के प्राप्त होने पर किए जाने वाले अंतिम आबंटन अभी लंबित हैं। फिर भी, निधियों के दत्तमत अनुदान पर निम्नलिखित आबंटन किए गए :-

(i) सर्किल कल्याण बोर्ड को 8.92 मिलियन रु.

(ii) सर्किल खेल बोर्ड को 3.80 मिलियन रु.

(iii) असम, बिहार, हरियाणा, तथा उत्तर पूर्व राज्यों में बाढ़ से पीड़ित कर्मचारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के तौर पर विभाग को (लगभग) 20 मिलियन रु. की मांग प्राप्त हुई। परन्तु अभी तक केवल 1.61 मिलियन रु. आबंटित किए गए तथा शेष लंबित प्रस्तावों का निपटान शीघ्र किया जाएगा।

अवकाश गृह

1.45 कर्मचारियों तथा उनके परिवार के लाभार्थ देश के विभिन्न भागों में 29 अवकाश गृह हैं। विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश), दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल) तथा जामनगर (गुजरात) में तीन और अवकाश गृह खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

ड्यूटी के दौरान डकैतों, आतंकवादियों तथा दंगों आदि के कारण विभागीय कर्मचारी की मृत्यु के मामले में केन्द्रीय कल्याण निधि से वित्तीय सहायता

1.46 1 अप्रैल 2004 से 31 दिसम्बर, 2004 की अवधि के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें मृतक कर्मचारी के परिवार को केन्द्रीय कल्याण निधि से भुगतान के लिए 43,000/- रु. संस्वीकृत किए गए। इसके अलावा, मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, सर्किल कल्याण निधि से 7000/-रु. की राशि संस्वीकृत की गई।

1.47 अनुकंपा आधार पर वित्तीय सहायता के अनुदान पर निर्णय लेने के लिए सदस्य (विकास) की अध्यक्षता में गठित समिति ने बीमार एवं जरूरतमंद कर्मचारियों के तीन प्रस्ताव पारित किए।

खेल

1.48 1 अप्रैल से 31 दिसम्बर, 2004 की अवधि के दौरान टेबिल टेनिस, हॉकी, कबड्डी, वालीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स तथा साइक्लिंग, चैस एवं कैरम में अखिल भारतीय डाक खेल टूर्नामेंट आयोजित किए गए। सचिव (डाक) की अध्यक्षता में बेंगलूर में अक्टूबर, 2004 में 17वीं डाक खेल बोर्ड बैठक आयोजित की गई। दिल्ली सर्किल के दो कर्मचारियों ने दिसम्बर, 2004 में क्लीवलैंड, यूएसए में आयोजित वर्ड बैच प्रेस पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में भाग लिया।

1.39 To mobilise procurement of business effectively, the Assistant Superintendent of Post Office/Inspector (Post) and Postmen have been authorised to procure Postal Life Insurance policies during their off duty hours and on Sundays/holidays on incentive basis.

1.40 The Northern Zone Meeting was held at Lucknow on 1st July, 2004, which was attended by concerned CPMsG, Directors and Deputy Divisional Managers.

Staff Relations

1.41 During the period, the Department endeavoured to maintain harmonious and meaningful relations with the Federations and Unions/Associations of its employees. The Secretary (Posts) took the meetings with National Federation of Postal Employees (NFPE), Federation of National Postal Organisations (FNPO) and with Bhartiya Postal Employees Federation. A meeting of National Federation of Postal Employees was also held with the Hon'ble Minister of Communications & IT on 17th November, 2004 to discuss the grievances of the Postal employees.

1.42 A seminar on Union matters was organized in the Postal Staff College, India on 19th and 20th October, 2004. The union leaders from the Unions affiliated to all the three Federations in the Department of Posts attended the seminar.

1.43 As a follow up of decision taken in the first ordinary meeting of the Departmental Council (JCM), the union leaders visited Postal Training Centre, Mysore and expressed satisfaction on the training programme imparted in the Centre. A seminar on 'VISIBILITY OF INDIA POST' for Federation/Associations leaders is scheduled to be held in February, 2005.

Staff Welfare

1.44 Pending final allocations to be made on receipt of the audited accounts, the following allocations were made out of the Vote on Account grant of funds :

- (i) Rs.8.92 million to the Circle Welfare Board.
- (ii) Rs. 3.80 million to the Circle Sports Board.

- (iii) Due to heavy floods in the States of Assam, Bihar, Haryana and North East the Department received demands amounting to Rs. 20 million (approx.) to be given as financial assistance to the flood affected employees. However, so far an amount of Rs. 1.61 million allocated and the remaining pending proposals are likely to be disposed of shortly.

Holiday Homes

1.45 29 Holiday Homes are functional at various places of the country for the benefit of the employees and their families. The proposal for opening of three more holiday homes viz. Visakapatnam (Andhra Pradesh), Darjeeling (West Bengal) and Jamnagar (Gujarat) is under consideration.

Financial assistance from Central Welfare Fund in cases of Departmental official's death due to attack by robbers, terrorists and riots etc. while on duty.

1.46 During the period from 1st April, 2004 to 31st December, 2004 one such case occurred in which Rs.43,000/- has been sanctioned for payment to the family of the deceased official from Central Welfare Fund besides Rs.7,000/- sanctioned from Circle Welfare Fund, as per existing instructions.

1.47 Committee headed by Member (D) constituted for deciding grant of financial assistance on compassionate grounds cleared three proposals for the ailing and needed officials.

Sports

1.48 During the period from 1st April to 31st December, 2004, All India Postal Sports Tournaments in Table-Tennis, Hockey, Kabaddi, Volleyball, Badminton, Athletics & Cycling, Chess & Carrom were organised. 17th Postal Sports Board Meeting was organised in Oct. 2004 at Bangalore under the Chairmanship of Secretary (P). Two officials of Delhi Circle participated in the World Bench Press Powerlifting Tournament held at Cleveland, U.S.A in December, 2004.

1.49 भारतीय डाक टीम के फरवरी 2005 में नवीं मुंबई में आयोजित होने वाली XXXIV सीनियर राष्ट्रीय एवं अंतर-राज्य कैरम चैम्पियनशिप में भाग लेने की संभावना है और 66वीं सीनियर और अंतर-राज्य टेबल टेनिस चैम्पियनशिप जनवरी 2005 में पनवेल, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में आयोजित की गई।

मानव संसाधन विकास पोस्टल स्टाफ कालेज

1.50 पुनरीक्षावधि के दौरान पोस्टल स्टाफ कालेज द्वारा 8 प्रवेश प्रशिक्षण तथा 12 सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें 380 अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान 81 अधिकारियों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षण दिया गया। अनुमान है कि 01.01.2005 से 31.01.2005 तक 50 अधिकारियों को प्रवेश प्रशिक्षण तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा। दिसम्बर 2004 तक एशियाई प्रशांत पोस्टल कालेज में भारतीय डाक सेवा के छह अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

विदेशी प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण

1.51 19 देशों के 23 विदेशी प्रतिभागियों के लिए विदेश मंत्रालय के आईटीईसी/एससीएपी के अंतर्गत डाक सेवाओं में सूचना प्रौद्योगिकी पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्र

1.52 छः प्रशिक्षण केन्द्रों में दिसम्बर 2004 तक कुल 6,955 कर्मचारियों को सेवाकालीन तथा प्रवेश प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 3,380 और कर्मचारियों को भी प्रवेश एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

कार्यस्थल पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण सुविधा

1.53 दिसम्बर 2004 तक छः क्षेत्रीय डाक प्रशिक्षण केन्द्रों पर लगभग 20,000 कर्मचारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण दिया गया। अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग और 15,000 कर्मचारियों को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा।

स्थापना

1.54 श्री आर. गणेशन को 01.12.2004 को सचिव (डाक) के तौर पर प्रोन्नत किया गया। श्री जी.मोहन कुमार को सदस्य,

डाक सेवा बोर्ड के ग्रेड में पदोन्नत किया गया। दो अधिकारियों को प्रधान मुख्य पोस्टमास्टर जनरल के ग्रेड में पदोन्नत किया गया। एक अधिकारी को अपर महानिदेशक, सेना डाक सेवा के तौर पर प्रोन्नत किया गया। दो अधिकारियों को उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी) में प्रोन्नत किया गया। 54 अधिकारियों को डाक सेवा ग्रुप "ख" से कनिष्ठ समयमान (जेटीएस) ग्रेड में प्रोन्नत किया गया है। 46 आईपीओ लाइन/जनरल लाइन कर्मचारियों को डाक सेवा ग्रुप "ख" में प्रोन्नत किया गया। 20 निजी सचिवों को वरिष्ठ निजी सचिव ग्रेड में प्रोन्नत किया गया।

राजभाषा

1.55 निदेशालय के कर्मचारियों को हिन्दी के सॉफ्टवेयर का प्रयोग करने का प्रशिक्षण देने के लिए जून, 2004 में दो दिन की तकनीकी कार्यशाला का आयोजन किया गया।

1.56 समीक्षाधीन अवधि के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप-समिति ने 3 कार्यालयों का निरीक्षण किया। वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप-समिति ने दो कार्यालयों के अध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श किया।

1.57 राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2004-05 में निर्धारित निदेशों के अनुसरण में, विभाग के अधिकारियों ने वर्ष के दौरान 17 कार्यालयों का निरीक्षण किया।

1.58 उपर्युक्त के अलावा, समीक्षाधीन अवधि के दौरान हिन्दी का सरकारी कामकाज में उपयोग करने के संबंध में विभाग के 18 अनुभागों का भी निरीक्षण किया गया।

1.59 विभाग में 14 सितम्बर, 2004 को हिन्दी दिवस का आयोजन किया गया तथा 14 से 28 सितम्बर, 2004 तक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया। हिन्दी पखवाड़े के दौरान आयोजित की गई विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए। पखवाड़े के दौरान एक दो-दिवसीय हिन्दी कार्यशाला का भी आयोजन किया गया।

सामग्री प्रबंधन

1.60 डाक विभाग के 150 वर्ष के उपलक्ष्य में डाक विभाग की फील्ड यूनिटों में डाकियों और समूह "घ" कर्मचारियों को दी जानी वाली वर्दी के रंग में परिवर्तन करने के लिए आदेश जारी किए गए। नई वर्दी 01 अक्टूबर, 2004 से प्रभावी हुई।

1.49 India Post Team is likely to participate in XXXIV Senior National & Inter-State Carrom Championship to be held at New Mumbai in February, 2005 and 66th Senior National & Inter-State Table Tennis Championships was held at Panvel, District Raiga, Maharashtra in January, 2005.

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

Postal Staff College

1.50 During the period under review, the Postal Staff College conducted 8 Induction and 12 In-service training programmes, in which 380 officers participated. Besides, 81 officers were imparted training in computers during the period. It is anticipated that 50 officers would be imparted induction and in-service training from 01.01.2005 to 31.03.2005. Six Indian Postal Service Officers were trained at Asian Pacific Postal College upto December, 2004

Training for Foreign Participants

1.51 A training programme on Information Technology in Postal Services under ITEC/SCAAP of Ministry of External Affairs was organised for 23 foreign participants from 19 countries.

Regional Postal Training Centres

1.52 A total number of 6,955 officials were imparted in-service and induction training by the six Regional Training Centers up to December, 2004. It is anticipated that an additional number of 3,380 officials would also be imparted induction and in-service training during the current financial year.

Work Place Computer Training Facilities

1.53 By December, 2004, a total number of about 20,000 officials were imparted training on computers at the six Regional Postal Training Centres. It is anticipated that an additional number of about 15,000 officials would be imparted training during the current financial year.

Establishment

1.54 Shri R. Ganesan was promoted as Secretary (Posts) on 01.12.2004. Shri G. Mohanakumar was

promoted to the grade of Member, Postal Services Board. Two officers were promoted to the grade of Principal Chief Postmaster General. One Officer was promoted as Addl. Director General, Army Postal Service. Two officers were promoted to HAG Grade. 54 Officers have been promoted to JTS Grade from PS Group B. 46 IPO line/General line officials were promoted to PS Group B. 20 Private Secretaries were promoted to Sr. Private Secretary Grade.

Official Language

1.55 A two-day technical workshop was also organised for the officials of the Directorate in June 2004 to impart the training of the usages of Hindi software.

1.56 During the period under review, the second Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language carried out inspections in 3 offices. The Drafting and Evidence Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language held discussions with the heads of two offices during the year.

1.57 In pursuance of the directives laid down in the Annual Programme 2004-05 issued by the Department of Official Language (Ministry of Home Affairs), the officers of the Department inspected 17 offices during the year.

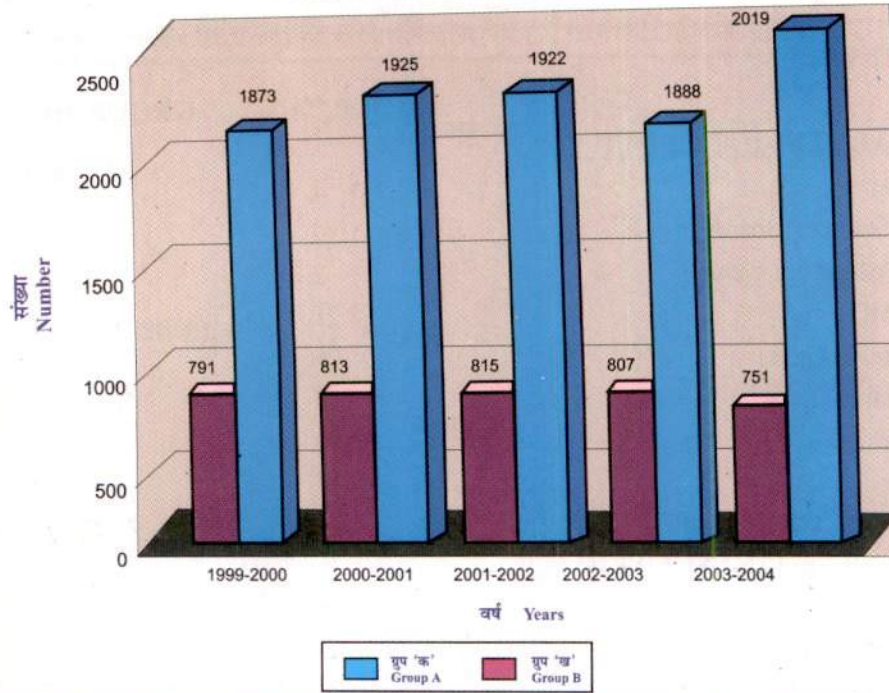
1.58 Apart from the above, 18 sections of the Department have also been inspected in connection with the official use of Hindi during the period under review.

1.59 Hindi Diwas was observed in the Department on 14th September, 2004 and Hindi Fortnight was observed from 14th to 28th September, 2004. Prizes were distributed to the winners of various competitions held during the Hindi Fortnight. A two-day Hindi workshop was also organised during the fortnight.

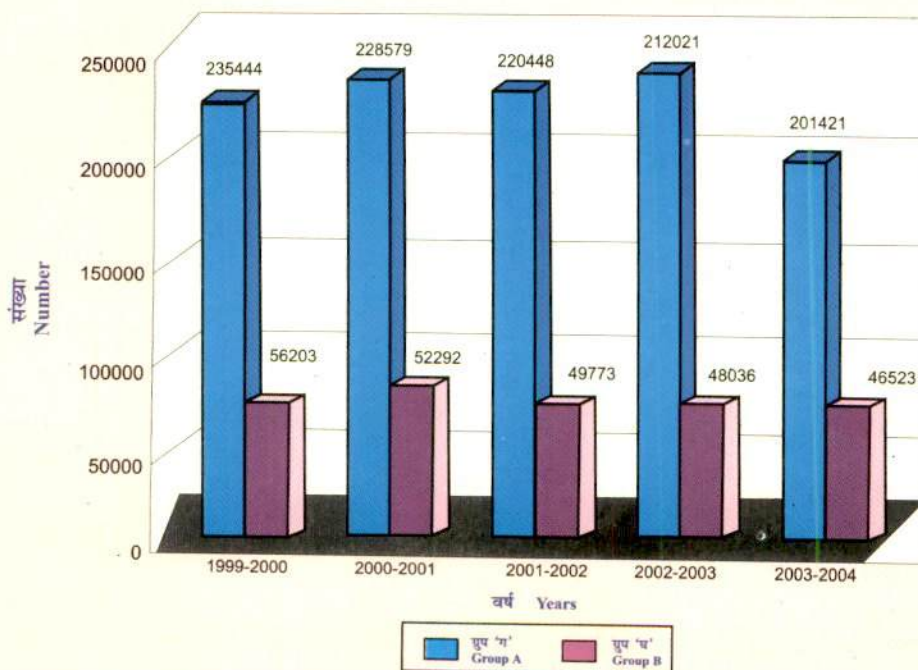
Material Management

1.60 To commemorate the Sesquicentennial Year of the Department of Posts, orders have been issued to change the colour of uniform supplied to Postmen and group 'D' officials in the field units of the Department of Post. The new uniform came into effect w.e.f 1st October 2004.

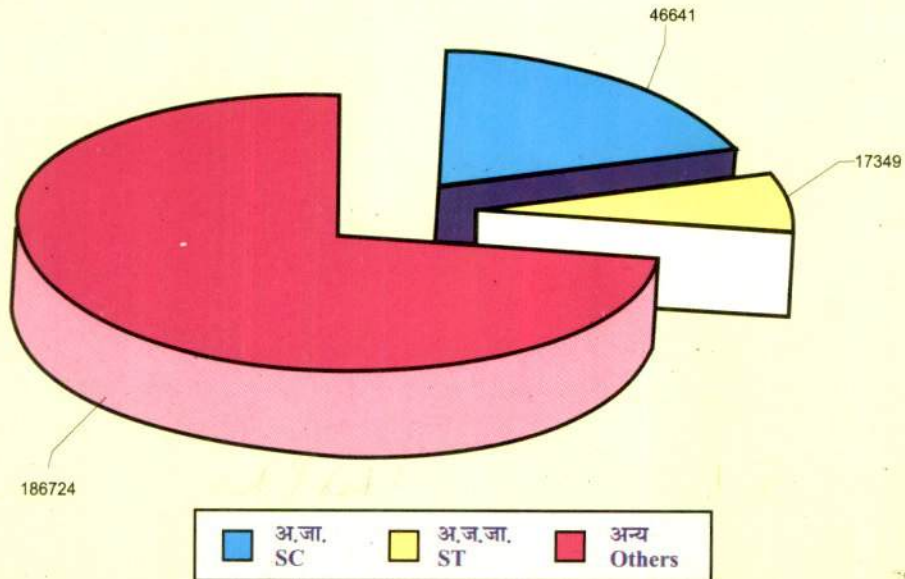
राजपत्रित अधिकारी GAZETTED STAFF



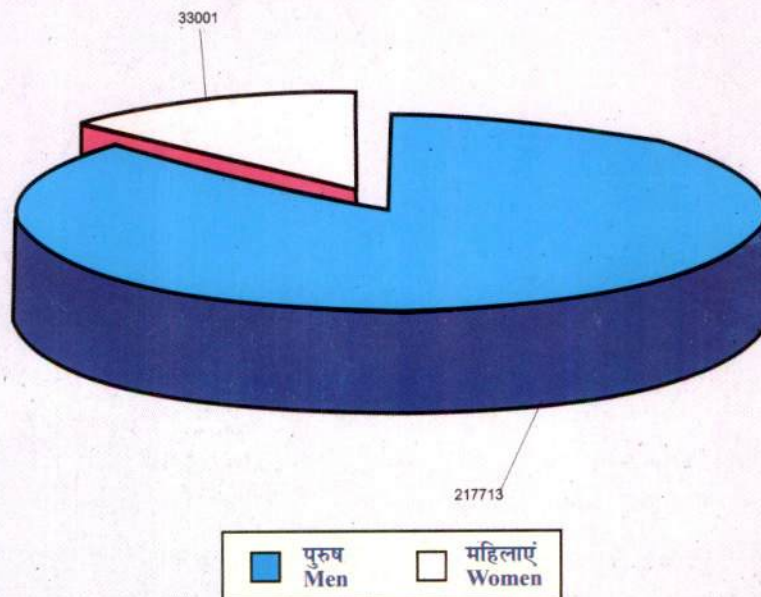
अराजपत्रित कर्मचारी NON-GAZETTED STAFF



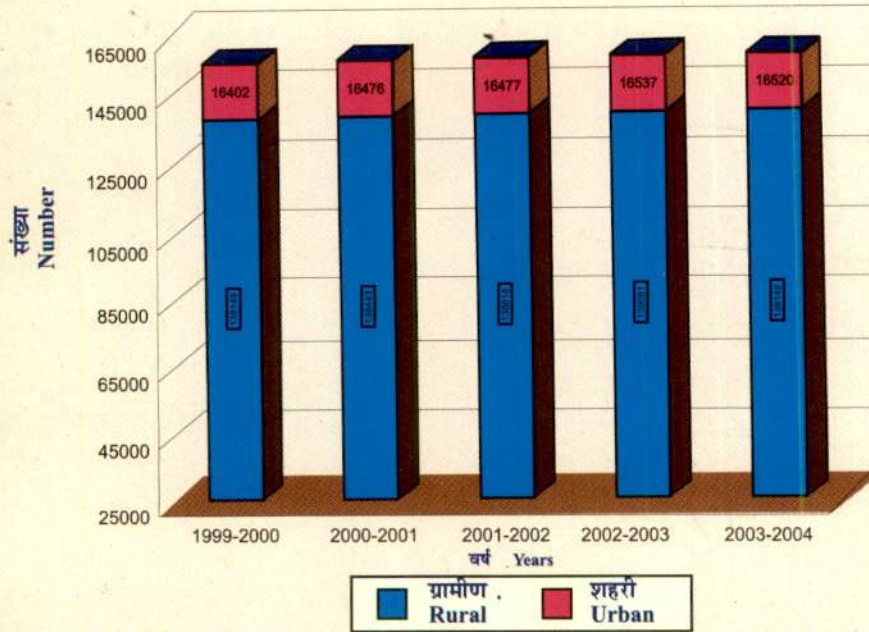
31.3.2004 की स्थिति के अनुसार अ.जा./अ.ज.जा. कर्मचारी (विभागीय)
SC/ST EMPLOYEES AS ON 31.03.2004 (DEPARTMENTAL)



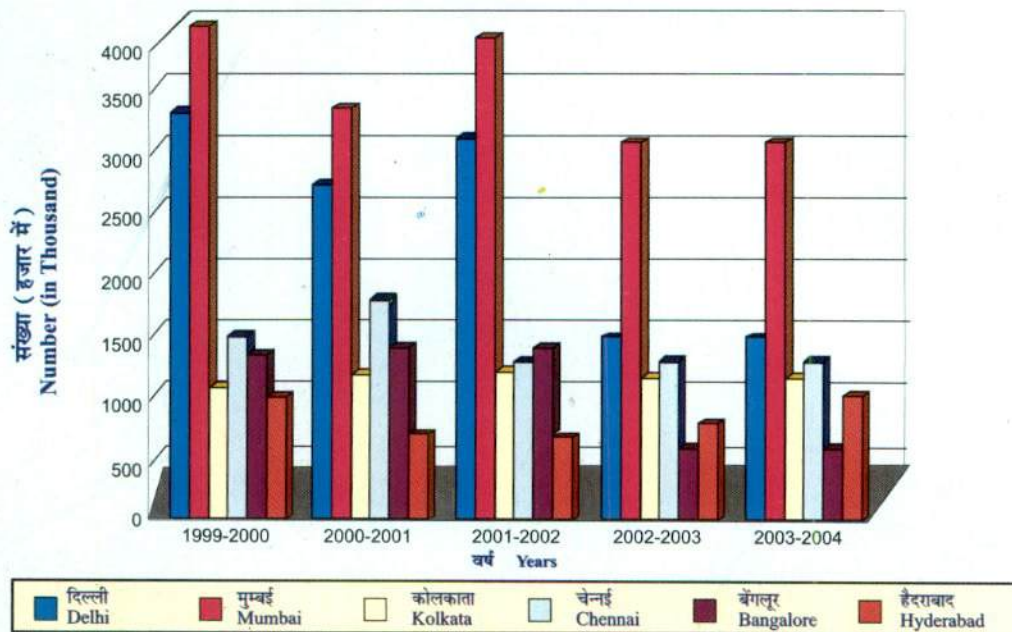
31.3.2004 की स्थिति के अनुसार महिला कर्मचारी (विभागीय)
WOMEN EMPLOYEES AS ON 31.03.2004 (DEPARTMENTAL)



डाकघरों की संख्या NUMBER OF POST OFFICES



प्रतिदिन निपटाई गई महानगरीय डाक METRO MAIL HANDLED PER DAY





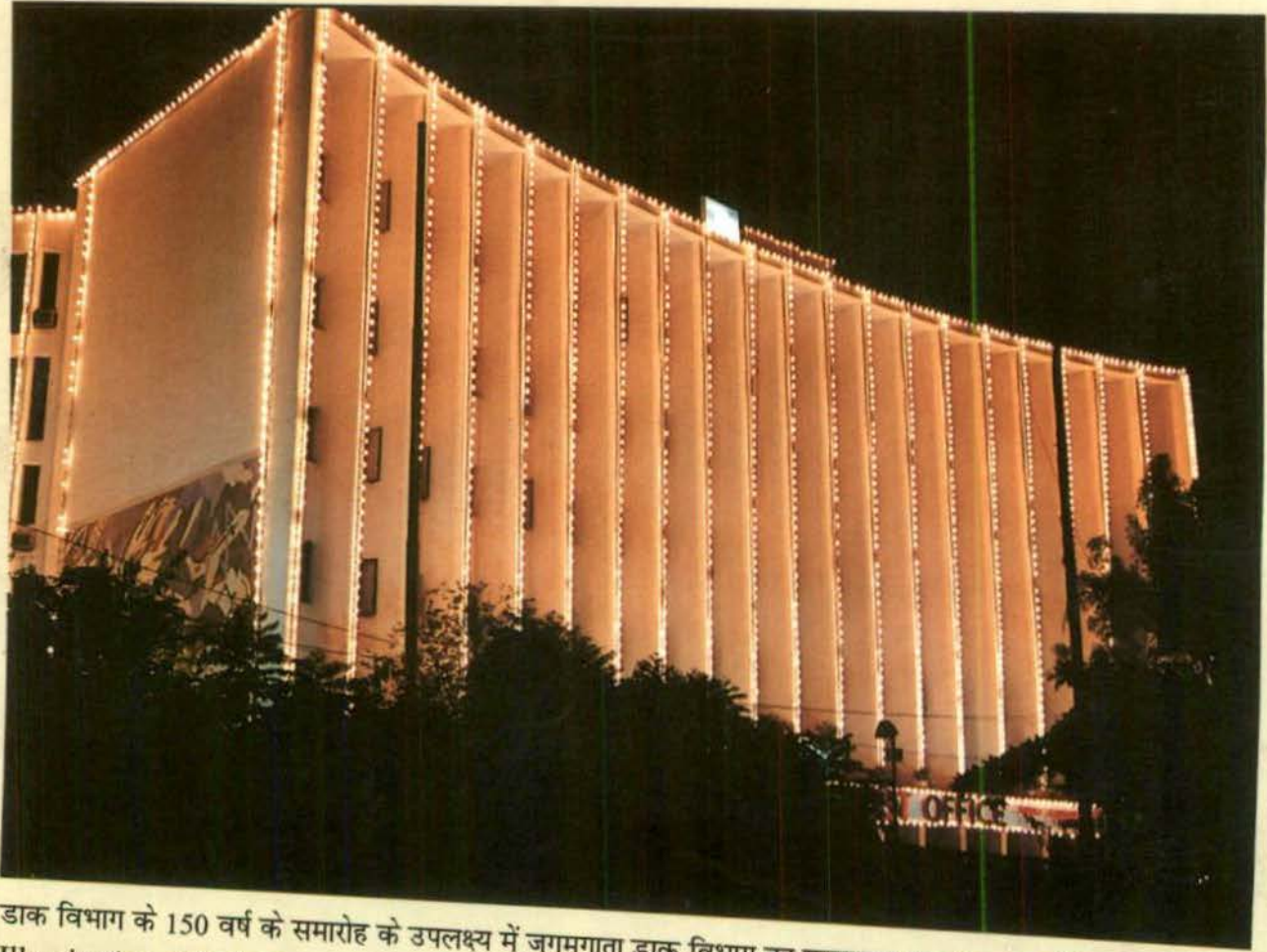
माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री दयानिधि मारन और श्रीमती वत्सला रघु, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, तमिलनाडु सर्किल चेन्नई जनरल पोस्ट आफिस भवन के जीर्णोद्धार के लिए आधार शिला रखने के समारोह में।

Hon'ble Minister of Communications & IT Shri Dayanidhi Maran and Smt. Vatsala Raghu, CPMG, Tamilnadu Circle, at the foundation stone laying ceremony for the restoration of Chennai General Post Office building.



गणतंत्र दिवस परेड, 2005 में राजपथ, नई दिल्ली में भाग लेती डाक विभाग की झांकी।

Tableau of Department of Posts participating in the Republic Day Parade, 2005 at Rajpath, New Delhi.



डाक विभाग के 150 वर्ष के समारोह के उपलक्ष्य में जगमगाता डाक विभाग का मुख्यालय डाक भवन, नई दिल्ली।
Illumination of Dak Bhavan, New Delhi, the headquarters of Department of Posts in celebration of
150 Years of the Department of Posts.



भारतीय डाक विभाग
Department of Posts, India
Website: www.indiapost.org